• अब मप्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कंपनी • उपचुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

www.akshnews.com

अब निशाने पर क्षेत्रीय दल

वर्ष 18, अंक-23 | 1 से 15 सितंबर 2020 | पृष्ठ-48 | मूल्य 25 रूपये

बेदम दावे कमजोर दांव

R.N.I. NO.HIN/2002/8718 M.P. BPL/642/2018-20

समय पर जांच, उपचार एवं सावधानियां

आपको डेंगू एवं चिकुनगुनिया से बचा सकते हैं...

डेंगू एवं चिकुनगुनिया का वाहक एडीज मच्छर रुके हुए साफ पानी में पैदा होता है और दिन के समय काटता है। पूरी बांह के कपड़े पहनें तथा पानी को जमा न होने दें। इससे बचने के लिए घरों के आस-पास सफाई रखें, सभी कंटेनर जिनमें पानी भरा हो एवं कूलर के पानी सप्ताह में एक बार खाली कर, सुखा कर, उनमें नया पानी भरें। आप दिन में भी सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें।

डेंगू के लक्षण

तेज बुखार, आँखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों और सिर में तेज दर्द, मसूड़ों व नाक से खून बहना और शरीर पर लाल चकत्ते होना, डेंगू हो सकता है।

चिकुनगुनिया के लक्षण

तेज बुखार, सिर दर्द, जोड़ों में असामान्य दर्द और शरीर पर लाल चकत्ते आना आदि चिकुनगुनिया के प्रमुख लक्षण हैं।

उपचार

यह लक्षण पाए जाने पर शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क खून की जांच कराएं, जांच में डेंगू या चिकुनगुनिया पाए जाने पर डॉक्टर की सलाह के अनुसार पूरा उपचार लें।

डेंगू एवं चिकुनगुनिया से बचाव

- पानी के बर्तन ढंककर रखें।
- अनुपयोगी सामग्रियों जैसे कूलर, ड्रम, टंकी, बाल्टी आदि में पानी जमा न होने दें, दोबारा उपयोग से पूर्व उन्हें अच्छी तरह सुखाएं।
- हैण्डपम्प के आस-पास भी पानी इकट्ठा न होने दें। जमा पानी पर मिट्टी का तेल या इंजन का जला हुआ तेल डालें।
- आस-पास सफाई रखें, सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें, पूरी बांह के कपड़े पहनें। पानी में मच्छर नहीं पनपने दें।

मास्क पहनें,
धोते रहें हाथ,
रहें दो गज़ दूर,
कोरोना से
बचेंगे जरूर।

हमारा पानी हमारी जवाबदारी

राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जनहित में जारी
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

D-16049/20

इस अंक में

राजकाज

9 | उपचुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन

लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र आयोजित होने जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 21 से 23 सितंबर के बीच बुलाया गया है। राजभवन की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद विधानसभा...

राजपथ

10-11 | उपेक्षा का दंश

देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस दिन पर दिन अपना वजूद खोती जा रही है। इसकी वजह यह है कि पार्टी में युवा नेतृत्व को हमेशा हाशिए पर रखा जाता रहा है। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि पार्टी में हमेशा से...

मिसाल

14-15 | इंदौर का चौका

मप्र वाकई अजब है, गजब है। देश का हृदय प्रदेश होने के नाते इस प्रदेश का अपना ही महत्व है। इस बात को यहां का शासन-प्रशासन और जनता भी अच्छी तरह जानती है। यही कारण है कि कई मामलों में मप्र देश के लिए मिसाल बनकर सामने आता है।

उपलब्धि

17 | डिंडौरी ने दिखाया दम

कोरोना संक्रमणकाल में मनरेगा प्रवासी श्रमिकों के लिए वरदान साबित हुआ है। प्रदेश में गत वर्षों की अपेक्षा इन पांच माह में रिकार्ड काम हुआ है और लोगों को काम मिला है। इस दौरान लगभग सभी जिलों में मनरेगा के तहत खूब काम हुए हैं। लेकिन प्रदेश का डिंडौरी जिला ऐसा रहा है...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

मप्र में 27 सीटों पर होने वाला उपचुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, बल्कि यह चुनाव सत्ता का भविष्य तय करेगा। चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा भले ही नहीं की है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने मोर्चा संभाल लिया है। खासकर भाजपा और कांग्रेस जीत के बड़े-बड़े दावे कर रही हैं। लेकिन फिलहाल उनके दावों में दम नहीं है। क्योंकि कोरोना संक्रमण के कारण मतदाता अभी तक अपने भावों को प्रकट नहीं कर पाया है। इसलिए पार्टियों के दांव कमजोर साबित हो रहे हैं।

राजनीति

30-31 | अब निशाने पर क्षेत्रीय दल

कांग्रेस मुक्त भारत अभियान के साथ ही भाजपा क्षेत्रीय दलों के सफाए पर भी काम कर रही है। भाजपा के निशाने पर कई क्षेत्रीय पार्टियां और उसके नेता हैं। लेकिन नीतीश कुमार के पास ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी उनका साथ छोड़ नहीं रही? कई राजनीतिक रणनीतिकार...

महाराष्ट्र

35 | बंगला नंबर-2

पिछले हफ्ते शरद पवार के पोते पार्थ पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख द्वारा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग के लिए सार्वजनिक रूप से फटकार खाने के बाद, उनके मुंबई आवास पर उनसे मिलने गए। टेलीविजन कैमरों और पत्रकारों का एक...

बिहार

38 | नीतीश की सेंधमारी

सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच का रास्ता खोलकर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से मुद्दा झटक लिया है, फिर एक के बाद एक लगातार झटके देते जा रहे हैं। चंद्रिका राय को जेडीयू में लाकर नीतीश कुमार ने लालू यादव को जो झटका दिया है...

6-7 अंदर की बात
39 पड़ोस
41 विदेश
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

मायाजाल में सुशांत की आत्महत्या या हत्या

किसी शायर ने कहा है...

जरूरी नहीं कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए।
लहजा बदल के बोलने से भी बहोत कुछ टूट जाता है।।

कुछ ऐसा ही हो रहा है अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में। अभिनेता ने आत्महत्या की या उनकी हत्या हुई है, इसको लेकर राजनीतिक रोटियां सिकने लगी हैं। कोई इसे आत्महत्या बता रहा है तो कोई हत्या। आरोप-प्रत्यारोप का दौर राजनीतिक रूप लेने लगा है। मायानगरी में हुई यह घटना अब मायावी हो गई है। जिसकी मर्जी में जो आता है, वही बयां कर देता है। आलम यह है कि राज्यों की पुलिस भी पैंतरेबाजी में जुट गई है। हालांकि अब इस मामले में सीबीआई जांच शुरू हो गई है। जबसे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच सीबीआई ने शुरू की है, इसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आने शुरू हो गए हैं। इसी पूछताछ और जांच में यह खुलासा हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत मादक पदार्थ यानी ड्रग्स लेते थे। यह भी संदेह जताया जाने लगा है कि सुशांत की मौत मादक पदार्थ लेने से हुई हो। पर यह स्पष्ट है कि मुंबई में मादक पदार्थों का कारोबार करने वालों का तंत्र सक्रिय है। जबसे सुशांत मामले में मादक पदार्थ का कोण सामने आया है, महाराष्ट्र के विपक्षी नेताओं को सरकार पर हमला बोलने का भी मौका मिल गया है कि महाराष्ट्र सरकार कैसे मादक पदार्थों की बिक्री रोकने में नाकाम रही है। सुशांत की मौत अब भी रहस्य के परदों में है, पर फिल्मी परदे की दुनिया का सच इसके जरिए एक-एक कर सामने आ रहा है। इसमें की गई साजिशें, काम देने के मामले में भाई-भतीजावाद, शोहरत के शिखर पर पहुंचने के लिए की जाने वाली तिकड़मों आदि की परतें उघड़ रही हैं। यानी फिल्मी दुनिया का अंदरूनी पक्ष उतना उजला नहीं है, जितना परदे पर दिखाई देता है। जिस तरह सुशांत मामले में फिल्मी दुनिया के बहुत सारे लोगों ने मौन साधे रखा उससे भी उनकी निष्ठा, प्रतिबद्धता और मानवीयता पर सवाल उठ रहे हैं। अच्छी बात है कि सीबीआई जांच में सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला जल्दी सुलझता दिख रहा है। पर इसमें फिल्मी दुनिया के भीतर की जो कुछ सच्चाईयां उजागर होंगी, वह शायद फिल्म प्रेमियों के मन पर अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ेंगी। अफसोस की बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद से अब तक इस मामले में बॉलीवुड से लेकर राजनीति की दुनिया में जितने ध्रुव खड़े हो गए और उनके बीच जिस तरह के आरोप-प्रत्यारोप सामने आए, वे मामले की हकीकत को सामने लाने में मददगार नहीं थे। बल्कि ऐसे में आरोप और संदेह की नई परतें बन गईं, जिससे लोगों को अपनी सुविधा के मुताबिक धारणाएं बनाने का मौका मिला। यहां तक कि इस मामले को कुछ राजनीतिकों ने अपनी सुविधा का मुद्दा बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्या सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को इंसाफ इस रास्ते दिलाया जा सकेगा? बॉलीवुड में जिस तरह वंशवाद या परिवारवाद का बोलबाला रहा है, उसमें नए कलाकारों को अपनी जगह बनाने के लिए किस तरह के संघर्षों से गुजरना पड़ता है, यह छिपा नहीं है। प्रतिद्वंद्विता, खींचतान और नाकामी से लेकर चकाचौंध के बीच अकेले पड़ जाने और अवसाद से घिर जाने के हालात भी उन कलाकारों के लिए बड़ी चुनौती होती है। इसके अलावा, किसी की मौत में साजिश और रहस्य की क्या भूमिका है, यह बिना बारीक जांच के सामने आना संभव नहीं है। इसलिए बेहतर है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कोई पूर्वधारणा बनाने के बजाय अब सीबीआई की जांच के नतीजों और फिर इससे जुड़े मुकदमे में अदालत के फैसले का इंतजार किया जाए।

-राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 18, अंक 23, पृष्ठ-48, 1 से 15 सितंबर, 2020

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2018-20

ब्यूरो
मुंबई :- ऋतेन्द्र माथुर, **कोलकाता:**- इंद्रकुमार, **जयपुर:**- आर.के. बिन्नानी, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
094259 85070, (मंदसौर) धर्मवीर रत्नावत
098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी-
फोन : 011 25495021, 011 25494676
मुंबई : बी-1, 41 शिव पावर्ती चेम्बर प्लाट नंबर 106-110 सेक्टर-21 नेरूल, नवी मुंबई-400706 मो.-093211 54411
कोलकाता : 70/2 हजरा रोड कोलकाता
फोन-033 24763787, मोबाइल: 09331 033446
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)
फोन- 0141 2295805, मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : 39 श्रुत्रि सिलटर निपानिया, इंदौर
मोबाइल - 094251 25096

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

बसपा बिगाड़ेगी गणित

मप्र में होने वाले उपचुनाव में शिवराज सरकार का भविष्य तय होगा। इस बार भाजपा और कांग्रेस के अलावा बसपा भी अधिक सक्रिय है। 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बसपा भी अपने पूरे उम्मीदवार खड़े करने की बात कह रही है। जिससे भाजपा-कांग्रेस का गणित बिगड़ सकता है।

● **रमेश धाकड़,** राजगढ़ (म.प्र.)

मजबूत हो कांग्रेस

सिंधिया व कई बागी विधायकों के भाजपा में चले जाने के बाद कांग्रेस के संगठन को नए स्तर से तैयार करने की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के ऊपर है। पार्टी संगठन में बूथ लेवल पर कुछ कमियां थीं। कांग्रेस को अगर प्रदेश में बने रहना है तो उसे अपने आप को मजबूत करना होगा।

● **चंदन सोनी,** भोपाल (म.प्र.)

लोगों की जीत

स्वच्छता सर्वेक्षण लीग-2020 मध्यप्रदेश का इंदौर शहर स्वच्छता के मामले में एक बार फिर नंबर-1 बन गया। लगातार चौथी बार इंदौर स्वच्छता में नंबर-1 बना है। यह जीत यहां के लोगों की जीत है, जो साफ-सफाई को अभियान के रूप में न लेकर आंदोलन की तरह ले रहे हैं।

● **राजेश्वरी साहू,** इंदौर (म.प्र.)

मनरेगा ही श्रमिकों का सहारा

देशव्यापी लॉकडाउन के बाद आर्थिक गतिविधियां थमने के कारण बड़ी संख्या में श्रमिकों ने पलायन किया है। ये श्रमिक शहरों से गांवों में पहुंचे। जब बेरोजगार होकर गांव पहुंचे श्रमिकों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया। तब मप्र सरकार ने मनरेगा को माध्यम बनाया और लोगों को उनके गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराना शुरू किया। सरकार का यह कदम हजारों श्रमिकों और उनके परिवार के लिए रोजी-रोटी का माध्यम बन गया है। गांवों में लोगों को रोजगार मुहैया कराने के साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग कोविड-19 को लेकर जनजागरण अभियान भी चला रहा है। मनरेगा में कार्यरत श्रमिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए होम-मेड मास्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

● **विकास तिवारी,** गुना (म.प्र.)

आत्मनिर्भर होगा मप्र

मप्र अब आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के तहत देशी चिकित्सा पद्धति, आयुष, आदिवासी चिकित्सा पद्धति, योग आदि को बढ़ावा दिया जाएगा, जो कि सरकार की ओर से प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अच्छी पहल है। वहीं प्रदेश सरकार की हमारी शिक्षा, संस्कार और रोजगार देने वाली होगी, जो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होगी। इसमें पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र का भी विकास किया जाएगा।

● **नितेश सिसोदिया,** सीहोर (म.प्र.)

उम्मीद की नई किरण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत दिनों स्वतंत्रता दिवस पर जो भाषण दिया, वह ना सिर्फ हमारी देश की वर्तमान स्थिति को बतलाता है बल्कि भविष्य में हम किस दिशा की ओर बढ़ेंगे इसकी भी रूपरेखा तय करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के मन में विश्वास जगाया है कि आने वाला समय समस्याओं पर विजय का होगा। जनता भी प्रधानमंत्री के इस विश्वास में एक नए कल को देख रही है। जनता के मन में उम्मीद की नई किरण उदय हो रही है।

● **प्रताप सिंह,** नई दिल्ली

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

कौन जीता, कौन हारा

राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का झगड़ा फिलहाल रुक गया है। लेकिन प्रदेश की राजनीति में अब यह सवाल उठने लगा है कि इस राजनीतिक द्वंद में किसकी जीत हुई है और किसकी हार। ज्यादातर इस पूरे विवाद में गहलोत का पलड़ा भारी बता रहे हैं। ऐसों का तर्क है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत न केवल अपनी सरकार बचा पाने में सफल रहे वरन् अपने धोर प्रतिद्वंदी सचिन पायलट से उन्होंने उपमुख्यमंत्री पद और प्रदेश कांग्रेस की कमान भी छीन ली। इतना ही नहीं पायलट की कांग्रेस के निष्ठा को भी ध्वस्त करने में वे सफल रहे। लेकिन बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक सचिन पायलट की वापसी को गहलोत की न केवल हार बल्कि उनका भविष्य भी इस घरवापसी के चलते अंधकारमय करार दे रहे हैं। लेकिन सूत्र बताते हैं कि आलाकमान पायलट को कमजोर नहीं होने देना चाहता है। ऐसे में खबर है कि पायलट के एक विश्वस्त को उपमुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा और स्वयं सचिन को केंद्रीय संगठन में महामंत्री का पद दिया जाएगा। ऐसे में हाल-फिलहाल यह तय कर पाना कठिन है कि कौन जीता, हारा कौन। लेकिन अगर ऊपरी तौर पर देखा जाए तो यह बात तो साफ नजर आ रही है कि पायलट अब न सत्ता में रह पाए हैं और न ही संगठन में।

सियासी दल का ब्राह्मण मोह

उत्तर प्रदेश में हर सियासी दल का ब्राह्मण मोह उमड़ पड़ा है। कांग्रेस कुछ ज्यादा ही लालायित है। तभी तो पार्टी के नेता जितिन प्रसाद ने अपने सारे विधायकों को खुली सलाह दे डाली कि वे ब्राह्मणों के उत्पीड़न का खुलकर विरोध करें। सूबे में ब्राह्मण आबादी कितनी है, इसका कोई अधिकृत आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है। ब्राह्मण संगठनों के दावों को देखें तो बारह से पंद्रह फीसदी तक ब्राह्मण हैं। हालांकि हकीकत में तो इसके आधे ही होंगे। उपाध्याय, स्वामी, पांचाल, बढ़ई, अचारज और महापंडित जैसी जातियां ओबीसी में ठहरी। पर सियासी मोलतोल के वक्त उन्हें भी शामिल कर लेते हैं ब्राह्मण। हां, रोटी-बेटी के नाते की बात हो तो नाक-भौं सिकोड़ते हैं। कभी कांग्रेस का वोट बैंक थे ब्राह्मण। मंदिर आंदोलन ने भगवा पार्टी की तरफ मोड़ दिया। फिर 2007 में मायावती ने ज्यादा ब्राह्मणों को टिकट दिए तो वे भूल गए कि ठाकुर, बामन, बनिया चोर का नारा इसी पार्टी का था। उल्टे खुद नारा लगाने लगे कि हाथी नहीं, गणेश है, ब्रह्मा, विष्णु महेश है। हाथी दिल्ली जाएगा, ब्राह्मण शंख बजाएगा। मायावती को 2007 में बहुमत मिला तो श्रेय दलित-ब्राह्मण भाईचारे को मिला। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लखनऊ पहुंचे तो उन्होंने भी दलितों-ब्राह्मणों से ही सरोकार जताया। बसपा तो अब भाजपा पर खुलेआम ब्राह्मणों की अनदेखी का आरोप लगा रही है। किसी भी प्रमुख राज्य में भाजपा ने ब्राह्मण को मुख्यमंत्री नहीं बना रखा।

एटार्नी जनरल के बगावती तेवर

प्रशांत भूषण अवमानना प्रकरण में बगैर एटार्नी जनरल से सलाह-मशविरा किए सारी कार्यवाही को अंजाम दिया है। प्रशांत भूषण के वकील दुष्यंत दवे ने सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता केके वेणुगोपाल से राय लिए जाने पर जोर दिया लेकिन सुप्रीम कोर्ट राजी नहीं हुई। सूत्रों का दावा है कि वेणुगोपाल इससे खासे आहत और नाराज हैं। इतने नाराज कि उन्होंने इस प्रकरण पर अपनी निजी राय प्रशांत भूषण के पक्ष में सार्वजनिक कर दी। इसके ठीक बाद उन्होंने एक वकील अनुज सक्सेना द्वारा स्वरा भास्कर पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाते हुए मुकदमा चलाने की इजाजत पर एक्शन ले लिया। केके वेणुगोपाल ने उनकी अर्जी को नामंजूर कर दिया है। दरअसल, अवमानना कानून के अनुच्छेद-15 में स्पष्ट प्रावधान है कि अवमानना का मुकदमा चलाए जाने के लिए एटार्नी जनरल या फिर सॉलिस्टर जनरल की सहमति जरूरी है। प्रशांत भूषण प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया है। अनुज सक्सेना अब अपनी अर्जी सॉलिस्टर जनरल के यहां लगाने का मन बना चुके हैं। इस बीच चर्चा जोरों पर है कि केंद्र सरकार वेणुगोपाल के रुख से खासी नाराज है। बहुत संभव है कि वेणुगोपाल के स्थान पर किसी अन्य को महाधिवक्ता बना दिया जाए।

दाल में काला

रंजन गोगोई के पिता असम की कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री रहे थे। पर खुद न्यायमूर्ति गोगोई कई बार कह चुके हैं कि वे न तो राजनीतिक हैं और न उनकी ऐसी कोई महत्वकांक्षा है। राज्यसभा के एक नामित सदस्य और किसी पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से चुने गए राज्यसभा सदस्य के बीच अंतर होता है। गोगोई को यह सफाई इस बार असम के पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के एक बयान के कारण देनी पड़ी है। तरुण गोगोई ने कहा था कि न्यायमूर्ति रंजन गोगोई अगले चुनाव में भाजपा के असम के संभावित मुख्यमंत्री उम्मीदवार हो सकते हैं। फिलहाल सर्बानंद सोनोवाल असम की भाजपा सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। भाजपा की तरफ से असम के उपाध्यक्ष विजय गुप्ता तरुण गोगोई के बयान को निराधार बता चुके हैं। पर असम भाजपा के भीतर सोनोवाल को लेकर खुसर-पुसर तो जरूर है अन्यथा पार्टी के ही एक सांसद और एक मंत्री क्यों कहते हैं कि हिमंत बिस्वा सरमा में मुख्यमंत्री पद की सारी योग्यताएं हैं।

रिश्तों का घालमेल

कांग्रेस आलाकमान ने उत्तराखंड में पार्टी की अंदरूनी कलह रोकने के मकसद से हरीश रावत को राष्ट्रीय महासचिव और असम का प्रभारी बनाया था। लेकिन सूबे की सियासत से उनका मोह फिर भी नहीं छूटा। सूबेदार प्रीतम सिंह और विधायक दल की नेता इंदिरा हृदेश दुखी हों तो रहें। सुर्खियों में रहने के हथकंडे हरीश रावत को आते हैं। तभी तो सूबे के एक स्थानीय फल काफल की पार्टी दी। कई भाजपाई तो दिखे पर प्रीतम और इंदिरा नहीं पहुंचे। भाजपा सरकार की पोल खोलने की गरज से बैलगाड़ी पर यात्रा भी निकाल चुके हैं। इस चक्कर में सरकार ने कोरोना की बंदिश तोड़ने के आरोप में कई मुकदमे भी उनके खिलाफ दर्ज कर दिए। असली शोहरत उनके साथ जुबानी जंग कर भाजपा के सूबेदार बंशीधर भगत ने दिलाई। पिछले साल हुई हरीश रावत की काफल पार्टी में तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पहुंचे थे। कमाल का घालमेल है सूबे के नेताओं के रिश्तों में। आलाकमान भी इस बात को समझ नहीं पा रहा है।

सिस्टम से मिल रही कलेक्टरी

मप्र की प्रशासनिक वीथिका में हाल ही में हुए कुछ तबादलों को लेकर तरह-तरह की चर्चा हो रही है। इसकी वजह यह है कि कई अफसरों का दामन दागदार होने के बाद भी उन्हें कलेक्टर जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठाया गया है। प्रदेश के एक बड़े जिले में हाल ही में पदस्थ किए गए एक कलेक्टर को लेकर जब आपत्ति उठाई गई तो सत्तारूढ़ पार्टी के एक कद्दावर नेता व सांसद ने यह कहकर आपत्ति को खारिज कर दिया कि यह तो सिस्टम से आए हुए हैं। अब वह सिस्टम क्या है, यह तो उक्त सांसद ही बता सकते हैं। लेकिन प्रशासनिक वीथिका में सिस्टम का मतलब **लेनदेन की प्रक्रिया** मानी जाती है। इसकी प्रमाणिकता इस बात से भी होती है कि 2010 बैच के एक आईएएस अधिकारी इन दिनों अपने पॉकेट में लक्ष्मी लेकर घूम रहे हैं कि उन्हें कलेक्टरी मिल जाए। वैसे इन साहब ने जबलपुर और होशंगाबाद के लिए भी बोली लगाई थी। लेकिन इनकी दाल नहीं गल पाई। **संस्कारधानी** के लिए तो महाकाल की नगरी वाले भक्त बाजी मार गए। वैसे देखा जाए तो प्रदेश के सभी 52 जिलों में कलेक्टर बनने के लिए अफसर लगातार हाथ-पांव मार रहे हैं। इसकी वजह यह है कि प्रदेश में एक सैकड़ा से अधिक आईएएस ऐसे हैं जो कलेक्टर बनने की पात्रता रखते हैं। ऐसे में यह बात तो तय है कि उन्हीं अफसरों की लॉटरी लग पाएगी जो कलेक्टर बनने के सिस्टम को भलीभांति समझते हैं।

महंगे मोबाइल का राज

मोबाइल जरूरत के साथ ही स्टेटस सिंबल बन गया है। किसी व्यक्ति के हाथ में मोबाइल देखकर उस व्यक्ति की हैसियत का आंकलन किया जा सकता है। प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों एक बड़े साहब का मोबाइल चर्चा में है। इसकी वजह यह है कि गंभीर स्वभाव वाले साहब के हाथ में इन दिनों 2 लाख रुपए का मोबाइल देखा जा रहा है। वैसे तो साहब ईमानदारी का पुतला माने जाते हैं, लेकिन महंगा मोबाइल कानाफूसी कर रहा है। जब इसकी पड़ताल की गई तो यह तथ्य सामने आया कि मुख्य सचिव स्तर के इन साहब का जब से कद बढ़ा है, तब से इनको महंगी वस्तुओं का शौक भी बढ़ा है। बताया जाता है कि अपना-अपना हित साधने के लिए साहब के चहेते अफसरों के साथ ही ठेकेदार आदि भी साहब को महंगी वस्तुएं भेंट कर जाते हैं। कुछ सूत्र तो यह दावा करते हैं कि अब तो साहब बिना लिए-दिए बात भी नहीं करते हैं। यानी साहब ने अपने हर काम की फीस तय कर दी है। बताया जाता है कि हथेली पर दूब उगाने में माहिर अफसर साहब की नई नीति का फायदा उठाने के लिए लक्ष्मी का चढ़ावा चढ़ाकर खूब चांदी काट रहे हैं। लक्ष्मीपूजन के बाद साहब किसी को निराश नहीं होने देते हैं।

चुनाव जीतने की जमावट

प्रदेश में उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया। ऐसे में चुनावी जमावट होने लगी है। मालवा में उपचुनाव को जीतने के लिए दो मंत्रियों ने अपनी पसंद से दो अधिकारियों की जमावट की है। उन्होंने संगठन और सरकार को विश्वास दिलाया है कि इन अधिकारियों के कारण चुनावी खर्च की भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सूत्रों का कहना है कि मंत्रियों ने जिन अधिकारियों पर दांव लगाया है उनमें एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं और पहले से ही वहां पदस्थ हैं। जबकि राज्य प्रशासनिक सेवा के एक अन्य अधिकारी को हाल ही में वहां पदस्थ किया गया है। सूत्र बताते हैं कि चुनावी मैदान में **ताल ठोकने वाले एक मंत्रीजी** ने विश्वास दिलाया है कि वरिष्ठ अधिकारी ने चुनावी खर्च का जिम्मा उठा लिया है। वे पहले से ही जिले में पदस्थ हैं इसलिए उनकी पकड़ और समझ भी अधिक है। इसलिए अगर वे अपने पद पर बने रहते हैं तो इससे चुनाव में फायदा होगा। मंत्रीजी की मांग पर सरकार ने उक्त वरिष्ठ अधिकारी को फिलहाल अभयदान दे दिया है। वहीं दूसरे अधिकारी 2007 बैच के राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। इनके बारे में कहा गया है कि ये चुनाव में वहां पार्टी की जीत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए उन्हें ट्रांसफर कराकर अहिल्या नगरी में भेजा गया है। अब देखना यह है कि मंत्रियों का इन अधिकारियों पर किया गया विश्वास सफल होता है या नहीं।

जांच अधूरी, कमाई पूरी

हनीट्रैप कांड जहां कई अधिकारियों के लिए आफत बन गया है, वहीं एक साहब के लिए मनमाफिक कमाई का जरिया बन गया था। 1985 बैच के उक्त साहब 31 अगस्त को रिटायर हो गए, लेकिन उन्होंने जमकर माल कूटा है। दरअसल, साहब हनीट्रैप कांड के लिए बनी एसआईटी के सर्वेसर्वा थे। इस कांड में 48 केस दर्ज हैं। साहब ने इन केसों को तीन कैटेगरी में बांट रखा था। ए कैटेगरी में सेक्स, बी कैटेगरी में फोटो और सी कैटेगरी में वॉट्सएप चैट थे। साहब ने भी कैटेगरी के हिसाब से इस केस में जमकर कमाई की है। उन्होंने हनीट्रैप में फंसे अफसरों को उनके सेक्स वीडियो, फोटो और वॉट्सएप चैट दिखा-दिखाकर कभी प्यार से, कभी पुचकारकर, तो कभी डराकर उनसे बड़ी-बड़ी रकम वसूली है। उन्होंने बताया जाता है कि जांच भले ही अधूरी रह गई है, लेकिन साहब ने कमाई पूरी की है। साहब के करीबी अफसरों का कहना है कि हनीट्रैप मामले में बड़ी कमाई करने के बाद भी साहब संतुष्ट नहीं थे। क्योंकि उन्हें मालूम था कि यह केस पैसों का झांड़ है। इसीलिए रिटायर होने के बाद वे खुश नहीं थे, क्योंकि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए।

तबादले के लिए परिक्रमा

जिस पार्टी की सरकार रहती है उस पार्टी का मुख्यालय अफसरों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं होता है। इस तीर्थ स्थल का मुख्य पदाधिकारी अफसरों के लिए भगवान से कम नहीं होता है। क्योंकि उसकी परिक्रमा कर अधिकारी अपना हित साध लेते हैं। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से अफसरों का तीर्थ स्थल तो बदला ही है, साथ ही वह चेहरा भी बदल गया है जिसके आशीर्वाद से उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है। सूत्र बताते हैं कि इसलिए प्रदेश के अधिकांश अधिकारी इन दिनों भगवाधारी माननीय की परिक्रमा कर मनमाफिक तबादले करा रहे हैं। आलम यह है कि उक्त माननीय राजधानी में रहें या फिर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में वे अफसरों से मिलने के लिए वे रिजर्व टाइम रखते हैं। अफसरों को भी माननीय की यह स्टाइल खूब भा रही है। प्रदेश के एक अधिकारी ताल ठोककर कहते हैं कि जो भी हो अगर आपने उक्त माननीय की मन से परिक्रमा कर उनकी मंशा अनुसार प्रसाद चढ़ा दिया तो आपको मनमाफिक जगह मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। बताते हैं कि माननीय का एक गुर्गा मंत्रालय में प्रमुख अफसरों से रोजाना मिलकर सारे काम करवाता है।

अगर नारकोटिक्स ब्यूरो बुलीवुड में एंट्री करता है तो कई ए-लिस्टर्स सलाखों के पीछे होंगे। अगर ब्लड टेस्ट किए जाते हैं तो कई हैरान करने वाले खुलासे होंगे। उम्मीद करती हूं कि पीएमओ स्वच्छ भारत अभियान के तहत बुलीवुड नाम के गटर को साफ कर देंगे।

● **कंगना रनौत**

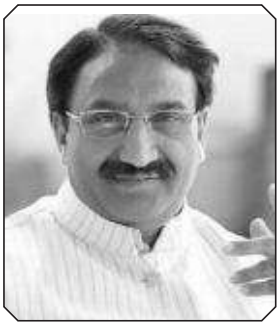

केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य को देखते हुए काम कर रही है। फिर भी न जाने क्यों विपक्षी पार्टियां जेईई और नीट की परीक्षा को लेकर बखेड़ा खड़ा कर रही हैं। मेरे पास रोजाना अनगिनत मेल ऐसे स्टूडेंट्स के आते हैं, जो यह जानना चाहते हैं कि परीक्षा कब होगी? वे छात्र यह नहीं चाहते हैं कि किसी भी सूरत में इस साल जीरो ईयर घोषित हो।

● **रमेश पोखरियाल निशंक**

एमएस धोनी ने अपने कैरियर के बहुत बड़े हिस्से में लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी की। बतौर बल्लेबाज वे सबसे ज्यादा सफल चार नंबर पर रहे। लेकिन, टीम पर दबाव न पड़े, इसलिए उन्होंने निचले क्रम में खेलने का फैसला किया। क्योंकि टीम को लगता था कि लोअर ऑर्डर में दबाव झेलने के लिए उनसे बेहतर कोई बल्लेबाज नहीं होगा।

● **आरपी सिंह**

विपरीत परिस्थितियों में हार मानकर घर बैठ जाना सबसे बड़ी हार होती है। आज मैं भले ही अरबों का मालिक हूं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब मेरे पास पैसों की तंगी थी। ऐसी स्थिति में मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैदान में डटे रहा। जिसका परिणाम है अमेजन।

● **जेफ बेजोस**

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' जैसे ख्यात सीरियल में काम करना बड़ी चुनौती है। पुरानी अंजली मेहता (नेहा मेहता) पिछले 12 सालों से इस शो से जुडी थीं जाहिर है लोगों के बीच उनकी एक छवि बनी हुई है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हूं कि लोग मेरी उनसे तुलना करेंगे ही। ऐसी स्थिति में मैंने सिर्फ अपना बेस्ट देने का सोचा है इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे मुझे मौका दें ताकि मैं उनकी उम्मीदों पर खरी उतरूं। ताली के साथ गाली खाने के लिए भी तैयार हूं (मुस्कुराते हुए)। ऑडियंस की जो राय होगी उसे मैं सर झुकाकर मान लूंगी।

● **सुनैना फौजदार**

वाक्युद्ध

कांग्रेस किस स्थिति में है यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि केंद्र सरकार पर उंगली उठाने से पहले वे अपने दामन को भी देख लिया करे। कांग्रेसी स्वयं आपस में लड़-झगड़ रहे हैं। लेकिन इसके लिए भाजपा को दोषी मान रहे हैं। अब ऐसी पार्टी के लिए क्या कहा जा सकता है।

● **जेपी नड्डा**

जब भी किसी मसले को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछा जाता है तो वे उसका जवाब देने की बजाय हम ही से सवाल पूछ लेती है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि आप सत्ता में हो तो सवाल भी आप ही से पूछा जाएगा और जवाब भी आपको ही देना होगा। लेकिन सत्तापक्ष अपने आगे विपक्ष को कोई महत्व नहीं दे रहा है।

● **राहुल गांधी**

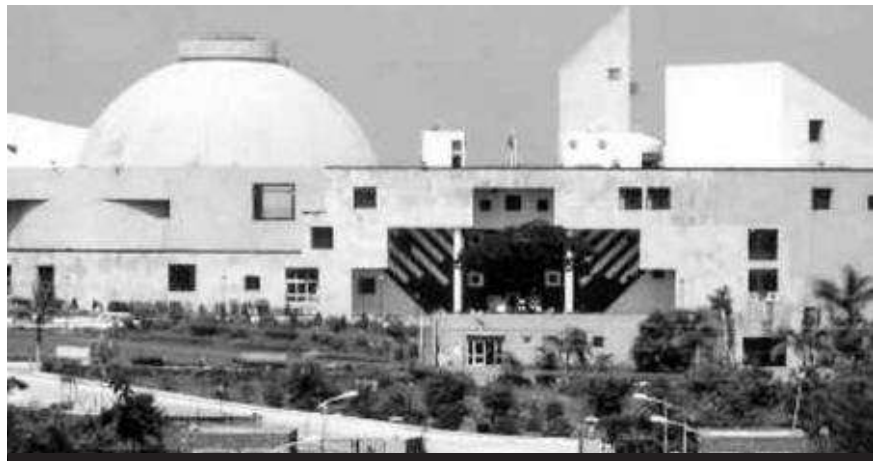

उपचुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन

लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र आयोजित होने जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 21 से 23 सितंबर के बीच बुलाया गया है। राजभवन की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया की जाएगी। माना जा रहा है कि मध्यप्रदेश विधानसभा के इस सत्र के दौरान शिवराज सरकार अपना बजट भी पेश करेगी। इसके अलावा कुछ अहम अध्यादेशों को भी विधानसभा से पारित करवाया जाएगा। इससे पहले विधानसभा सचिवालय की ओर से सत्र आहूत करने के लिए प्रस्ताव राजभवन भेजा गया था, जहां राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई। बता दें कि इससे पहले जुलाई में जब विधानसभा का सत्र आहूत किया जाना था, तो कोरोना की वजह से उसे सर्वदलीय बैठक में सहमति के बाद टालने का फैसला ले लिया गया था।

विधानसभा सत्र में सरकार आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। इसके माध्यम से प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक व कृषि विकास दर के आंकड़े सामने रखे जाएंगे। इसके साथ ही वर्ष 2020-21 के लिए बजट अध्यादेश के स्थान पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विनियोग विधेयक प्रस्तुत करेंगे। सरकार नगरीय निकाय चुनाव व्यवस्था में परिवर्तन के लिए संशोधन विधेयक लाएगी। इसके माध्यम से प्रदेश में एक बार फिर मतदाता ही सीधे महापौर और अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। प्रदेश में कोरोना संकट और सत्ता परिवर्तन से जुड़ी गतिविधियों के कारण विधानसभा का बजट सत्र नहीं हो पाया था। इसकी वजह से शिवराज सरकार को एक लाख 66 करोड़ रुपए से अधिक का लेखानुदान अध्यादेश के माध्यम से लाना पड़ा था। उम्मीद थी कि मानसून सत्र तक स्थितियां सामान्य हो जाएंगी और विधिवत बजट प्रस्तुत होगा लेकिन कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए सर्वसम्मति से सत्र को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया। अब, 21 से 23 सितंबर तक चलने वाले विधानसभा सत्र में सभी जरूरी शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे।

वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इसमें बजट अध्यादेश के स्थान पर विधेयक लाया जाएगा। वहीं, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। इसमें प्रति व्यक्ति के साथ औद्योगिक सहित अन्य क्षेत्रों की विकास दर के बारे में आंकड़े सामने रखे जाएंगे। सत्र में पेट्रोल और डीजल पर एक-एक रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के लिए किए गए वैट अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक प्रस्तुत होगा। वहीं, श्रम कानून और मंडी अधिनियम में अध्यादेश के माध्यम से किए गए बदलाव के लिए श्रम और कृषि विभाग संशोधन विधेयक लाएंगे।

सरकार ने तय किया है कि नगर निगम के महापौर और नगर पालिका व परिषद के अध्यक्ष का चुनाव सीधे मतदाताओं से कराने के लिए प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को फिर से लागू करेगा। इसके लिए नगर पालिक अधिनियम में संशोधन विधेयक का मसौदा तैयार हो चुका है। कमलनाथ सरकार ने अधिनियम में संशोधन करके चुने हुए पार्षदों में से ही महापौर और अध्यक्ष का चुनाव करने की व्यवस्था को लागू किया था, हालांकि उस पर अमल के पहले ही कमलनाथ सरकार गिर गई। सूत्रों का कहना है कि सरकार 89 आदिवासी विकासखंडों में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए केंद्र की अनुमति मिलने पर साहूकारी अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव भी रख सकती है। सांसद और विधायकों को शीर्ष सहकारी संस्थाओं का अध्यक्ष और प्रशासक बनाने के लिए सहकारी अधिनियम में किए गए संशोधन के लिए भी विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।

मध्यप्रदेश विधानसभा का सत्र 24 सितंबर से पहले आहूत किया जाना संवैधानिक तौर पर अनिवार्य हो गया था। दरअसल इससे पहले विधानसभा का सत्र 24 मार्च को आहूत किया गया था और उसके बाद कोरोना की वजह से सत्र आहूत नहीं हो पाया। संवैधानिक नियमों के मुताबिक, विधानसभा के दो सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं हो सकता। यही वजह है कि 24 सितंबर से पहले सत्र आहूत करना अनिवार्य था। उधर विपक्ष लंबे वक्त से सरकार को घेरने के लिए विधानसभा सत्र का इंतजार कर रहा है। यह माना जा रहा है कि 21 सितंबर से जो सत्र आहूत किया जाएगा उसमें कांग्रेस, शिवराज सरकार को घेरने के लिए खास रणनीति तैयार करने जा रही है। कांग्रेस का निशाना सबसे ज्यादा उन मंत्रियों पर होगा जो विधायक नहीं रहते हुए भी मंत्री बन गए हैं। इसके साथ ही किसान बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर भी कांग्रेस ने शिवराज सरकार को घेरने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। वहीं सरकार के लिए यह सत्र इसलिए भी अहम है कि बजट के साथ उसे कई अहम बिल कानूनी तौर पर पारित करवाने हैं।

● **जितेन्द्र तिवारी**

अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पर रार

मप्र विधानसभा सत्र की घोषणा के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। भाजपा और कांग्रेस के बीच इसके लिए शक्ति परीक्षण हो सकता है। क्योंकि कांग्रेस ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा पूर्व में की थी। उधर, भाजपा में भी अध्यक्ष-उपाध्यक्ष को लेकर खींचतान चल रही है। सत्ता में भागीदारी को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार महाकौशल, विंध्य या मालवा क्षेत्र के किसी विधायक को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जिन भाजपा विधायकों का नाम विधानसभा अध्यक्ष के लिए सामने आ रहा है उसमें डॉ. सीताशरण शर्मा के अलावा विंध्य क्षेत्र से राजेंद्र शुक्ल, नागेंद्र सिंह, केदार शुक्ला और महाकौशल से गौरशंकर बिसेन और अजय विश्नोई शामिल हैं। वहीं उपाध्यक्ष के लिए भाजपा से जिन विधायकों के नाम इस पद के लिए सामने आया है उसमें प्रदीप लारिया, यशपाल सिंह सिसोदिया, नंदन मरावी और मौजूदा प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का नाम शामिल है। उधर, कांग्रेस भी दोनों पदों के लिए दावेदारी करने की तैयारी कर रही है।

भारत विश्व का सबसे युवा देश है। लेकिन यहां की राजनीति में अभी भी बुजुर्गियत हावी है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि जब भी कोई महत्वाकांक्षी युवा नेता आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसे उपेक्षा ही हाथ लगती है। खासकर कांग्रेस में तो यह परंपरा सी बन गई है। मप्र कांग्रेस में युवा विधायकों और नेताओं की भरमार है, लेकिन संगठन में वे हाशिए पर हैं। शायद यही वजह है कि कांग्रेस जनप्रिय नहीं हो पा रही है।

उपेक्षा का दंश

कांग्रेस में छायी खामोशी

मप्र की सत्ता से बाहर होने के बाद अब कांग्रेस संगठन में बदलाव की मांग को लेकर चिंगारी उठती दिखने लगी है। वजह है प्रदेश में संगठन की मजबूती के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया जाना। दरअसल अभी संगठन में आम कार्यकर्ता की जगह बड़े नेताओं के पट्ठों का कब्जा है। सरकार गिरने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बीच पूर्व की भांति संबंध भी नहीं रहे हैं। नेता-कार्यकर्ता भी उपचुनाव की बांट जोह रहे हैं। उसके बाद ही उनकी चुप्पी टूटने की संभावना है। प्रदेश में कांग्रेस संगठन की स्थिति का अंदाज इससे लगाया जा सकता है कि उसमें कितने महासचिव, सचिव और प्रवक्ता हैं, यह जानकारी अधिकृत रूप से कहीं नहीं हैं। कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की एक मई 2018 को जब जिम्मेदारी संभाली थी, उसके बाद विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण के दौरान जितने असंतुष्ट नेता थे, सभी को पद बांटे गए थे। पदों की बंदरबाट में नेता और उसके पद का कहीं रिकॉर्ड नहीं रखा गया, बल्कि लेटरहैड पर सीधी नियुक्ति दे दी गई। लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह असंतुष्टों को पद बांटे जाने से संगठन के पिरामिड को और ध्वस्त किया गया।

देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस दिन पर दिन अपना वजूद खोती जा रही है। इसकी वजह यह है कि पार्टी में युवा नेतृत्व को हमेशा हाशिए पर रखा जाता रहा है। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि पार्टी में हमेशा से ही बुजुर्गों के हाथ में नेतृत्व रहता है, सिर्फ कुछ अपवादों को छोड़ दें तो। अगर मप्र की बात करें तो पिछले दो दशक के दौरान अरूण यादव ही एकमात्र ऐसे नेता रहे जिनको युवा नेतृत्व के तौर पर पार्टी की कमान सौंपी गई थी। यानी यहां युवा नेतृत्व हाशिए पर रहा है। युवा नेताओं की उपेक्षा, गुटबाजी और हवाहवाई नेताओं के बढ़ रहे महत्व के चलते 15 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस 15 माह में ही सत्ता से बाहर हो गई। यही नहीं भारतीय राजनीति का सबसे चमकदार चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। लेकिन पार्टी ने इससे भी सबक नहीं लिया। इसका परिणाम यह हुआ है कि कांग्रेस के अन्य युवा विधायक भी नेतृत्व की चाह में कुलबुलाने लगे हैं।

कांग्रेस के एक वरिष्ठ विधायक कहते हैं कि बिल्ली को हमेशा छींका टूटने का इंतजार रहता है। लेकिन अब छींका टूटने का इंतजार करने की जगह पर छींका तोड़ने की जोर आजमाइश भी करनी पड़ती है। कांग्रेस की अदूरदर्शी सोंच की वजह से सत्ता का छींका टूटकर भाजपा के पक्ष में चला गया है। शायद यही वजह है कि पार्टी का युवा वर्ग पद और सम्मान पाने के लिए आवाज उठाने लगा है। बिल्ली की तरह छींका टूटने का इंतजार करने की जगह वह छींका तोड़ने के लिए उछलकूद करने लगे हैं। पार्टी के एक पदाधिकारी कहते हैं कि यह कांग्रेस का पुराना मर्ज है कि पार्टी में युवा नेतृत्व को हाशिए पर रखा जाता है। वह कहते हैं कि अब समय बदल गया है। भाजपा में युवाओं को आगे लाया जा रहा है। जबकि कांग्रेस में अभी भी बुजुर्ग नेताओं को ही महत्व दिया जा रहा है। लेकिन इस समय का युवा अपने मान-सम्मान के लिए सारी बाधाएं तोड़ने में देर नहीं करता है। इसलिए पार्टी आलाकमान को नीति और नीयत में बदलाव करने की जरूरत है।

कांग्रेस का इतिहास ही बिखराव का रहा है। पार्टी में उचित पद और सम्मान नहीं मिलने के कारण कई नेताओं ने अलग होकर नई पार्टी का गठन किया, जो आज कांग्रेस को चुनौती दे रही है। एक बार फिर कांग्रेस ऊहापोह में है। पार्टी में पुराने और नए नेताओं के बीच गहरी खाई बन गई है। युवा तुर्क विद्रोह के मूड में हैं और उन्हें संभालने तथा राज्यों में पार्टी को मजबूत करने की कोई कोशिश नहीं हो रही है, या ये युवा नेता जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गए हैं। आज के माहौल में, जबकि कांग्रेस की एक विपक्ष के रूप में देश में सबसे ज्यादा जरूरत है; यह पार्टी व्यापक जनाधार होते हुए भी एक तरह से अजीब-सी शून्यता की तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस के भीतर मंथन का यह दौर क्या देश के सामने एक नई और ऊर्जावान कांग्रेस ला पाएगा? या यह पार्टी एक इतिहास बनकर रह जाएगी? क्या कांग्रेस की ओवरहॉलिंग की जबरदस्त जरूरत है? इस तरह के सवाल राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिकाओं में उठ रहे हैं।

गौरतलब है कि 2018 में जब मप्र में कांग्रेस सरकार की कमान बुजुर्ग कमलनाथ को दी गई, तब से ही कांग्रेस में नई पीढ़ी की बगावत की आग सुलगने लगी। इसका परिणाम यह हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे युवा नेता को पार्टी छोड़नी पड़ी। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने से पार्टी में भगदड़ सी मच गई है। वहीं कांग्रेस के युवा विधायकों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा उबाल मारने लगी है। पिछले कुछ माह में युवा विधायकों ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। वहीं कुछ विधायक पार्टी का नेतृत्व करने के

लिए अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं।

कांग्रेस में युवा नेताओं की एक लंबी कतार है। हालांकि इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में वही रहते हैं, जो पहले से राजनीतिक परिवारों से हैं। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि इनमें से ज्यादातर राहुल गांधी के समर्थक रहे हैं। मप्र में कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद से उनकी जगह पाने के लिए कई युवा नेता सपना देख रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के एक युवा विधायक कहते हैं कि सियासत में खुद जगह बनाने के परिश्रम से आसान है खाली स्थान में अवसर तलाशना। स्वाभाविक है इस कोशिश में मुकाबला अपनों से हो जाए, फिर जो हालात बनते हैं, वह इन दिनों मप्र कांग्रेस की तस्वीर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में जाने से कांग्रेस का युवा चेहरा बनने की होड़ सीधे मुख्यमंत्री पद की दावेदारी तक पहुंच गई है। पार्टी में नई पीढ़ी भी उसी पुराने मर्ज का शिकार होती जा रही है, जिसके चलते मप्र में कई क्षत्रपों में टकराव होता रहा। पार्टी कमजोर होती गई। सत्ता की राह 2018 में तभी आसान बनी, जब पार्टी के कई गुटों को प्रभावहीन कर दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया साथ आए। लेकिन सिंधिया को उचित स्थान और सम्मान नहीं मिलने के कारण पार्टी को एक बड़ी बगावत का सामना करना पड़ा।

सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद से पार्टी के युवा नेताओं की महत्वाकांक्षा उभरकर सामने आने लगी है। पिछले दिनों सड़क से सोशल मीडिया तक कांग्रेस के युवा नेताओं को लेकर जो तमाशा हुआ, वह संकेत है कि आने वाले दिनों में नकुलनाथ, जयवर्धन सिंह और जीतू पटवारी सहित अन्य युवा नेताओं में सियासी खींचतान देखने को मिल सकती है। पर्दे के पीछे दिग्विजय सिंह, कमलनाथ सहित कुछ बुजुर्ग नेता भी हो सकते हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि कमलनाथ अपनी राजनीतिक विरासत के जरिए नकुलनाथ को, तो दिग्विजय सिंह अपने पुत्र जयवर्धन सिंह को आगे बढ़ा रहे हैं। मौजूदा समय में जीतू की छवि प्रदेश कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बराबर नहीं तो कम भी नहीं है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी का भी जीतू पर खास स्नेह है। ऐसे में लगता तो नहीं है कि नकुलनाथ के हाथों में कुछ आएगा। हां, अगर उपचुनावों में नकुल अपने विधानसभा क्षेत्र में जीत का परचम लहरा देते हैं तो उन्हें एआईसीसी या कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति में बड़ा औहदा जरूर मिल सकता है, लेकिन क्षेत्रीय राजनीति में पीसीसी चीफ पर दांव जीतू और जयवर्धन के अनुभव के सामने फीका पड़ना तय है। इस संबंध में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का कहना है कि नकुलनाथ हमारे प्रदेश से इकलौते सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में इतनी विपरीत परिस्थितियों में वे जीतकर आए हैं जिससे उन्होंने अपनी क्षमता साबित की है। हम सब लोग कांग्रेस के युवा उनके साथ खड़े हैं और उनके पीछे खड़े हैं। अगर एक बार जयवर्धन सिंह को एक तरफ हटा भी दिया जाए तो जीतू पटवारी से पार पाना नकुलनाथ और कमलनाथ दोनों के लिए ही आसान नहीं होगा।

भारतीय राजनीति में 50 साल की उम्र तक के नेता युवा की श्रेणी में आते हैं। इस नजरिए से देखें तो मप्र कांग्रेस में करीब 42 विधायक हैं जो युवा हैं। इनमें प्रदीप पाठक, जयवर्धन सिंह, तरवर सिंह, विनोद दीक्षित, विक्रम सिंह, राहुल सिंह, नीलांशू चतुर्वेदी, सिद्धार्थ कुशवाहा, कमलेश्वर पटेल, सुनील सराफ, विजय राघवेंद्र सिंह, संजय यादव, तरुण भनोट, भूपेंद्र मरावी, ओमकार सिंह मरकाम, नारायण सिंह पट्टा, अशोक मर्सकोले, हिना कांवरे, योगेंद्र सिंह, संजय शर्मा, सुनील उइके, कमलेश प्रताप शाह, विजय रेवनाथ चौरे, नीलेश पूसाराम उइके, निलय डागा, आरिफ मसूद, बापू सिंह तंवर, प्रियव्रत सिंह, कुणाल चौधरी, सचिन बिरला, सचिन यादव, मुकेश रावत, कलावती भूरिया, उमंग सिंघार, सुरेंद्र सिंह बघेल, हीरालाल अलावा, पांचीलाल मेड़ा, जगदीश पटेल, जीतू पटवारी, महेश परमार, हर्ष गहलोत और मनोज चावला आदि शामिल हैं। वहीं प्रदेश में कांग्रेस के एकमात्र सांसद नकुलनाथ भी युवा हैं। जबकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरूण यादव भी अभी 46 साल के हैं। यानी कांग्रेस में युवाओं की भरमार है।

एक तरफ प्रदेश में कांग्रेस बुजुर्ग नेतृत्व के सहारे चल रही है। वहीं भाजपा ने युवा वीडी शर्मा को संगठन की कमान सौंपी है। वीडी भाजपा के लिए भाग्यशाली साबित हुए हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी सत्ता में वापस आ गई है। यही नहीं वीडी ने जिस तरह सत्ता और संगठन के बीच सामंजस्य बना रखा है, उसे देखकर कांग्रेस युवा भी संगठन में कुछ करके दिखाने के लिए बेचैन हैं। ये सही है कि सियासी दलों की मजबूती उसके नेताओं की परस्पर प्रतिद्वंद्विता से भी पोषित होती है, लेकिन मप्र कांग्रेस के लिए हमेशा से नुकसानदेह साबित होती रही है, जिसके चलते ही कमलनाथ सरकार डेढ़ साल में ही न केवल विदा हुई, बल्कि भाजपा ने वापसी भी की। अब वही मर्ज नई पीढ़ी में भी देखा जा रहा है, जो पहले की तरह पनपता रहा तो कांग्रेस लंबे समय के लिए सत्ता के वनवास पर जा सकती है, हो सकता है उसे अस्तित्व के लिए भी जूझना पड़े। अपने पुत्रों को आगे बढ़ाने में व्यस्त बुजुर्ग नेताओं को एक बार इस पर भी विचार करना ही चाहिए।

● **कुमार राजेन्द्र**

सिंधिया की जगह कौन लेगा?

ज्योतिरादित्य सिंधिया जबसे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए हैं, उनकी खाली जगह को पाने के लिए युवा कांग्रेस उतावले हो रहे हैं। अब जाकर प्रदेश में सिंधिया की जगह लेने और कांग्रेस का युवा चेहरा बनने को लेकर पार्टी में युवा नेताओं की गोलबंदी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे व सांसद नकुलनाथ की दावेदारी ने सबको चौका दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछले मंत्रिमंडल में हमारे जो युवा मंत्री थे जैसे जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह, हनी बघेल, सचिन यादव, ओमकार मरकाम, ये सब अपने-अपने क्षेत्र में आने वाले उपचुनाव में युवाओं का नेतृत्व मेरे साथ करेंगे। नकुल के युवा नेतृत्व के बयान वाले वीडियो सामने आने के बाद सियासी माहौल गरमा गया है। दरअसल, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सियासत में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पार्टी के वरिष्ठ और बुजुर्ग चेहरे माने जाने लगे हैं। वहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी से नाता तोड़ने के बाद अब कई नेता युवा चेहरा बनने के लिए अपनी-अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं।

ताकि कोई और सिंधिया न बने

मध्यप्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक बार फिर दोहरी भूमिकाओं में आ गए हैं। कमलनाथ को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दायित्व सौंपा गया है। वे कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं। प्रदेश में कांग्रेस में फिर से पनप रही गुटबाजी को देखते हुए ये फैसला किया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष की दोहरी भूमिका के चलते ही कमलनाथ सरकार गिर गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का हाथ छोड़ भाजपा के कमल से दोस्ती की और अपने साथ लंबी विधायकों की फौज भी ले गए। सिंधिया की महत्वाकांक्षा के कारण नाथ सरकार गिरी और फिर से शिवराज सिंह की कमल सरकार बनी। वर्तमान में प्रदेश की राजनीति में कमलनाथ के सुपुत्र नकुलनाथ, दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह और जीतू पटवारी की बढ़ती महत्वाकांक्षा के कारण आलाकमान ने कमलनाथ को ही नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है।

दरअसल कमलनाथ मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और अब नेता प्रतिपक्ष भी चुने गए हैं। मप्र कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष के लिए कई दावेदार थे लेकिन किसी को ये मौका नहीं दिया गया। नेता प्रतिपक्ष की रेस में पहला नाम पूर्व मंत्री और लहार विधायक डॉ. गोविंद सिंह का था। डॉ. गोविंद सिंह ग्वालियर-चंबल अंचल का नेतृत्व करते हैं और भिंड जिले की लहार विधानसभा सीट से लगातार 7वीं बार के विधायक हैं। ऐसे में माना जा रहा था कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन ये बात भी बेहद गौर करने की है कि गोविंद सिंह को दिग्विजय सिंह का करीबी माना जाता है। गोविंद सिंह के अलावा पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन भी नेता प्रतिपक्ष बनने की रेस में थे लेकिन वो कमलनाथ के करीबी हैं। अगर दोनों में से किसी एक को भी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी जाती तो एक बार फिर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के समर्थकों की पर्दे के पीछे से गुटबाजी शुरू हो जाती। ऐसे में कांग्रेस में जारी गुटबाजी के बीच कमलनाथ को चुना गया ताकि पावर सेंटर्स की आशंकाओं को खत्म किया जा सके।

इधर, युवा चेहरों पर फोकस रखते हुए दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह का नाम भी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सामने आ रहा था। लेकिन जयवर्धन और कमलनाथ के सुपुत्र नकुलनाथ में भी प्रतियोगिता चल रही है और दोनों को ही प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री कहकर प्रचारित किया जा रहा है। 9 जुलाई को दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह का जन्मदिन था। इस दौरान राजधानी भोपाल में उन्हें मध्यप्रदेश का भावी मुख्यमंत्री बताते हुए पोस्टर लगाए गए। इस पोस्टर के बाद राजनीति शुरू हुई। इसके तुरंत बाद कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ का सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ वायरल वीडियो में कह रहे थे कि मैं उपचुनाव में युवाओं का नेतृत्व करूंगा। पिछले मंत्रिमंडल में हमारे मंत्री जयवर्धन सिंह, जीतू पटवारी, सचिन यादव, हनी बघेल और ओमकार मरकाम अपने-अपने क्षेत्र में मेरे साथ युवाओं का नेतृत्व करेंगे। इसी वीडियो के बाद से प्रदेश में सियासी माहौल गरमाने लगा जिसकी गर्माहट अब तक बनी हुई है।

कमलनाथ को दोहरी भूमिका सौंपने के पीछे आलाकमान की एक मंशा ये भी है कि आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी में किसी तरह की फूट नहीं चाहती है। मध्यप्रदेश में जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, तब भी वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। उस समय सिंधिया खेमे के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे थे। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह का खेमा भी सक्रिय था। ऐसे में कांग्रेस ने प्रदेश के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की लेकिन यहां कांग्रेस की ये गलती कमलनाथ सरकार पर भारी पड़ गई। यही कारण रहा कि 73 वर्षीय कमलनाथ को ही नेता प्रतिपक्ष भी बनाया गया जबकि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी उनके पास पहले से है। दरअसल वजह साफ है कि केंद्रीय आलाकमान फिर से स्टेट कांग्रेस में दो पावर सेंटर नहीं बनाना चाहता और न ही गुटबाजी को हवा देना चाहता है। इसका परिणाम मध्यप्रदेश में पहले ही देख चुके हैं। मप्र में फिर से कोई सिंधिया न बने इसलिए कमलनाथ को ही नेता प्रतिपक्ष का अहम पद का निर्वाह भी कराया जा रहा है। जल्द विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले उनके सिर पर नेता प्रतिपक्ष का सेहरा बांध दिया गया है।

● **अरविंद नारद**

कांग्रेस का फैसला जरूरी था या फिर विकल्प?

मध्यप्रदेश में कमलनाथ के पास दोहरी जिम्मेदारी है। वो मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और अब नेता प्रतिपक्ष भी चुने गए हैं। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष के लिए कई दावेदार थे लेकिन मौका कमलनाथ को दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष की रेस में पहला नाम पूर्व मंत्री डॉ. गोविंद सिंह का था। डॉ. गोविंद सिंह ग्वालियर-चंबल अंचल का नेतृत्व करते हैं। भिंड जिले की लहार विधानसभा सीट से लगातार 7वीं बार विधायक हैं। ऐसे में माना जा रहा था कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। गोविंद सिंह को दिग्विजय सिंह का करीबी माना जाता है। लेकिन कांग्रेस में जारी गुटबाजी के बीच कमलनाथ को चुना गया। दूसरी तरफ गोविंद सिंह के अलावा पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन भी नेता प्रतिपक्ष बनने की रेस में थे लेकिन वो कमलनाथ के करीबी थे। इस कारण उन्हें भी नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया। दरअसल, आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी में किसी तरह की फूट नहीं चाहती है। ऐसे में पार्टी ने 73 वर्षीय कमलनाथ पर भरोसा किया। मध्यप्रदेश में जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तब भी वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। उस समय सिंधिया खेमे के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे थे, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह का खेमा भी सक्रिय था ऐसे में कांग्रेस ने प्रदेश के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कमलनाथ को नेता प्रतिपक्ष इसलिए बनाया गया है कि पार्टी में खेमेबाजी ना हो।

घोषणा कब बनेगी हकीकत?

कोरोना संक्रमण के कारण मप्र सहित देशभर में बेरोजगारी बढ़ी है। सरकारी नौकरियों का टोटा तो पहले से ही था, अब प्राइवेट सेक्टर भी दगा दे रहे हैं। ऐसे में मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि अब प्रदेश के सरकारी विभागों में निकलने वाली नौकरी केवल प्रदेशवासियों को ही मिलेगी। लेकिन क्या यह घोषणा हकीकत में बदल पाएगी? यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि इस व्यवस्था को लागू करने में सरकार के सामने कई बाधाएं आएंगी। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी घोषणा की थी कि प्रदेश के निजी क्षेत्रों में 70 फीसदी प्रदेश के युवाओं को नौकरी दी जाएगी, लेकिन इसका पालन नहीं हो सका।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब प्रदेश की सभी सरकारी नौकरियों को केवल वहां के मूलनिवासियों के लिए आरक्षित करने की बात कही, तो स्वाभाविक तौर पर इस घोषणा पर तीखी प्रतिक्रिया आई और बहस शुरू हो गई। आरक्षण पर भारत में लंबी कानूनी बहस और कई अदालती फैसले आ चुके हैं। लेकिन 'सकारात्मक कार्रवाई और मूलनिवासी आरक्षण' की समानताओं और उनमें भेद पर सवाल खड़े होते रहते हैं। इसकी वजह संवैधानिक व्यवस्था है। दरअसल, संविधान का अनुच्छेद 16(1) भारत के सभी नागरिकों के लिए नियुक्तियों और रोजगार में अवसरों की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 16(2) यह भी तय करता है कि किसी भी नागरिक के साथ लिंग, जाति, धर्म, भाषा, जन्मस्थल आदि के आधार पर किसी रोजगार या पद पर नियुक्ति में भेदभाव नहीं हो सकता, इन आधारों पर उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन अनुच्छेद 16(3) इन नियमों के संबंध में अपवाद की बात करता है। इसके मुताबिक, संसद कोई ऐसा कानून बना सकती है, जिसमें किसी सार्वजनिक पद या रोजगार में नियुक्ति के लिए किसी खास इलाके में निवास स्थान होना जरूरी हो सकता है।

यह ऐसी ताकत है, जो स्पष्ट तौर पर संसद में निहित है, ना कि राज्य विधानसभा में। इसका मतलब हुआ कि सार्वजनिक रोजगारों में जन्मस्थल के आधार पर किसी भी तरह के आरक्षण को दिए जाने का अधिकार सिर्फ भारत की संसद को है, ना कि कोई राज्य ऐसा करने में सक्षम है। इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि अनुच्छेद 19(1) के तहत, भारत के हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में रहने और वहां बसने का अधिकार है। साथ में भारत के नागरिक के तौर पर, किसी भी राज्य के किसी भी सार्वजनिक दफ्तर में उनके जन्मस्थल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आखिर संविधान किस तरह के सकारात्मक कदम का प्रबंधन करता है और कैसे यह समता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के जरिए सकारात्मक कार्रवाईयों का प्रावधान किया जाता है। इनसे राज्य को उच्च शिक्षण संस्थानों और नियुक्तियों में सामाजिक, शैक्षिक पिछड़े वर्गों या फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों से आने वालों के लिए विशेष प्रावधानों के जरिए आरक्षण की व्यवस्था करने का अधिकार मिलता है। यह वह समुदाय होते हैं, जिनका राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में जरूरी प्रतिनिधित्व नहीं होता। इस व्यवस्था के पीछे समान लोगों के लिए समान मौके और कुछ कमजोर तबकों के लिए आरक्षित मौकों की व्यवस्था किए जाने का विचार है।

सामान्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस तरह के आरक्षण के खिलाफ रहा है। प्रदीप जैन बनाम् भारत संघ के मामले में कोर्ट ने पाया कि मूलनिवासियों के लिए आरक्षण दिया जाना संविधान का उल्लंघन है। लेकिन कोर्ट ने इसके खिलाफ कोई तय फैसला नहीं दिया, क्योंकि यहां मामला समता के अधिकार से जुड़ा था। कोर्ट ने अपने परीक्षण में कहा कि ऐसा करना प्राथमिक तौर पर संविधान के हिसाब से सही नहीं लगता, हालांकि कोर्ट ने इस पर कोई तय नजरिया व्यक्त करने से इनकार कर दिया। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनंदा रेड्डी बनाम् आंध्रप्रदेश राज्य मामले में भी प्रदीप जैन केस के फैसले को ही बरकरार रखा गया और तेलुगू माध्यम में परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए 5 फीसदी ज्यादा नंबर वाले प्रावधान को रद्द कर दिया।

हाल में हरियाणा कैबिनेट ने एक अध्यादेश पारित किया है, जिसके कानून बन जाने के बाद प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसदी आरक्षण हो जाएगा। 2008 में महाराष्ट्र ने राज्य सरकार से मदद लेने वाले उद्योगों में 80 फीसदी आरक्षण स्थानीय लोगों के लिए करने का प्रस्ताव रखा था, हालांकि इसे लागू नहीं किया गया। इसी तरह गुजरात में भी 1995 में स्थानीय लोगों के लिए 85 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि ना तो निजी क्षेत्र और ना ही सार्वजनिक क्षेत्र में इस नीति को लागू किया गया। ऐसे में मप्र सरकार की घोषणा पर भी संदेह जताया जा रहा है।

● **रजनीकांत पारे**

स्थानीय लोगों की भर्तियों पर आरक्षण की नीतियां

महाराष्ट्र में, जो भी कोई राज्य में 15 या उससे ज्यादा सालों तक रह चुका हो, उसे सरकारी नौकरियों में आवेदन करने की छूट है। बशर्ते वह मराठी में धाराप्रवाह हो। तमिलनाडु में भी इसी तरह का एक भाषायी टेस्ट होता है। इन आरक्षणों का कानूनी आधार सार्वजनिक दफ्तरों की आधिकारिक भाषा है, जो सरकारी नौकरियों के क्रियान्वयन के लिए बेहद जरूरी है। पश्चिम बंगाल में भी कुछ पदों के लिए भाषा परीक्षा ली जाती है, हालांकि सामान्य तौर पर वहां सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। उत्तराखंड में तीसरे और चौथे दर्जे की सरकारी नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित हैं। मेघालय में खासी, जयंतिया और गारो जनजातियों के लिए समग्र तौर पर 80 फीसदी स्थानीय नौकरियों में आरक्षण है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 80 फीसदी नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी तो सभी राज्यों ने इस दिशा में लक्ष्य बनाकर काम करना शुरु किया था। लेकिन मप्र ने स्वच्छता अभियान को आंदोलन की तरह अपनाया। इसका परिणाम यह हुआ कि यहां के शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में हमेशा आगे रहे। प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी इंदौर का दबदबा शुरु से है, वहीं भोपाल सहित अन्य शहर भी भारतीय पटल पर छाए हुए हैं।

इंदौर का चौका

मप्र वाकई अजब है, गजब है। देश का हृदय प्रदेश होने के नाते इस प्रदेश का अपना ही महत्व है। इस बात को यहां का शासन-प्रशासन और जनता भी अच्छी तरह जानती है। यही कारण है कि कई मामलों में मप्र देश के लिए मिसाल बनकर सामने आता है। स्वच्छता सर्वेक्षण में मप्र शुरू से मिसाल बना हुआ है। प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर ने तो अपनी अलग ही छाप छोड़ी है। वहीं राजधानी भोपाल सहित अन्य नगरीय निकाय भी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण-2020 में मप्र ने एक बार फिर अपना लोहा मनवाया है।

इंदौर शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण में एक के बाद एक चार साल से लगातार देश के सबसे साफ शहर का खिताब हासिल किया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में प्रदेश के चार शहर टॉप-20 में शामिल हुए हैं। इसमें पहले नंबर पर फिर इंदौर शहर रहा है। 7वें नंबर पर भोपाल, 13वें पर ग्वालियर और 17वें पर जबलपुर रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से बात करते हुए बताया कि **जब एक बार** वे इंदौर आए थे तो उनके जापानी मित्र ने उसने कहा था कि मैं शहर में गंदगी ढूंढने निकला था लेकिन मिली नहीं। केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, जब दूसरे देश जहां सफाई को लेकर विशेष ध्यान दिया जाता है, वहां के लोग ऐसी बात कहें।

स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार भोपाल की रैंकिंग सुधकर 7वें नंबर पर आ गई है। पिछले साल यह 19वें नंबर पर था। इस बार भोपाल को 6 हजार में से 5066.31 अंक मिले हैं। इसके पहले हुए सर्वेक्षण में भोपाल को एक बार सबसे स्वच्छ राजधानी भी घोषित किया जा चुका है, लेकिन इस बार यह खिताब नहीं मिला। ग्वालियर शहर इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में 46 अंकों की छलांग लगाकर 59 से 13वें नंबर पर पहुंच गया है। इस बार 10 लाख आबादी वाले स्वच्छ शहरों की सूची में जबलपुर ने 17वीं रैंक हासिल की है। इस बार शहर की रैंकिंग गिर गई है। जबलपुर को सिटीजन फीडबैक में अवॉर्ड मिला है। छोटे शहरों में मध्यप्रदेश के खरगोन ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं उज्जैन को 12वां, बुरहानपुर को 14वां, सिंगरौली को 15वां और छिंदवाड़ा को 16वां स्थान मिला है।

जबलपुर जिले की नगर पालिका परिषद सिहोरा को स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के तहत एक लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में सिटिजन लेड इनोवेशन केटेगरी में ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के लिए पुरस्कार मिला है। साथ ही निकाय को राज्य में 11वां स्थान एवं पश्चिम जोन में 67वां स्थान प्राप्त हुआ। जो कि पिछले वर्ष के स्वच्छता परिणामों से बेहतर है। स्वछता सर्वेक्षण रैंकिंग में सिवनी 134 से 82 पायदान आगे बढ़कर 52वें नंबर में आ गया है। पहली बार के सर्वेक्षण में सिवनी 178वें स्थान पर रहा था। अब भी स्वच्छता अभियान में कमियां हैं जिसके कारण सिवनी टॉप रैंकिंग में स्थान नहीं बना पा रहा है। सीएमओ नवनीत पांडे के अनुसार लगातार अच्छे प्रयास और नागरिकों के सहयोग से रैंकिंग में सुधार आ रहा है। टॉप रैंकिंग में आने के लिए कमियों को दूर करने के प्रयास किए जा रहे है।

मप्र के नगरीय निकाय लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पीछे शासन-प्रशासन का समर्पण और निकायों की सक्रियता का योगदान है। आज इंदौर भारत ही नहीं बल्कि विश्वभर के लिए स्वच्छता की मिसाल बना हुआ है। इंदौर में स्वच्छता अभियान की शुरुआत शहर से डस्टबिन के हटाए जाने और हर एक घर से कचरा इकट्ठा कर उसके निस्तारण से हुई। वर्ष

मप्र के 378 शहरों ने अपना बेहतर प्रदर्शन किया

स्वच्छ सर्वेक्षण-2020 के घटकों में मध्यप्रदेश के 378 शहरों ने अपना बेहतर प्रदर्शन किया। इसमें शहरों में स्वच्छता, साफ-सफाई, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण तथा उनका प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन और शहरों की स्वच्छता बनाए रखने में नागरिकों का सहयोग प्राप्त करने के प्रयास प्रमुखता से किए गए। इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप खुले में शौच से मुक्त राज्य का गौरव प्राप्त किया और हमारे 234 शहर ओडीएफ+ और 107 शहर ओडीएफ++ के परीक्षण में सफल हुए हैं। इसी क्रम में कचरा मुक्त शहर के मूल्यांकन में राज्य के 18 निकाय स्टार रेटिंग प्राप्त करने में सफल रहे हैं, जो देश में सर्वाधिक शहरों के मामलों में द्वितीय स्थान है। उल्लेखनीय है कि विगत तीन सर्वेक्षणों में भी मध्यप्रदेश के 20 शहर देश के सर्वश्रेष्ठ 100 शहरों में रहे हैं। स्वच्छ सर्वे में भोपाल ने लंबी छलांग लगाई है। पिछले सर्वे में 19वें पायदान पर रहे भोपाल को इस बार 7वीं रैंक मिली। अब राजधानी भोपाल देश का 7वां सबसे साफ-सुथरा शहर बन गया है। देश के साफ-सुथरे शहरों की टॉप-20 लिस्ट में प्रदेश के चारों महानगरों को जगह मिली है। लिस्ट में इंदौर लगातार चौथी बार टॉप पर है, इसके बाद भोपाल 7वें, ग्वालियर 13वें और जबलपुर 17वें नंबर पर है। भोपाल को सेल्फ सस्टेनेबल कैपिटल का अवॉर्ड भी मिला है। हालांकि, इस बार क्लीनेस्ट कैपिटल ऑफ इंडिया का खिताब नहीं मिल सका। इसमें हम नई दिल्ली से पिछड़ गए।

2016 में इस शहर में पूरे 85 वार्ड में हर घर से कचरा उठाया जाने लगा था। हालांकि, वर्ष 2019 आते-आते इंदौर ने कचरे को जमा करने से लेकर उसके **समुचित इस्तेमाल** की एक ऐसी व्यवस्था विकसित कर ली है कि कई शहर कचरे के प्रबंधन को यहां से सीख सकते हैं। तकरीबन 275 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले और 27 लाख की आबादी वाले इस शहर से रोजाना 1,150 टन कचरा निकलता है जिसमें से आधा कचरा जैविक होता है। हर तरह के कचरे को दोबारा प्रयोग में लाने के लिए शहर में बीते कुछ वर्षों में कई सफल प्रयोग हुए हैं।

स्वच्छ भारत मिशन के सलाहाकार असद वारसी के मुताबिक इस वक्त शहर के हर घर से कचरे-कचरे को जमा किया जाता है। कचरा जमा कर इसे इकट्ठा करने के बाद इंदौर नगर निगम का असली काम शुरू होता है। इंदौर नगर निगम के सलाहकार जावेद वारसी जामी बताते हैं कि कचरा इकट्ठा करते समय ही इसे गीले कचरे और सूखे कचरे के रूप में अलग-अलग रखा जाता है। कचरा इकट्ठा करने वाले वाहन के चालक गौतम कनेरिया बताते हैं कि शुरुआत में 80 प्रतिशत लोग गीला, सूखा कचरा एक साथ ही रखते थे, लेकिन काफी अनुरोध के बाद अब हमें लोगों के घर से ही कचरा अलग-अलग मिलने लगा है। कचरा ठीक से अपने गंतव्य तक पहुंचे इसके लिए हर गाड़ी में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है। शहर में 8000 से अधिक सफाईमित्र भी हैं, जो कचरा इकट्ठा करने के साथ सड़कों की सफाई भी करते हैं।

इंदौर में आमतौर पर सड़के साफ और चमकती हुई दिखती हैं। इसकी वजह सफाई के काम में लगी मशीनें हैं जो हर रात करीब 800 किलोमीटर सड़क, डिवाइडर और फुटपाथ की सफाई करती हैं। इस काम में 400 लीटर पानी लगता है। वारसी बताते हैं कि इसमें लगने वाला अधिकतर पानी रिसाइकल किया हुआ होता है। इंदौर नगर निगम के मुताबिक सड़कों की धुलाई के बाद सांस के साथ जाने वाले धूल के कणों की मात्रा 76 माइक्रोग्राम तक कम हो गई है जो कि वर्ष 2014 में 142 माइक्रोग्राम थी। इससे पर्यावरण का स्तर सुधरा है। वारसी कहते हैं कि इंदौर में बीते कुछ वर्षों से थैला बैंक और बर्तन बैंक शुरू हुआ, जिसकी मदद से आम लोग कागज और जूट के बने थैले और किसी बड़े आयोजन के लिए स्टील के बर्तन ले सकते हैं। इस तरह से कचरे की मात्रा में लगातार कमी आई। शहर में पॉलीथिन पर पाबंदी भी है और लोगों को अपना थैला लेकर चलने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया।

देश के 10 सबसे साफ शहर

रैंक	शहर	पॉइंट
1	इंदौर	5647.56
2	सूरत	5519.59
3	नवी मुंबई	5467.89
4	विजयवाड़ा	5270.32
5	अहमदाबाद	5207.13
6	राजकोट	5157.36
7	भोपाल	5066.31
8	चंडीगढ़	4970.07
9	विशाखापट्टनम	4918.44
10	वडोदरा	4870.34

इंदौर ने सब्जी मंडी में बचने वाले कचरे से बायो-सीएनजी गैस बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। यह प्लांट इस तरह के कचरे से इतना सीएनजी बना लेता है कि शहर में 20 सीएनजी बसों को रोजाना ईंधन दिया जा सकता है। नगर निगम ने सार्थक और बैसिक्स जैसे गैर सरकारी संस्थाओं का साथ लेकर शहर के 700 कचरा उठाने वाले लोगों से संपर्क किया। उन्हें प्रशिक्षण और पहचान-पत्र देकर कचरों के वर्गीकरण का काम सौंपा। वे कचरे को प्लास्टिक, कागज, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, शीशा और धातु के मुताबिक अलग-अलग करते हैं। नगर निगम के द्वारा स्थापित वर्गीकरण वाले केंद्र में कचरा इकट्ठा करने और उसके वर्गीकरण की व्यवस्था के साथ फटका और इगलू मशीनें हैं, जिससे यह काम आसान हो जाता है। कचरे के प्रकार के मुताबिक इसे महीन टुकड़ों में काटने की व्यवस्था भी इस केंद्र में है।

जावेद वारसी जामी बताते हैं कि हर रोज प्लास्टिक के 100-100 किलो के ब्लॉक नीमच स्थित सीमेंट प्लांट में भेजे जाते हैं, जहां इसका उपयोग ईंधन के तौर पर होता है। कुछ उन्नत किस्म के प्लास्टिक के टुकड़े मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को भी दिए जाते हैं, जिससे अच्छी सड़कें बनाई जा रही है। इस केंद्र में रोज 45,000 किलो प्लास्टिक को दोबारा उपयोग लायक बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसी केंद्र पर प्लास्टिक से डीजल बनाने की पद्धति भी विकसित की जा रही है और 3000 लीटर कच्चे तेल से 2600 लीटर डीजल और 180 लीटर पेट्रोल भी बनाया जा रहा है।

इंदौर के परमाणु नगर कॉलोनी में 65 ऐसे घर हैं जो कचरे को ठिकाने लगाने के लिए कई नई पहल कर रहे हैं। ऐसे घरों से निकलने वाला कचरा पहले गीले और सूखे कचरे के रूप में छांटा जाता है। सूखे कचरे को एक जगह इकट्ठा कर रिसाइकलिंग के लिए बेच दिया जाता है और गीले कचरे को आपसी सहभागिता के साथ खाद बनाने की प्रक्रिया में डाला जाता है। कॉलोनी के भीतर ही कंपोस्टिंग के जरिए गीले कचरे से खाद बनता है। खाद बनाने के काम में शहर के 29000 और भी घर लगे हुए हैं। इंदौर नगर निगम ने घरों में खाद बनाने पर जोर दिया है और इस तरह 150 टन कचरा रोजाना कम करने का लक्ष्य रखा है। नगर निगम घरों को पचास फीसदी सब्सिडी के साथ कंपोस्टिंग यूनिट प्रदान कर रहा है। गैर सरकारी संगठन स्वाहा के जरिए मोबाइल कंपोस्टर की स्थापना भी की गई है। इस उपकरण के जरिए व्यवसायिक इलाकों से कचरे को इकट्ठा कर गाड़ी में लगे कंपोस्टर के जरिए खाद में बदला जाता है। स्वाहा 8 से 10 टन तक कचरा इकट्ठा कर रोज इसे खाद में बदल रहा है। इन उपकरणों का उपयोग व्यवसायिक इलाकों के अलावा बड़े रहवास और होटल में भी हो रहा है। वारसी कहते हैं कि इंदौर का लक्ष्य आने वाले समय में इस तरह के प्रयासों को आगे और भी बढ़ावा देना है। कचरा इकट्ठा कर एक जगह लाने में परिवहन का एक बड़ा खर्चा है, लेकिन उस कचरे को श्रोत के पास ही निपटान करने से यह खर्च कम किया जा सकता है। इंदौर नगर निगम हर वर्ष 10 प्रतिशत की दर से कचरा निस्तारण पर खर्च में कमी करना चाह रहा है। इंदौर को साफ रखने की लगातार हो रही कोशिश को लेकर इंदौर नगर निगम के अपर आयुक्त रजनीश कसेरा मानते हैं कि कचरे का समुचित निस्तारण अबाध रूप से चलता रहे, इसके लिए इसकी सतत् निगरानी, चल रहे प्रोजेक्ट के प्रति हमारा दृढ़ निश्चय और सबसे जरूरी लोगों की इस सफाई अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है।

● **सुनील सिंह**

अब मप्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कंपनी

मप्र में सरकार की कोशिश है कि दिसंबर 2024 तक भोपाल और इंदौर में हर हाल में मेट्रो रेल का संचालन शुरू हो जाए। इसके लिए सरकार ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिए हैं। वहीं प्रोजेक्ट को गति प्रदान करने के लिए मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड का नाम अब मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में परिवर्तित कर दिया गया है। सरकार को उम्मीद है कि कॉरपोरेशन बनने से मेट्रो प्रोजेक्ट के कार्य में गति आएगी और प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो जाएगा। इसलिए गत दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में कॉरपोरेशन के गठन को हरी झंडी दी गई। कंपनी को बोर्ड बनाए जाने के संबंध में भारत सरकार, मध्यप्रदेश सरकार एवं मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड के बीच 19 अगस्त 2019 को त्रिपक्षीय एमओयू साइन किया गया था।

मुख्यमंत्री चौहान ने बैठक में निर्देश दिए कि इस संबंध में आगामी कार्यवाहियां तत्परता के साथ पूर्ण की जाएं, जिससे प्रदेश के इंदौर-भोपाल शहरों में मेट्रो रेल के कार्य को गति प्रदान कर लक्षित समय 3 से 4 वर्ष में पूर्ण किया जा सके। बैठक में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव वित्त मनोज गोविल, कंपनी के एमडी नीतेश व्यास उपस्थित थे। एमडी नीतेश व्यास ने बताया कि त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश सरकार की प्रोजेक्ट में बराबर भागीदारी के लिए बनाए जा रहे नए बोर्ड में भारत सरकार के 5 संचालक तथा मध्यप्रदेश सरकार के 5 संचालक (प्रबंध संचालक सहित) शामिल होंगे। मध्यप्रदेश सरकार के नगरीय विकास के आयुक्त इसके प्रबंध संचालक होंगे तथा प्रमुख सचिव वित्त, राजस्व, लोक निर्माण विभाग तथा नगरीय विकास विभाग इसके संचालक होंगे। अब ज्वाइंट वेंचर कंपनी में नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम शुरू करेगा।

मेट्रो रेल के निर्माण के लिए भारत सरकार के मेट्रो रेल अधिनियमों के अंतर्गत मेट्रो निर्माण क्षेत्र को मेट्रोपोलिटन क्षेत्र घोषित किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में बैठक में इंदौर एवं भोपाल मेट्रो क्षेत्रों को मेट्रोपोलिटन क्षेत्र घोषित किए जाने संबंधी कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया। प्रदेश से वित्त, पीडब्ल्यूडी, राजस्व व नगरीय प्रशासन के प्रमुख सचिव इसके डायरेक्टर होंगे। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में केंद्र और राज्य की 50-50 हिस्सेदारी होगी। मेट्रो के लिए स्वतंत्र इकाई के रूप में अन्य प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए इस बोर्ड का गठन जरूरी था।

मेट्रो प्रोजेक्ट में अब तक क्या-क्या हुआ

12 जनवरी 2017 को मध्यप्रदेश सरकार की स्वीकृति के बाद भोपाल-इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का काम मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड ने शुरू कर दिया था। भोपाल-इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट को 11 सितंबर 2018 को पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड (पीआईबी) और 3 अक्टूबर 2018 को केंद्रीय कैबिनेट की स्वीकृति मिली। 19 अगस्त 2019 को भारत सरकार, मध्यप्रदेश सरकार और मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ। 14 सितंबर 2019 को इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई। 26 सितंबर 2019 को भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई। 4 नवंबर 2019 को यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने भोपाल मेट्रो के लिए ऋण (कुल प्रस्ताव-3493.34 करोड़ रुपए) मंजूर किया और 10 दिसंबर 2019 को इस संबंध में वित्तीय समझौता हुआ। 2 दिसंबर 2019 को न्यू डेवलपमेंट बैंक ने इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए ऋण (कुल प्रस्ताव- 3 हजार 200 करोड़ रुपए) मंजूर किया। 22 दिसंबर 2017 को मेसर्स डीबी इंजीनियरिंग एंड कंसलटिंग जीएमबीएच (जर्मनी) और उसकी सहयोगी कंपनियों मेसर्स लूईस बर्गर एसएएस (यूएसए) और मेसर्स जियो डाटा इंजीनियरिंग एसपीए (इटली) को प्रोजेक्ट का जनरल कंसलटेंट बनाया गया। 1 नवंबर 2018 को भोपाल और इंदौर मेट्रो के पहले सिविल कार्य के लिए कॉन्ट्रेक्ट एग्रीमेंट किया गया। इसके अनुसार भोपाल मेट्रो के अंतर्गत 247 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से 6.22 किलोमीटर लंबी वायाडक्ट (रेलवे पुल) और इंदौर मेट्रो कार्य के अंतर्गत 228 करोड़ 96 रुपए की लागत से 5.29 किलोमीटर लंबे वायाडक्ट (रेलवे पुल) बनाए जाएंगे।

गौरतलब है कि पूर्व में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने अफसरों को साफ-साफ शब्दों में कह दिया था कि चाहे जो भी हो दिसंबर 2024 तक भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल के दौड़ने के लिए तय मार्गों का कार्य पूरा हो जाना चाहिए। नागपुर में मेट्रो का काम कैसे जल्दी हुआ? वहां जाइए अध्ययन करिए। जमीन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया फटाफट पूरी करें। गुणवत्ता के साथ काम किया जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मेट्रो निर्माण क्षेत्र में काम तेजी से शुरू हो गया है। भोपाल और इंदौर में मेट्रो रूट पर रात-दिन कार्य हो रहे हैं। निर्माणकर्ता कंपनी को प्रशासन ने निर्देश दे दिया है कि तय सीमा से पहले कार्य पूरा होना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि भोपाल और इंदौर में 14,442 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से मेट्रो प्रोजेक्ट पूरा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत भोपाल में 6941 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च होने हैं। वहीं इंदौर में 7500 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए जाने हैं। प्रोजेक्ट के लिए प्रदेश सरकार ने अब 248 करोड़ 96 लाख रुपए तथा केंद्र सरकार ने 245 करोड़ 23 लाख की राशि दी है। प्रोजेक्टर पर अभी तक 138 करोड़ 58 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अभी तक मेट्रो निर्माण का काम धीमी गति से चल रहा था, लेकिन अब काम तेजी से हो रहा है।

● **विकास दुबे**

डिंडौरी ने दिखाया दम

कोरोना संक्रमणकाल में मनरेगा प्रवासी श्रमिकों के लिए वरदान साबित हुआ है। प्रदेश में गत वर्षों की अपेक्षा इन पांच माह में रिकार्ड काम हुआ है और लोगों को काम मिला है। इस दौरान लगभग सभी जिलों में मनरेगा के तहत खूब काम हुए हैं। लेकिन प्रदेश का डिंडौरी जिला ऐसा रहा है जिसमें पिछले एक साल में सबसे अधिक काम हुआ है। डिंडौरी ने प्रदेश के सभी बड़े-छोटे जिलों को पछाड़कर ए-ग्रेड का दर्जा पाया है। दरअसल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जिलों की एक साल की ग्रेडिंग जारी की है। ग्रेडिंग जारी करते हुए डिंडौरी जिले को ए-ग्रेड में रखा है। जबकि भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित तमाम बड़े जिलों को बी, सी ग्रेड से संतोष करना पड़ा है। यानी आदिवासी जिला डिंडौरी ने मनरेगा में सबसे बेहतर काम किया है। मालूम हो कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग हर साल मनरेगा में बेहतर काम करने पर जिलों की ग्रेडिंग जारी करता है। इसके तहत मजदूरों को काम और मजदूरी देने में डिंडौरी, बालाघाट, अशोकनगर, बुरहानपुर सहित अन्य छोटे जिलों ने अच्छा काम किया है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी ग्रेडिंग में ए ग्रेड में एक मात्र डिंडौरी जिले को शामिल किया गया है। यह इस बात का संकेत है कि इस आदिवासी जिले में मनरेगा के तहत खूब काम हुआ है। डिंडौरी जिले ने एक साल में 70 लाख मानव दिवस सृजित किए और 3 हजार 159 परिवारों को 100 दिन तक रोजगार दिया है। मनरेगा के तहत इंदौर सहित 12 जिलों को बी ग्रेड में रखा गया है। इस श्रेणी में उन्हीं जिलों को रखा गया है, जहां मनरेगा के तहत अच्छा काम हुआ है। अशोकनगर, बालाघाट, बुरहानपुर, दमोह, ग्वालियर, हरदा, इंदौर, कटनी, मंडला, मुरैना, शाजापुर और विदिशा जिले में मनरेगा के तहत काम तो हुए पर बेहतर नहीं। इसलिए इन जिलों को बी ग्रेड में रखा गया है।

भोपाल, जबलपुर सहित 28 जिले ऐसे हैं जहां मनरेगा के तहत संतोषजनक काम नहीं हुआ है। इस श्रेणी में कई बड़े जिलें हैं, लेकिन वहां मनरेगा में अधिक काम नहीं हुए हैं। जबलपुर, आगर-मालवा, अलीराजपुर, बड़वानी, बैतूल, भिंड, भोपाल, छिंदवाड़ा, दतिया, धार, गुना, झाबुआ, खंडवा, मंदसौर, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, राजगढ़, रतलाम, सतना, सिवनी, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन और उमारिया जिले में मजदूरों को काम और मजदूरी सही समय पर नहीं मिली है इसलिए सभी जिले सी ग्रेड में है। वहीं प्रदेश के रीवा, सागर सहित 9 जिले ऐसे हैं जहां मनरेगा के तहत सबसे कम काम हुए हैं। छतरपुर, देवास, होशंगाबाद, खरगौन, रायसेन, रीवा, सागर, सीहोर, शहडोल जिले के अधिकारी मनरेगा को लेकर लापरवाह साबित हुए हैं। इन जिलों में मनरेगा के तहत काम ही नहीं हुए इसलिए इन्हें डी ग्रेड दिया गया है। इन जिलों के अधिकारियों को 3 माह में ग्रेडिंग सुधारने के आदेश दिए गए हैं।

गौरतलब है कि मप्र में मनरेगा के तहत पिछले पांच माह में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने के लिए ग्रामों का आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाने में मनरेगा योजना अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकती है। योजना में इस वर्ष 20.50 करोड़ मानव दिवस का लेबर बजट केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत 40 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान है। ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना बनाकर एवं समयबद्ध रूप से कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत प्रति दिवस मजदूरी दर 190 रुपए है, जबकि दूसरे राज्यों महाराष्ट्र में 238 रुपए, गुजरात में 224, राजस्थान में 220 तथा हरियाणा में सर्वाधिक 290 रुपए है। यह दर केंद्र द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रदेश की मनरेगा मजदूरी दर बढ़वाने के लिए आवश्यक 'टाइम एंड मोशन स्टडीज' शीघ्र करवाई जाए। मनरेगा के कार्यों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि कार्य गुणवत्तापूर्ण हों, समय से पूर्ण हो जाएं तथा पूर्ण हुए कार्य उपयोग में आने लगें। मनरेगा कार्यों का सही मूल्यांकन भी सुनिश्चित किया जाए। 79 प्रतिशत जॉब कार्डधारी कार्य कर रहे हैं मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत 79 प्रतिशत जॉब कार्डधारी कार्य कर रहे हैं। यह अच्छा प्रतिशत है। अन्य राज्यों उत्तरप्रदेश में 57 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 72 प्रतिशत, राजस्थान में 73 प्रतिशत तथा बिहार में 36 प्रतिशत सक्रिय जॉब कार्डधारी हैं। हर गांव में शांति धाम पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया ने बताया कि मनरेगा से प्रदेश के छोटे-बड़े प्रत्येक गांव में शांतिधाम बनवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस कार्य की सराहना की। समय पर हुआ मजदूरी का भुगतान प्रदेश में वर्तमान वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत समय पर मजदूरी भुगतान का प्रतिशत भी गत 5 वर्षों की तुलना में सर्वाधिक रहा है। वर्ष 2020-21 में यह 93 प्रतिशत रहा। जबकि वर्ष 2019-20 में समय पर मजदूरी भुगतान का प्रतिशत 84.19 प्रतिशत मात्र था। अब तक हुए 2 लाख 87 हजार कार्य पूर्ण मनरेगा के तहत प्रदेश में अब तक 2 लाख 87 हजार कार्य पूर्ण हो चुके हैं। गत वर्ष इस अवधि तक पूर्ण हुए कार्यों की संख्या एक लाख 64 हजार तक ही सीमित रही।

● **लोकेश शर्मा**

एमआईएस पर आधारित है ग्रेडिंग

मानीटरिंग की यह व्यवस्था मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (एमआईएस) पर आधारित है। जिसमें प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को पूर्व माह तक की प्रगति मानते हुए गणना की जाती है। अर्थात् 31 अगस्त की एमआईएस स्थिति के आधार पर जुलाई माह की रैंकिंग की जाती है। अर्जित लक्ष्यों के हिसाब से अलग-अलग अंक निर्धारित होते हैं। कुल प्राप्तांक 100 के आधार पर जिला पंचायत समिति की ग्रेडिंग रैंकिंग की जाएगी।

मप्र सहित देशभर में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाकर भ्रूण हत्या पर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन उसके परिणाम संतोषजनक नहीं आ रहे हैं। हाल ही में जारी हुई एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक देश में 68 लाख से अधिक बच्चियों को जन्म के पहले ही मार दिया जाएगा।

68 लाख बच्चियां नहीं ले पाएंगी जन्म!

देश में 2030 तक भारत में 68 लाख बच्चियां जन्म नहीं ले सकेंगी, क्योंकि बेटे की लालसा में उन्हें जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाएगा। यह जानकारी 19 अगस्त को जर्नल प्लोस में छपे एक नए शोध में सामने आई है। शोधकर्ताओं ने इसके लिए देशभर में हो रही कन्या भ्रूण हत्या को जिम्मेवार माना है। यह शोध फेंग्किंग चाओ और उनके सहयोगियों द्वारा किया गया है जो कि किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सऊदी अरब से जुड़े हैं।

भारत में कन्या भ्रूण हत्या का इतिहास कोई नया नहीं है। लंबे समय से लड़कों को दी जा रही वरीयता का असर लिंगानुपात पर भी पड़ रहा है। समाज में फैली इस कुरीति ने संस्कृति का रूप ले लिया है। लड़का वंश चलाएगा यह मानसिकता आज भी भारत में फैली हुई है। सिर्फ अनपढ़ और कम पढ़े-लिखे परिवारों में ही नहीं बल्कि शिक्षित लोगों में आज भी यह मानसिकता खत्म नहीं हुई है। 1970 के बाद से तकनीकी ज्ञान ने इस काम को और आसान कर दिया है। इसमें भ्रूण की पहचान बताने वाले अल्ट्रासाउंड सेंटर और नर्सिंग होम की एक बड़ी भूमिका है।

इस शोध में शोधकर्ताओं ने देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया है और उनमें जन्म के समय लिंगानुपात का विश्लेषण किया है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार यह देश की 98.4 फीसदी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिसमें से 9 में स्पष्ट तौर पर बेटे की वरीयता साफ झलकती है। इसमें से उत्तर-पश्चिम के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। यदि पूरे भारत को देखें तो 2030 तक 68 लाख कन्या भ्रूण जन्म नहीं ले पाएंगी। यदि 2017 से 2025 तक का वार्षिक औसत देखें तो यह आंकड़ा 469,000 के करीब है। जबकि 2026 से 2030 के बीच यह बढ़कर प्रति वर्ष 519,000 पर पहुंच जाएगी। शोधकर्ताओं के अनुसार कन्या जन्म में सबसे अधिक कमी उत्तर प्रदेश में होगी, जिसमें अनुमान है कि 2017 से 2030 के बीच 20 लाख बच्चियां जन्म नहीं ले पाएंगी।

हालांकि देश में इसको रोकने के लिए पीसी पीएनडीटी एक्ट अर्थात् प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन एवं दुरूपयोग निवारण अधिनियम-1994) बनाया गया था जिसे 1996 में लागू किया गया था। वर्ष 2003 में इसे संशोधित किया गया था, इसके तहत लिंग निर्धारण करते हुए पहली बार पकड़े जाने पर तीन वर्ष की सजा एवं 50 हजार का जुर्माना लगाने का प्रावधान था। जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर पांच वर्ष की जेल एवं एक लाख रुपए का अर्थ दंड निर्धारित किया गया है। इसके बावजूद देश में अभी भी इस कानून का उल्लंघन जारी है।

यह स्थिति तब तक नहीं सुधरेगी जब तक लोगों की मानसिकता नहीं बदलती। केवल कानून बना देने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। भारतीय समय में मानसिकता के बदलाव की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी है। आज भी लोग बेटियों की जगह बेटों को तरजीह देते हैं। जिसके पीछे की मानसिकता यह है कि बेटों से वंश चलता है, जबकि बेटियां पराया धन होती हैं। जो शादी के बाद पराए घर चली जाती हैं।

देश में आज भी लड़की का मतलब परिवार के लिए अतिरिक्त खर्च होता है। इसमें समाज की भी बहुत बड़ी भूमिका है, बच्चियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों की वजह से भी लोग बेटी के बदले बेटा चाहते हैं। तकनीक की मदद से गर्भ में ही बच्चे के लिंग का पता चल जाता है और बेटी होने पर गर्भपात करा दिया जाता है। ऐसे में कानून के साथ-साथ मानसिकता में भी बदलाव लाने की जरूरत है, जिससे वास्तविकता में बेटियों को बराबरी का हक दिया जा सके।

जनगणना के आंकड़ों के आधार पर आईएमआर का विश्लेषण करने पर शिशु की मौत का आंकड़ा भी काफी चौंकाने वाला है। आंकड़ों के विशेषज्ञ और विकास संवाद के रिसर्च एसोसिएट अरविंद मिश्रा ने वर्ष 2000 से 2018 तक के आईएमआर और सेंसस के आंकड़ों की गणना करके पाया कि इस दौरान 17,68,500 शिशुओं की मौत हुई है। मध्यप्रदेश में शिशुओं की यह हालत तब है जब सरकार इन्हीं वर्षों में विकास के तमाम दावे करती आई है। प्रदेश सरकार ने कृषि विकास दर (18-20 प्रतिशत) और आर्थिक विकास दर (करीब 10-12 प्रतिशत) को हमेशा राष्ट्रीय औसत से अधिक रहने का दावा किया है।

● **राजेश बोरकर**

16 साल में 17 लाख शिशुओं की मौत

रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा मई 2020 में सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के जारी आंकड़ों से यह तय हो गया कि मध्यप्रदेश लगातार 15वीं बार शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) में सबसे अव्वल रहा। 2018 के आंकड़ों को लेकर जारी यह ताजा रिपोर्ट बताती हैं कि 2017 के मुकाबले एक अंक की बढ़ोतरी के साथ मध्यप्रदेश का आईएमआर 48 हो गया, यानी प्रति हजार जन्म पर 48 शिशुओं की मौत। वर्ष 2004 के बाद से ही मध्यप्रदेश की स्थिति शिशु मृत्यु दर के मामले में देश में सबसे खराब रही है। वर्ष 2017 के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में यह दर एक अंक और शहरी इलाकों में 4 अंक बढ़ी है जो कि चौंकाने वाली है। पिछले 15 वर्षों में इस दर में लगातार कमी आ रही थी और 2016 और 2017 में दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। ऐसा पहली बार हुआ कि आईएमआर में वृद्धि दर्ज की गई है।

कई नौकरी, एक परीक्षा

युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राष्ट्रीय भर्ती नीति (एआईआर) को मंजूरी दे दी है जिससे देश के करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा। राष्ट्रीय भर्ती संस्था कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी जिसका करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा। रेलवे, बैंकिंग और एसएससी की प्राथमिक परीक्षा के लिए अलग-अलग परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन तीनों के लिए एक एजेंसी बनाई जाएगी। एक ही आवेदन, एक ही शुल्क, एक ही परीक्षा होगी। इस परीक्षा का स्कोर तीन साल के लिए मान्य होगा। अभी तक केवल दो भाषाओं में ही परीक्षा देने की इजाजत थी, लेकिन इसके जरिए परीक्षार्थी 12 भाषाओं में परीक्षा दे सकते हैं। अभी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी केवल तीन संस्थाओं के लिए परीक्षा लेगी, लेकिन भविष्य में सभी केंद्रीय संस्थाओं की परीक्षा यही एजेंसी लेगी। इन तीन संस्थाओं में लगभग ढाई करोड़ विद्यार्थी भाग लेते हैं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि एनआरए साल में दो बार ही सीईटी (कॉमन एलजिबिलिटी टेस्ट) का आयोजन करेगी। अभी रेलभर्ती बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन तथा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली आरंभिक परीक्षाओं को भी इसी में मर्ज किया जाएगा। इन सभी परीक्षाओं में ग्रुप-बी और सी के 1.25 लाख पदों के लिए करीब ढाई करोड़ उम्मीदवार बैठते हैं। लेकिन अभी उन्हें हर परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा भी अलग-अलग देनी पड़ती है। कार्मिक राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि नए फैसले के मुताबिक सीईटी में सफल उम्मीदवारों की एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी। जो कि तीन साल तक मान्य रहेगी। हालांकि जो भी उम्मीदवार अपना स्कोर बेहतर करना चाहेंगे वे लोग फिर से परीक्षा में बैठ सकते हैं, ये विद्यार्थियों के लिए बड़ा ऐलान होगा, लेकिन अभी उन्हें हर परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा भी अलग-अलग देनी पड़ती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि देश में सरकारी नौकरियों के लिए 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं। सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को बहुत सी परीक्षा देनी होती थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है।

नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन के बाद नौकरी के लिए उम्मीदवारों को अलग-अलग आरंभिक परीक्षाओं से मुक्ति मिलेगी, साथ ही परीक्षाओं की तारीखें एकसाथ आ जाने से एक परीक्षा छोड़नी पड़ती थी, जो अब नहीं होगी। परीक्षा केंद्र अलग-अलग शहरों में पड़ते थे लेकिन अब यह समस्या भी खत्म हो जाएगी। परीक्षाओं के लिए अब जिला मुख्यालय पर एक केंद्र होगा, साथ ही आपको दूर नहीं जाना होगा। विद्यार्थियों को एक ही परीक्षा के लिए फीस भरनी होगी। जिससे विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली यात्रा के खर्च में भी कमी आएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग और आईबीपीएस के प्रतिनिधि संचालक मंडल में शामिल होंगे, इसके साथ ही अभी परीक्षा के आवेदन से लेकर रिजल्ट आने में 12-18 महीने लगते हैं, जो कि अब सीईटी से यह समय घटेगा। जो भी विद्यार्थी ग्रुप बी और सी की जॉब के लिए तैयारी करते हैं उनको लाभ होगा। आपको बता दें कि आरंभिक परीक्षा की अहर्ताएं एक जैसी ही होती हैं, लेकिन हर बोर्ड का अलग-अलग पैटर्न होने से उम्मीदवारों को अलग-अलग प्रकार से परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक ही परीक्षा के होने से एक ही किस्म की तैयारी अब करनी होगी। पहले केंद्र सरकार ने एमबीबीएस में एडमिशन के लिए भी एक टेस्ट किया जो कि सफल रहा। आपको बता दें कि पहले हर राज्य अपनी-अपनी परीक्षा करवाता था। लेकिन बाद में प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के लिए एक एजेंसी एनटीए का गठन किया गया, इससे पहले यह काम सीबीएसई या अन्य एजेंसियों को करना पड़ता था।

एनआरए वर्ष में दो बार ऑनलाइन माध्यम से सीईटी आयोजित करेगा। प्रतिभागियों का पंजीकरण, रोल नंबर, एडमिट कार्ड, अंक पत्र, मेधा सूची आदि ऑनलाइन माध्यम से संचालित होंगी। सीईटी अनेक भाषाओं में उपलब्ध होगी। यह देश के विभिन्न हिस्सों से लोगों को परीक्षा में बैठने और चयनित होने के समान अवसर प्राप्त करना सुविधाजनक बनाएगी। सीईटी बहुविकल्प प्रश्नों पर आधारित परीक्षा होगी और इसका स्कोर कार्ड 3 वर्षों तक मान्य होगा। इसके लिए देश के प्रत्येक जिले में एक परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसमें 117 आकांक्षी जिले शामिल हैं। प्रारंभिक योजना देशभर में 1000 परीक्षा केंद्र स्थापित करने की है। इससे गरीब पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को राहत मिलेगी। वर्तमान में, उम्मीदवारों को बहु-एजेंसियों द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न परीक्षाओं में भाग लेना होता है। परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त उम्मीदवारों को यात्रा, रहने-ठहरने और अन्य पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। सीईटी जैसी एकल परीक्षा से काफी हद तक उम्मीदवारों पर वित्तीय बोझ कम होगा।

● **प्रवीण कुमार**

भर्ती शुल्कों से भी मिलेगी राहत

उम्मीदवारों को भिन्न-भिन्न भर्ती एजेंसियों को शुल्क का भुगतान करना पड़ता है और इन परीक्षाओं में भाग लेने के लिए लंबी दूरियां तय करनी पड़ती हैं। इन अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं से उम्मीदवारों के साथ-साथ संबंधित भर्ती एजेंसियों पर भी बोझ पड़ता हैं। इसमें बार-बार होने वाले खर्च, कानून और व्यवस्था-सुरक्षा संबंधी मुद्दे और परीक्षा केंद्रों संबंधी समस्याएं शामिल हैं। औसतन, इन परीक्षाओं में अलग से 2.5 करोड़ से 3 करोड़ उम्मीदवार शामिल होते हैं। साझी पात्रता परीक्षा (सीईटी) उम्मीदवार एक सामान्य योग्यता परीक्षा में केवल एक बार शामिल होंगे तथा उच्च स्तर की परीक्षा के लिए किसी या इन सभी भर्ती एजेंसियों में आवेदन कर पाएंगे। एनआरए के तहत एक परीक्षा में शामिल होने से उम्मीदवारों को कई पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा।

पीला मोजेक का कहर

प्रदेश में 10 फीसदी नुकसान

सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन (सोपा) के कार्यकारी निदेशक डीएन पाठक के मुताबिक हमारे त्वरित सर्वेक्षण के अनुसार इंदौर, देवास, उज्जैन, धार, सीहोर, हरदा, शाजापुर, मंदसौर और नीमच में फसल को सबसे ज्यादा 10 फीसदी तक नुकसान हुआ है। शुरुआत में बोई गई फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचा। महाराष्ट्र और राजस्थान में अब तक इस वायरस का असर नहीं है। सोयाबीन की पत्तियां जल्द पीली होने पर फली आने में देरी और दाने छोटे रहने से फसल की कुल उत्पादकता पर विपरीत असर की आशंका है। कृषि मंत्री पटेल ने भरोसा दिलाया कि किसानों को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। जिन्होंने अभी तक बीमा नहीं कराया है वे प्रीमियम जमा कर बीमा कराएं। फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कराया जाएगा। कलेक्टरों को निर्देश दिए जा चुके हैं। किसानों को बीमा के साथ राजस्व परिपत्र पुस्तक के प्रावधानों के तहत भी क्षतिपूर्ति दी जाएगी।

प्रदेश में इस बार अनुकूल मौसम को देखते हुए किसानों ने रिकॉर्ड 58.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की बोवनी की थी। इसके कारण उम्मीद जताई जा रही थी कि गेहूं की तरह इस तिलहन फसल का भी बंपर उत्पादन होगा, लेकिन फसल येलो मोजेक वायरस की चपेट में आ गई है। अधिकांश जगह सोयाबीन के पत्ते पीले पड़ गए और पौधे सूख चुके हैं। कई जगह अफलन (फली न लगना) की शिकायतें सामने आ रही हैं। मालवा, निमाड़, महाकौशल सहित अन्य क्षेत्रों में करीब 25 फीसदी तक फसल के प्रभावित होने की आशंका है। नरसिंहपुर में 40, दमोह में 10, सिवनी में पांच फीसदी तक नुकसान की बात सामने आई है। प्रदेश में इस बार कुल 141 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से ज्यादा में खरीफ फसलों की बोवनी की गई है। बारिश में लंबा अंतराल और तापमान अधिक होने के कारण सोयाबीन की फसल प्रभावित हुई है। सरकार ने नुकसान का आंकलन करने के लिए कलेक्टरों को निर्देश दे दिए हैं। वहीं, दूसरी ओर अभी तक किसानों का फसल बीमा नहीं हो पाया है। बीमा के लिए कंपनी तय करने में समय लगने के कारण अब प्रीमियम जमा करने की समयसीमा 17 अगस्त से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है।

फसल खराब होने की सूचनाओं को देखते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने भोपाल के पास बैरसिया विधानसभा क्षेत्र के गांव तारा सेवनिया और बगोनिया में निरीक्षण किया। यहां सोयाबीन की 100 फीसदी तक फसल बर्बाद हुई है। सोयाबीन की फलियों में दाने नहीं हैं।

पूर्व कृषि संचालक डॉ. जीएस कौशल ने बताया कि येलो मोजेक वायरस का असर सोयाबीन में बड़े पैमाने पर नजर आ रहा है। मालवा, निमाड़ और महाकौशल से फसल प्रभावित होने की सूचनाएं आ रही हैं। रतलाम जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष डीपी धाकड़ ने बताया कि पूरे क्षेत्र में सोयाबीन की फसल येलो मोजेक, सफेद कीट सहित अन्य बीमारियों से प्रभावित हुई है। सोयाबीन इतना बढ़ गया कि उसमें फलियां ही नहीं लगीं। बीमा नहीं हुआ तो बड़ा नुकसान होगा किसानों के सामने समस्या यह भी है कि खरीफ फसलों का बीमा अभी तक नहीं हो पाया है। दरअसल, कृषि विभाग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए बीमा कंपनी ही समय पर तय नहीं कर पाया। इसके कारण फसलों का बीमा ही नहीं हुआ। यदि बीमा कंपनियां अब खराब हो चुकी फसलों का बीमा नहीं करती हैं तो किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि, विभागीय अधिकारियों का कहना है कि ऐसी स्थिति नहीं है। किसान 31 अगस्त तक बीमा करा सकते हैं।

मालवा-निमाड़ में सोयाबीन की फसलों में दो तरह के कीट सफेद मक्खी (व्हाइट फ्लाई) और तनाछेदक मक्खी (स्टेम फ्लाई) का प्रकोप हो रहा है। ये दोनों कीट सोयाबीन की पत्तियां और तना दोनों को खोखला कर रहीं हैं। सोयाबीन पकने से पहले ही पत्ते पीले पड़ रहे हैं। इस साल मालवा-निमाड़ में 29.80 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बोवनी हुई है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार अधिकांश रकबा इंदौर, धार, उज्जैन, रतलाम, देवास, खंडवा, शाजापुर, नीमच जिले में है। कीट के प्रकोप का आंकलन अभी नहीं हुआ है। किसानों का कहना है कि इंदौर में कुछ इलाकों में 10 से 50 फीसदी तक असर हुआ है। वहीं देवास में करीब 50 फीसदी फसलों पर असर है। इंदौर में कलेक्टर मनीष सिंह ने गत दिनों कृषि वैज्ञानिकों के साथ प्रभावित गांवों का दौरा किया। सबसे कम असर बड़वानी और खरगोन जिले में है।

कोरोना संकट में किसानों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, किसी तरह किसानों ने कर्ज लेकर उड़द की बुवाई की थी, अब पीला मोजेक रोग की वजह से ज्यादातर किसानों की उड़द की फसल पीली पड़ गई है। मध्यप्रदेश के सतना जिले में लक्ष्य से 5 फीसदी ज्यादा बोवनी करने के बाद उड़द के पौधों की पत्तियां पीली पड़ गईं। दूर से खेत का पीलापन नजर आने लगता है। सतना जिले में कोई ऐसा गांव नहीं मिला जहां की उड़द के पौधों की पत्तियां पीली न रही हों। जिला मुख्यालय से 50 किमी दूर ग्राम गहिरा के 22 वर्षीय युवा किसान विपिन बताते हैं, पिछले साल भी यही हुआ था। इस साल तो सलाह पर दवा भी डाली। इसमें 2700 से लेकर 2800 रुपए तक खर्च भी किए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। प्रशासनिक अधिकारियों से मिला भी लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। रैगांव विधानसभा के गांव मसनहा के किसान राम सिंह बागरी ने बताया, उड़द की खेती पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। एक तो बारिश नहीं हुई, फसल पिछड़ी। बारिश हुई तो लेट हुई जिससे जो फसल बो गई थी वो भी बर्बाद हो गई। अब किसी तरह कर्ज लेकर खेती कर रहे हैं तो प्रकृति मार रही है। कोई अन्य व्यवसाय नहीं है। तो खेती ही करनी पड़ रही है। इस साल सतना जिले में उड़द की फसल की बोवनी लक्ष्य से 5 फीसदी से भी ज्यादा हुई है।

● **राकेश ग्रोवर**

We Deal in Pathology
& Medical Equipments
Anu Sales Corporation
Add : Ground Floor, 17/1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
Mob. : 9329556524, 9329556530, E-mail : ascbhopal@gmail.com

अलविदा प्रणब दा...

संघ के खिलाफ भी संघ के साथ भी

भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले प्रणब मुखर्जी के आरएसएस से रिश्ते बनते बिगड़ते रहे हैं। एक कांग्रेसी होने के नाते प्रणब मुखर्जी भी संघ के कटु आलोचक रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें वो प्रणब दा ही थे जिन्होंने सांप्रदायिकता और हिंसा में संघ की भूमिका पर सवाल उठाए थे। उन्होंने ही संघ को राष्ट्र विरोधी बताया था और कहा था कि ऐसे किसी भी संगठन की देश को जरूरत नहीं। लेकिन शायद समय के साथ प्रणब दा ने ये सीख लिया था कि हर जगह कटुवचन बोलना सही नहीं, कई बार समय के बहाव से साथ भी बहना जरूरी होता है। ऐसी ही सोच ने उन्हें कभी धर्म संकट में नहीं पड़ने दिया। 2018 में प्रणब मुखर्जी को आरएसएस के संघ शिक्षा वर्ग-तृतीय के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होने का न्यौता मिला। उस समय की इस खबर ने सबको चौंका दिया और इससे भी चौंकाने वाली बात ये रही कि प्रणब दा ने ये न्यौता स्वीकार भी कर लिया। नागपुर में हो रहे इस कार्यक्रम में शामिल होने से पहले बहुत तरह के कयास लगाए गए लेकिन प्रणब दा ने भी साबित कर दिया कि वह राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने ऐसी स्पीच दी कि उससे उनकी पार्टी कांग्रेस को भी बुरा नहीं लगा और संघ भी खुश हो गया। हालांकि विरोध के भी कई स्वर उठे लेकिन इसका प्रणब दा पर रत्ती भर फर्क ना दिखा।

प्रणब मुखर्जी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर भी रहे और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित भी हुए लेकिन एक बात का मलाल ताउम्र रह ही गया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपने लंबे राजनीतिक जीवन में दो बार प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए और सार्वजनिक तौर पर भी इसे करीब-करीब स्वीकार करने में गुरेज नहीं किया। केवल वो ही नहीं बल्कि गवर्नेंस के उनके लंबे अनुभव और राजनीतिक समझ के कायल नेताओं और नौकरशाहों के बीच एक टैगलाइन भी मशहूर रही है- सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्रियों में से एक जो भारत को कभी नहीं मिला।

कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आने वाले प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में बैठे-बैठे अपनी पुरानी पार्टी का घोर पतन भी देखा और कट्टर राजनीतिक विरोधी विचारधारा की सरकार के साथ भी उतनी ही शिद्दत से काम किया। मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के बाद बेशक कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति भवन पहुंचाया, लेकिन जो सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया वैसा किसी प्रधानमंत्री ने किसी राष्ट्रपति को दिया हो, ऐसा देखने को तो नहीं ही मिला है।

2014 में यूपीए शासन के 10 साल हो चुके थे और वो चुनावी साल रहा। गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्र के नाम संबोधन में बाकी बातों के बीच तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का एक बात पर खास जोर दिखा- मजबूत सरकार। प्रणब मुखर्जी ने लोगों से वोट देकर बहुमत वाली सरकार चुनने की अपील की थी। गठबंधन की सरकारों से शायद उनका मोहभंग हो चुका था। यूपीए की गठबंधन सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे। प्रणब मुखर्जी को समझ आ चुका था कि देश के लिए बहुमत की सरकार की अहमियत क्या होती है।

कांग्रेस नेतृत्व और दूसरे साथी नेताओं ने भले ही प्रणब मुखर्जी को कितना भी निराश क्यों न किया हो, देशवासियों ने राष्ट्र के नाम संबोधन के संदेश को महामंत्र की तरह लिया और भाजपा की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बहुमत से जनादेश देते हुए केंद्र में मजबूत सरकार को भेज दिया और नरेंद्र मोदी गुजरात से पहुंचकर दिल्ली में प्रधानमंत्री बने। चुनाव नतीजे आने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन प्रणब मुखर्जी से मिलने पहुंचे तो इतनी गर्मजोशी से स्वागत किया जैसे देश के मतदाताओं को धन्यवाद दे रहे हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रणब मुखर्जी के उस संबोधन के प्रति आभार जताया जिसमें राष्ट्रपति ने मजबूत सरकार की अपील की थी।

2019 के चुनाव के दौरान भी ऐसा ही देखने को मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से बहुमत वाली मजबूत सरकार के लिए वोट करने की अपील की। तब प्रधानमंत्री मोदी ने समझाया कि जब बहुमत की मजबूत सरकार का प्रधानमंत्री दुनिया में कही भी जाता है तो उसे भारत की मजबूती के साथ हाथोंहाथ लिया जाता है और वैसे ही गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। बिलकुल ही विरोधी राजनीतिक विचारधारा की पृष्ठभूमि से आने वाले प्रणब मुखर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोई अलग व्यवहार करना तो दूर, दोनों के बीच ऐसा रिश्ता कायम हुआ जिसकी मिसाल कम ही मिलती है।

1969 में राजनीति में प्रवेश करने वाले प्रणब दा उस समय तक कांग्रस में अपनी अच्छी खासी धाक बना चुके थे। सबका यही अनुमान था कि इंदिरा गांधी के बाद प्रणब दा ही प्रधानमंत्री पद के असल दावेदार होंगे लेकिन राजीव गांधी से ज्यादा अनुभवी होने के बाद भी प्रणब दा को प्रधानमंत्री पद नसीब नहीं हुआ। राजीव गांधी के दौर में कांग्रेस से दूरियां बढ़ने और पीवी नरसिम्हा राव के समय दोबारा से कांग्रेस में अपनी जगह पक्की करने वाले प्रणब दा को सोनिया गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस से कुछ उम्मीदें दिखीं। लोगों को लगा कि सोनिया अगर खुद प्रधानमंत्री नहीं बनतीं तो इस बार प्रणब दा का नंबर पक्का है। मगर सभी अनुमान एक बार फिर से गलत साबित हुए और इस बार डॉ. मनमोहन सिंह ने बाजी मार ली। अंत में प्रणब दा को 2012 में कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया और वह राष्ट्रपति चुने गए। इस तरह उन्हें अपनी कर्तव्यनिष्ठा का फल मिला। वित्त मंत्री से लेकर विदेश मंत्री तक का पदभार संभालने वाले प्रणब मुखर्जी पहले ऐसे वित्त मंत्री थे जिन्होंने 5 बार देश का बजट पेश किया। पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस में एक क्लर्क की नौकरी से देश के सबसे शीर्ष पद तक पहुंचने का सफर ही उनकी मेहनत की कहानी कहता है।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

भोपाल विकास प्राधिकरण

विज्ञापन क्रमांक 4283/राजस्व/20

आवेदन पत्र प्राप्ति दिनांक 01.09.2020 से 15.09.2020 तक

दिनांक 29.08.2020

महालक्ष्मी परिसर (पुल बोगदा) में ऑफर के माध्यम से प्रकोष्ठ विक्रय हेतु उपलब्ध

रेरा पंजीकृत

ऑफर फार्म रू.500/-

अधिकतम ऑफर मूल्य ही स्वीकार किये जायेंगे

ऑफर खुलने की दिनांक एवं समय 17.09.2020 दोपहर 12.00 बजे खोले जायेंगें।

क्र.	प्रकोष्ठों/ इकाईयों का विवरण	रिक्त प्रकोष्ठों की संख्या	ब्लॉक नंबर	प्रकोष्ठ संख्या एवं नंबर	प्रकोष्ठ क्रमांक एवं तल	प्रकोष्ठों/ इकाईयों का उपयोग	क्षेत्रफल सुपर बिल्टअप वर्गमीटर में	आरक्षण की श्रेणी यदि आरक्षित हो	वर्तमान कलेक्टर गाईड लाईन 2019-20	प्रकोष्ठों/ इकाइयों का आरक्षित मूल्य रू. (प्रति भवन)	पट्टे लीज पर या भूमि स्वामी अधिकारी पर व्ययन	पट्टे लीज के प्रकरण में वार्षिक पट्टा भाड़ा रू. प्रति प्रकोष्ठ	अमानत राशि मूल्य की 10 प्रतिशत रू.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	सीनियर एम.आई.जी. (3 बी.एच.के.)	09	10	01	1002 दसवां तल	आवासीय	161.47	अनारक्षित	17300/-	43,75,600/-	लीज पर	8,203	4,37,560/-
			11	04	1001,1002, 1003, 1004 दसवां तल	आवासीय	161.47	अनारक्षित	17300/-	43,75,600/-	लीज पर	8,203	4,37,560/-
			12	04	1001,1002,1003 1004 दसवां तल	आवासीय	161.47	अनारक्षित	17300/-	43,75,600/-	लीज पर	8,203	4,37,560/-
2	एम.आई.जी. (2 बी.एच.के.)	09	15	04	1001,1002, 1003, 1004 दसवां तल	आवासीय	135.87	अनारक्षित	17300/-	36,45,204/-	लीज पर	6,902/-	3,64,520/-
			16	04	1001,1002,1003, 1004, दसवां तल	आवासीय	135.87	अनारक्षित	17300/-	36,45,204/-	लीज पर	6,902/-	3,64,520/-
			17	01	1002 दसवां तल	आवासीय	135.87	अनारक्षित	17300/-	36,45,204/-	लीज पर	6,902/-	3,64,520/-

भुगतान हेतु नियम एवं शर्तें-

1. प्रकोष्ठ पर भारित सम्पत्ति कर एवं पुनिर्धारण शुल्क (भू-राजस्व प्रीमियम राशि) रजिस्ट्री पृथक से देय होगा।
2. प्रकोष्ठ पर भारित रहवासी समिति शुल्क तय अनुसार रजिस्ट्री पूर्व अंतिम किस्त में पृथक से देय होगा।
3. जल प्रदाय स्ट्रीट लाईट एवं साफ-सफाई संचालन मद में 24 माह की राशि अग्रिम रजिस्ट्री से पूर्व पृथक से देय होगी ।
4. सम्पत्ति लीज पर विक्रय हेतु है । 5. जी.एस.टी. एवं अन्य लागू टेक्स शासन नियमानुसार देय होगें ।
6. किश्तो का निर्धारण निम्नानुसार देय होगा-

1. पंजीयन राशि 10 प्रतिशत प्रथम। 2. प्रथम किस्त 50 प्रतिशत (आर.सी.सी. एवं चुनाई कार्य पूर्ण), 3. द्वितीय किस्त 10 प्रतिशत (फ्लोरिंग बाह्य प्लास्टर एवं खिड़की दरवाजा आदि), 4. तृतीय किस्त 10 प्रतिशत (आंतरिक विद्युतीकरण एवं लिफ्ट की संस्थापना), 5. चतुर्थ किस्त 5 प्रतिशत (सेनेट्री, जलप्रदाय आदि कार्य), 6. पांचवी किस्त 5 प्रतिशत (बाह्य विद्युतीकरण कार्य पूर्ण होने पर), 7. छठवीं एवं अंतिम किस्त 5 प्रतिशत एवं अन्य देय राशियां (कार्य पूर्ण होने पर)

रेरा पंजीयन क्र. P- BPL-17-306

संपदा अधिकारी
भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें-

प्रगति भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन- I, एम.पी. नगर, भोपाल 462011 (म.प्र.)

दूरभाष : 0755-2701836/37/38, 2557273 / 2557276 Email : info@bda.org.in www.bda.org.in

सहायक यंत्री, अजित सिंघई जी मो. 8109581725 , उपयंत्री, अनिल जैन मो. 9896628038

बेदम दावे कमजोर दांव

मप्र में 27 सीटों पर होने वाला उपचुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, बल्कि यह चुनाव सत्ता का भविष्य तय करेगा। चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा भले ही नहीं की है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने मोर्चा संभाल लिया है। खासकर भाजपा और कांग्रेस जीत के बड़े-बड़े दावे कर रही हैं। लेकिन फिलहाल उनके दावों में दम नहीं है। क्योंकि कोरोना संक्रमण के कारण मतदाता अभी तक अपने भावों को प्रकट नहीं कर पाया है। इसलिए पार्टियों के दांव कमजोर साबित हो रहे हैं।

● राजेंद्र आगाल

कोरोना संक्रमण की दहशत के बीच मप्र में उपचुनाव का घमासान शुरू हो गया है। ये उपचुनाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद दिग्विजय सिंह के साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के राजनीतिक भविष्य की दिशा और दशा तय करेंगे। खासकर कांग्रेस से भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया की अग्निपरीक्षा होने वाली है। क्योंकि जिन 27 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, उनमें से 16 सीटें ग्वालियर-चंबल अंचल की हैं। यह अंचल सिंधिया का गढ़ है। यही नहीं, 16 में से 15 पूर्व विधायक तो सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं। ऐसे में कम से कम इन 15 पूर्व विधायकों को जिताने की जिम्मेदारी सिंधिया पर है। हालांकि दोनों पार्टियां सभी 27 सीटें जीतने का दावा कर रही हैं। लेकिन उनके दावे बेदम हैं और अभी तक जो भी चुनावी दांव चले गए हैं वे कमजोर नजर आ रहे हैं।

उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस में मैदानी तैयारी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने अपने सर्वे के बाद दावा किया है कि भाजपा एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। वहीं भाजपा का दावा है कि उपचुनाव हुए तो कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। किसके दावे सही होते हैं यह तो वक्त ही बताएगा। उधर, 21 अगस्त को चुनाव आयोग ने कोरोनाकाल में चुनाव की गाइडलाइन जारी कर यह संकेत दे दिया है कि मप्र की 27 विधानसभा सीटों पर अक्टूबर के मध्य तक हर हाल में उपचुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग से मिले संकेत के बाद प्रदेश में भाजपा, कांग्रेस और बसपा सहित अन्य पार्टियों ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। अभी तक की तैयारियों का आंकलन किया जाए तो भाजपा कांग्रेस से काफी आगे नजर आ रही है। इसकी वजह यह है कि भाजपा में लगभग 25 प्रत्याशी तय हैं। जबकि कांग्रेस को अभी सभी 27 प्रत्याशी तय करने हैं। चुनाव आयोग के अनौपचारिक ऐलान के बाद भाजपा और कांग्रेस तय समय पर चुनाव के लिए उत्साहित हैं। गौरतलब है कि मप्र के दो विधायकों के निधन और कांग्रेस के 25 बागी विधायकों के इस्तीफे से रिक्त विधानसभा की कुल 27 सीटों पर एकसाथ उपचुनाव होने हैं। जिन सीटों पर चुनाव होने हैं वे हैं- जौरा, आगर (अजा), ग्वालियर, डबरा (अजा), बमोरी सुरखी, सांची (अजा), सांवेर (अजा), सुमावली, मुरैना, दिमनी, अंबाह (अजा), मेहगांव, गोहद (अजा), ग्वालियर (पूर्व), भांडेर (अजा), करैरा (अजा), पोहरी, अशोक नगर (अजा), मुंगावली, अनूपपुर (अजजा), हाटपिपल्या, बदनावर, सुवासरा, बड़ामलहरा, नेपानगर, मांधाता आदि।

शुभ मुहूर्त कितना प्रभावी

भाजपा ने उपचुनाव प्रचार का श्रीगणेश गणेश चतुर्थी के दिन ग्वालियर से किया। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि शुभ मुहूर्त में शुरू हुआ चुनावी प्रचार भाजपा को बड़ी विजय दिलाएगा। हमारे देश में आमतौर पर किसी अच्छे और शुभ कार्य करने के लिए श्री गणेशाय नमः लिखा जाता है। ऐसे में गणेश चतुर्थी से शुरू हुआ भाजपा का चुनावी अभियान वैसे तो जोरदार रहा, क्योंकि इस दिन महल विरोधी रहे लगभग सभी नेता महल के साथ नजर आए। यही नहीं भाजपा के लिए गणपति बप्पा ने वर्षों पुरानी 'कसक' दूर कर दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के रजवाड़े में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 'चुनावी मिलन' भी किया। तीन दिनों तक ग्वालियर-चंबल अंचल में चले महासदस्यता अभियान के दौरान 72 हजार से अधिक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ली। हालांकि कांग्रेस ने अगले ही दिन क्षेत्र में रैली कर भाजपा के महासदस्यता अभियान को फर्जी बता दिया।

कई विधानसभा सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला

मध्य प्रदेश में होने वाली उपचुनाव की जंग कई विधानसभा सीटों पर त्रिकोणीय होगी। ये सीटें ग्वालियर-चंबल अंचल की हैं। उन सीटों पर भाजपा, कांग्रेस और बसपा के बीच मुकाबला होगा। बहुजन समाज पार्टी ने ग्वालियर-चंबल की 8 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। बसपा मध्यप्रदेश में उपचुनाव के लिए पूरी ताकत से जोर आजमाइश करेगी। बसपा ने ग्वालियर-चंबल अंचल की 8 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। इनमें से ज्यादातर सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इस सीटों पर बसपा तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव में जोर आजमाइश करेगी। ग्वालियर-चंबल अंचल में बसपा के वोटों की अच्छी-खासी संख्या है। 2018 के चुनावों में यहां की ज्यादातर सीटों में बसपा के प्रत्याशी दूसरी पॉजीशन पर रहे थे। ऐसे में लड़ाई त्रिकोणीय होने की पूरी संभावना है। घोषित की गई सीटों में मुरैना की जौरा सीट से सोनाराम कुशवाहा पूर्व विधायक बसपा, मुरैना से राम प्रकाश राजोरिया, मुरैना की अंबाह से भानु प्रताप सिंह सखवार, भिंड की मेहगांव सीट से योगेश मेघसिंह नरवरिया, भिंड की गोहद से जसवंत पटवारी, ग्वालियर की डबरा से संतोष गौड़, शिवपुरी की पोहरी से कैलाश कुशवाहा और शिवपुरी की करैरा सीट से राजेंद्र जाटव चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसमें बसपा की भूमिका कांग्रेस के वोट बैंक को सेंध लगाने वाली हो सकती है। जिन सीटों की घोषणा की गई है, इनमें ज्यादातर सीटों पर 2018 में बसपा के उम्मीदवार सेकंड पॉजीशन पर रहे थे। अब कांग्रेस के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नहीं हैं। ऐसे में इन चुनावों में बसपा भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा पहुंचाती दिख रही है।

मप्र के इतिहास में पहली बार ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है, जहां भाजपा और कांग्रेस चुनाव को किसी महायुद्ध की तरह लड़ रहे हैं। इसलिए दोनों पार्टियों का फोकस ग्वालियर-चंबल अंचल में सबसे अधिक है। इसकी वजह यह है कि यहां सबसे अधिक सीटें हैं। जो पार्टी इस क्षेत्र में बाजी मारेगी, वह सत्ता के करीब पहुंच सकती है। गौरतलब है कि देश की राजनीति में ग्वालियर क्षेत्र को मध्यप्रदेश कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। माधवराव सिंधिया ने ग्वालियर और आसपास के जिलों में कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। सिंधिया के निधन के बाद उनके पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया इस क्षेत्र में कांग्रेस को आगे बढ़ाते रहे। लेकिन अब कांग्रेस से बगावत के बाद सिंधिया के पास भाजपा से राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश की सत्ता में आधी हिस्सेदारी भी आ गई है।

पहली बार विरोध का सामना

ग्वालियर-चंबल अंचल में महल का प्रभाव इस कदर रहा है कि उसकी छत्रछाया में कांग्रेस के कई नेता पले-बढ़े हैं। अभी तक इस क्षेत्र में महल ही कांग्रेस के टिकट तय करता रहा है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में जाने से क्षेत्र का माहौल पूरी तरह बदल गया है। 22 अगस्त को भाजपा के महासदस्यता अभियान में शामिल होने जब सिंधिया ग्वालियर पहुंचे तो उनका जगह-जगह विरोध भी हुआ। यह पहला अवसर था जब सिंधिया को अपने क्षेत्र में विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन सिंधिया के लिए सबसे बड़ी बात यह रही कि उनके साथ शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और वीडी शर्मा सहित पूरी भाजपा खड़ी रही। ग्वालियर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जब सिंधिया को शिवराज सिंह के साथ देखा तो उनका विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया।

ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए है : कमलनाथ

उपचुनाव को लेकर प्रदेश में शुरू हुए राजनीतिक घमासान के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि प्रदेश की जनता भलीभांति जानती है कि उसे किसे वोट देना है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनी गई सरकार को जिस तरह षड्यंत्र करके सत्ता से बेदखल किया गया है, जनता उसका सबक भाजपा को जरूर सिखाएगी। वह कहते हैं कि प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव, आम चुनाव नहीं हैं। मैं इसे उपचुनाव भी नहीं मानता। ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पिछले चार महीने से मैंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया है, क्योंकि हमारी लड़ाई भाजपा की उपलब्धियों के साथ नहीं बल्कि उनके संगठन के साथ है। साथ ही कहा कि प्रदेश की जनता के सामने कांग्रेस के 15 महीने का शासन और भाजपा के 15 साल के कार्यकाल की तस्वीर है। हमने अपनी नीतियों और नीयत का परिचय दिया है। जनता सच्चाई को पहचाने और सच का साथ दे। मैं मध्य प्रदेश की पहचान बदलने की कोशिश कर रहा था लेकिन भाजपा इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी और इसलिए उन्होंने मेरी सरकार को गिरा दिया।

कांग्रेस कार्यकर्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया से इस कदर नाराज थे कि उनका विरोध करने के लिए सुबह से ही कई दिग्गज नेता पहुंच गए थे। लेकिन इससे पहले पुलिस ने कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया।

यही नहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध को देखते हुए सभा स्थल पर काले कपड़े पहनकर आए लोगों को प्रवेश नहीं दिया गया। कांग्रेस नेत्री रश्मि पवार काले कपड़े पहनकर सिंधिया का विरोध करने पहुंचीं, उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूर्व मंत्री बालेंद्र शुक्ला, भगवान सिंह यादव, पूर्व सांसद रामसेवक सिंह गुर्जर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह पहला मौका था जब सिंधिया का ग्वालियर में इतना बड़ा विरोध हुआ हो। हालांकि भाजपा के लिए यह दांव राहत वाला भी कहा जा सकता है। सही मायने में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यही चाहते थे कि सिंधिया का ग्वालियर में जितना विरोध होगा उतना पार्टी को फायदा भी मिलेगा।

दोनों ओर भितरघात का खतरा

उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस की परेशानी यह है कि दोनों पार्टियों में भितरघात का डर है। इसकी वजह भी नजर आती है। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए 25 पूर्व विधायकों का तो भाजपा से चुनाव लड़ना निश्चित है। इससे क्षेत्र के भाजपा नेताओं का भविष्य दांव पर लग गया है। कांग्रेस के पास कई क्षेत्रों में चुनाव मैदान में उतारने के लिए उम्मीदवारों का टोटा है। इसलिए कांग्रेस अब भाजपा के हारे और वरिष्ठ नेताओं को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रही है। उसे अपनी इस मुहिम में सफलता भी मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भाजपा के ऐसे असंतुष्ट नेताओं से खुद मुलाकात कर रहे हैं। प्रदेश में अब तक के चुनाव में कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला होता रहता है। लेकिन बसपा, सपा, निर्दलीय और अन्य पार्टियों के प्रत्याशी कांग्रेस-भाजपा की जीत के गणित को बिगाड़ते रहते हैं। अत: इस बार के उपचुनाव में दोनों पार्टियों की नजर वोटकटवा उम्मीदवारों पर रहेगी। सूत्र बताते हैं कि दोनों पार्टियों ने विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं से संपर्क करना शुरू कर दिया है। साथ ही चुनावी मैदान में उनके उतरने के प्रभाव का आंकलन किया जा रहा है।

दरअसल, 27 सीटों पर होने वाला उपचुनाव शिवराज सरकार के स्थायित्व और कांग्रेस की नई उम्मीदों से जुड़ा है। यही वजह है कि एक-एक सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए दोनों दल बिसात बिछा रहे हैं। इसमें दाल किसकी गलेगी अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन टिकट के दावेदारों की रस्साकसी देखकर संकेत मिलने लगा है कि बगावत दोनों तरफ होगी। अगर ऐसी स्थिति में कुछ सीटों पर बागी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतर गए तो किसी एक का खेल बिगड़ सकता है। टिकट न मिलने पर दल से बगावत कर चुनाव लड़ने का चलन बहुत पुराना है। इस बार होने वाले उपचुनाव भी इस घमासान से अछूते नहीं रहेंगे। भाजपा ने तो तय कर दिया है कि जो विधानसभा सदस्यता और कांग्रेस से इस्तीफा देकर पार्टी में शामिल हुए हैं, उन्हें ही टिकट मिलेगा। इसमें एक-दो फेरबदल भले हो जाएं, लेकिन ज्यादातर सीटों के उम्मीदवार तय हैं। वहीं कांग्रेस असंतुष्ट भाजपा नेताओं को पार्टी में शामिल करवा रही है। ऐसे में वहां भी बहुत से दावेदारों की उम्मीद टूटनी तय है। अब चुनाव लड़ने की आस में अपनी-अपनी जमीन तैयार कर रहे दोनों दलों के नेता टिकट न मिलने पर निर्दलीय भी आ सकते हैं। कई दावेदारों ने अपने समर्थकों को तैयारी में लगा दिया है।

कांग्रेस के सामने चुनौतियां

कांग्रेस में राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर सतह पर आए कलह राज्यों में भी पार्टी को खासा नुकसान पहुंचा सकती है। मप्र में होने वाले 27 विस सीटों के उपचुनाव में वह सत्ता वापसी की राह तलाश रही है, जो कलह के चलते खटाई में पड़ सकती है। खींचतान ने मतदाताओं के बीच पार्टी की साख पर सवाल तो खड़े ही किए हैं, राज्य में कांग्रेस की खेमेबंदी पर लगी पैबंद उधड़कर फिर सामने आने लगी है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, विवेक तन्खा, मुकुल वासनिक, अजय सिंह सहित कई प्रमुख नेताओं के दिल्ली कनेक्शन से उपजी खेमेबंदी चर्चा में है।

कांग्रेस उपचुनाव की 27 विस सीटों पर प्रत्याशी तय नहीं कर सकी है। कड़ी टक्कर देने के लिए वो भाजपा में विद्रोह की आस करती दिख रही है। वह भाजपा के बागियों को मौका देने की तैयारी में है। दूसरी मुश्किल है युवाओं को मौका न मिलना। सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद कांग्रेस में युवा चेहरे की कमी है, जिसे भरने के लिए कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के पुत्रों सहित जीतू पटवारी की खींचतान पिछले दिनों सड़क से सोशल मीडिया तक देखी जा चुकी है। बुजुर्ग नेताओं के ही हावी होने की दशा में युवा भी भविष्य के लिए इंतजार की मुद्रा में हैं। उन्हें उम्मीद है कि राहुल गांधी यदि पार्टी की कमान संभालते हैं तो उन्हें मौका मिल सकता है। ऐसे में जब तक हाईकमान स्तर पर तस्वीर स्पष्ट नहीं होगी, युवाओं का पार्टी की तरफ रुझान बढ़ा पाना टेढ़ी खीर होगी।

फायदा और नुकसान का गणित

संक्रमण बढ़ने के दौरान अप्रैल-मई में ही भाजपा और कांग्रेस ने अनुमान लगा लिया था कि इस बार चुनाव, फील्ड के बजाय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लड़ा जाएगा। इसलिए उसने चुनाव की डिजिटल तैयारी पहले से शुरू कर दी थी। भाजपा की वर्चुअल रैली और कांग्रेस की वर्चुअल मीटिंग इसी तैयारी का हिस्सा हैं। भाजपा और कांग्रेस ने समय की मांग को देखते हुए साइंटिफिक इलेक्शन कैंपेन की तैयारी पहले ही शुरू कर दी थी। राज्य में मार्च माह में पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 तत्कालीन विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था, जिससे कमलनाथ की सरकार गिर गई थी और भाजपा को सरकार बनाने का मौका मिला। इसके बाद तीन और विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया था। वहीं दो विधायकों का निधन होने से स्थान खाली पड़ा हुआ है। इस तरह राज्य में 27 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने वाले हैं। राज्य की विधानसभा की स्थिति पर गौर किया जाए तो भाजपा पूर्ण बहुमत से अभी 9 अंक दूर है, क्योंकि 230 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 116 विधायकों का समर्थन आवश्यक है। वर्तमान में भाजपा के 107 विधायक हैं। कांग्रेस के 89 विधायक हैं, सपा, बसपा व निर्दलीय मिलाकर सात विधायक हैं। इस तरह 203 विधायक हैं। भाजपा को 27 स्थानों में से सिर्फ 9 स्थानों पर ही जीत मिलने पर पूर्ण बहुमत का आंकड़ा हासिल हो जाएगा।

भाजपा सूत्रों का कहना है कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा के लिए सुखद अभी भी सूचनाएं नहीं आ रही हैं। इस वजह से भाजपा संगठन जहां अपने स्तर पर उपचुनाव वाले क्षेत्रों में काम कर रहा है, वहीं संघ के स्वयंसेवक अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इस समय कोरोना संक्रमण के कारण लोग मुसीबत में हैं और संघ के स्वयंसेवक इन लोगों की हर संभव मदद करने में लगे हैं। स्वयंसेवकों की सक्रियता से संघ को जमीनी फीडबैक भी मिल रहा और उसी के आधार पर आगे की रणनीति बनाई जा रही है। पिछले एक माह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत की भोपाल में हुए दो दौरों को विधानसभा उपचुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे, संघ प्रमुख के इन दौरों के दौरान उनका भाजपा के किसी बड़े नेताओं से तो मुलाकात नहीं हुई, मगर संघ प्रमुख का स्वयंसेवकों से संवाद जरूर हुआ। संघ के सूत्रों का कहना है कि संघ सूचनाओं के आधार पर अपनी रणनीति बनाता है। इसी आधार पर पिछले चार माह से संघ रणनीति बनाकर काम कर रहा है। इसीलिए संघ प्रमुख एक माह के भीतर मध्यप्रदेश का दो बार दौरा कर चुके हैं और संघ के लोगों से फीडबैक ले चुके हैं।

उपचुनाव से पहले संघ की शरण में ज्योतिरादित्य

तीन दिनों के ग्वालियर-चंबल के दौरे के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया गत दिनों नागपुर स्थिति संघ कार्यालय पहुंचे। कहा जा रहा है कि यहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संघ सरसंचालक डॉ. मोहन भागवत से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार संघ कार्यालय पहुंचे हैं। हालांकि सिंधिया ने कांग्रेस में रहते हुए भी संघ पर हमला नहीं बोला था। इसकी एक बड़ी वजह है सिंधिया परिवार का हिंदू महासभा, जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर। सिंधिया की इस मुलाकात के बाद ये माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद कांग्रेस की राजनीति के अपेक्षा भाजपा में बड़ा होने वाला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार संघ कार्यालय पहुंचे हैं। उनके संघ कार्यालय पहुंचने के साथ ही माना जा रहा है कि भाजपा में शामिल होन के बाद उपचुनाव से पहले सिंधिया संघ का आशार्वाद लेने के लिए नागपुर पहुंचे थे। संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद अब सिंधिया उपचुनाव में पूरी तैयारी से उतरेंगे। सिंधिया भाजपा में शामिल होने के बाद कई नेताओं से मिले थे जो संघ के भी करीब थे। लेकिन संघ के पदाधिकारियों से नहीं मिले थे। अब उपचुनाव से पहले संघ कार्यालय पहुंचने का एक मकसद ये भी हो सकता है कि ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में संघ का दबदबा है। सिंधिया मालवा में भी अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। ऐसे में संघ कार्यालय में हाजिरी लगाकर सिंधिया नागपुर की भी पसंद बनने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भाजपा के कई नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला करते रहते थे।

कैसे मिलेगी मंजिल

वर्ष 2018 में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने थे और कांग्रेस हाईकमान ने अप्रैल में ही मप्र कांग्रेस की बागडोर कमलनाथ को सौंप दी थी। तब कांग्रेस मप्र में कई धड़ों में बंटी होने के कारण करीब 15 साल से सत्ता से बाहर चल रही थी। नाथ ने सबसे पहले इन धड़ों को एकसाथ लाने में सफलता हासिल की, फिर कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया। केंद्रीय नेतृत्व को जीत का भरोसा दिलाया, तो राहुल गांधी ने मंदसौर की रैली में किसानों की कर्जमाफी का वादा किया। माना जाता है कि इसी वादे के चलते भाजपा के हाथों से सत्ता चली गई और कांग्रेस ने वापसी की। हालांकि करीब डेढ़ साल बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थक विधायकों के साथ भाजपा में चले गए और कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी। अब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ही मप्र में संगठन के मुख्य सूत्र हैं, लेकिन दिल्ली में मची उठापटक के बाद इनकी राहें भी एक नहीं दिख रहीं। सवाल उठ रहे हैं कि यदि राहें जुदा होंगी तो मंजिल कैसे मिलेगी? उपचुनाव वाले क्षेत्रों में अब तक दोनों एक साथ नहीं गए, न ही उपचुनाव को लेकर कभी चर्चा के लिए बैठे, जिससे कार्यकर्ताओं में सक्रियता का संदेश जा सके।

कार्यकर्ता फिर पसोपेश में

मप्र कांग्रेस में शीर्ष स्तर पर बिखराव से कार्यकर्ता एक बार फिर चौराहे पर है कि इधर जाए या उधर? तय नहीं कर पा रहा है कि पार्टी और खुद के सियासी भविष्य के लिए उसे किधर कदम बढ़ाने हैं। जानकार कहते हैं कि मामला भले ही जमीनी कार्यकर्ता का हो, लेकिन इसके लिए काफी हद तक पार्टी हाईकमान

18 लाख मतदाताओं की उपेक्षा किस पर पड़ेगी भारी

मप्र में जिन 27 सीटों पर उपचुनाव होने वाला हैं, उनमें से 25 पर कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे और भाजपा में शामिल होने के कारण हो रहा है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने वाले इन नेताओं के खिलाफ इनके क्षेत्र में माहौल है। कांग्रेस का दावा है कि 18 लाख मतदाताओं की उपेक्षा करने वाले पूर्व विधायकों को मतदाता उपचुनाव में सबक सिखाएंगे। वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस में भेदभाव और भ्रष्टाचार की राजनीति से परेशान होकर पूर्व विधायकों ने पार्टी छोड़ी है। गौरतलब है कि मार्च में कांग्रेस छोड़ने वाले 22 विधायकों में 19 ज्योतिरादित्य सिंधिया के वफादार हैं। बाकी बिसाहूलाल सिंह, ऐदल सिंह कंसाना और हरदीप सिंह डंग सिंधिया के समर्थक नहीं हैं, लेकिन सिंधिया की नाव में सवार होकर मंत्री की कुर्सी की ओर बढ़ गए। ये कमलनाथ कैबिनेट में स्थान न मिलने से नाराज थे। कांग्रेस छोड़ने वाले प्रद्युम्न लोधी, सुमित्रा कासडेकर और नारायण पटेल नए चेहरे थे, लिहाजा इनका कोई गहरा वैचारिक नाता कांग्रेस से नहीं था। ये बड़े नेताओं की मेहरबानी के अलावा कमलनाथ की ओर से किए गए सर्वे के जरिए पार्टी उम्मीदवार बनाए गए थे। ये लोग टिकट बंटवारे के समय पीसीसी को जातीय गणित के मुफीद भी थे। यानी ये बात तय है कि ऐसे ही राजनीति में नए और पहली बार के विधायकों पर भाजपा की नजर है। कांग्रेस का मैनेजमेंट इस टूटन को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे अनुभवी और राजनीतिक प्रबंधन के माहिर नेताओं का गणित भी फेल हो गया है। कांग्रेस नेताओं को विधायकों के जाने की भनक भी नहीं लग पा रही है। इस दल बदल से जाहिर है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी हो रही है। लोकतंत्र में खरीद-फरोख्त या हॉर्स ट्रेडिंग जैसे किसी भी कृत्य की स्पष्ट मनाही है। सवाल यह भी है कि यदि इस तरह सरकारें चलनी हैं तो चुनाव की आवश्यकता ही क्या है। कांग्रेस के जिन 25 विधायकों ने विधायकी छोड़ी उनको 18 लाख से ज्यादा लोगों ने चुना था। अब उनके इस संवैधानिक अधिकार वोट का क्या मतलब निकला। कांग्रेस कहती है कि चुने हुए प्रतिनिधियों को खरीदने या उनके दलबदल की कोई व्यवस्था नहीं है। भाजपा देश की सभी संस्थाओं को नष्ट करने पर तुली हुई है। चाहे आप मध्यप्रदेश, कर्नाटक या राजस्थान का उदाहरण देख लीजिए। कांग्रेस के इस तर्क को भाजपा हास्यास्पद बताती है, भाजपा कहती है कि आपातकाल लगाने वाले कब से लोकतंत्र की फिक्र करने लगे। अब देखना यह है कि उपचुनाव में मतदाता विधायकी छोड़कर फिर से चुनाव मैदान में उतरे नेताओं को सिर-आंखों पर बैठाता है, या उन्हें सबक सिखाता है।

जिम्मेदार है। यदि वह राज्य संगठनों को प्रोत्साहित करे और नेतृत्व की स्थिति स्पष्ट रखे तो कार्यकर्ता बिना किसी उहापोह के निष्ठा के साथ पार्टी संग खड़ा रहेगा। वैसे भी मप्र में हाईकमान को सिंधिया प्रकरण के बाद कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के उपाय करने ही चाहिए थे, जो नहीं किए गए। हम देख सकते हैं कि ग्वालियर-चंबल अंचल में भी शिवराज और सिंधिया का विरोध करने में थोड़ी संख्या में ही कांग्रेस कार्यकर्ता सामने आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद कांग्रेस में संगठन स्तर पर काफी उथल-पुथल देखी गई। ऐसे में जो नेता कांग्रेस छोड़कर गए, उनके स्थान पर पार्टी ने नियुक्ति नहीं की है। सिंधिया के प्रभाव क्षेत्र ग्वालियर चंबल में तो लगभग पूरा संगठन ही सिंधिया के समर्थकों के हाथों में था, जो अब भाजपा में जा चुके हैं। संगठन के मामले में यदि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की बात करें, तो कमलनाथ की जमीनी पकड़ अपेक्षाकृत कमजोर है, जबकि दिग्विजय सिंह ब्लॉक स्तर तक कांग्रेस पदाधिकारियों को जानते-पहचानते हैं। चूंकि दोनों नेताओं में दूरी की बातें कही जा रही हैं, तो संगठन की मजबूती कमलनाथ के लिए चुनौती बनेगी ही। यदि हाईकमान की अस्थिरता खत्म हो तो मप्र में भी तस्वीर काफी हद तक साफ होगी और संगठन मजबूत हो सकेगा।

तय होगा दिग्गजों का भविष्य

27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव कई मायने में महत्वपूर्ण हैं। ये चुनाव सत्ता का भविष्य तो तय करेंगे ही दिग्गज नेताओं का भी भविष्य तय करेंगे। इनके नतीजे भाजपा-कांग्रेस के प्रमुख नेताओं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ एवं दिग्विजय सिंह का राजनीतिक भविष्य तय करेंगे। इसीलिए उपचुनावों को आम चुनावों जैसा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों दल यही मानकर तैयारी कर रहे हैं। खास बात यह है कि दोनों प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहे हैं। हालांकि इतिहास पर नजर डालें तो उपचुनाव के नतीजे सत्तापक्ष की ओर ज्यादा आते रहे हैं। फिर भी बदली राजनीतिक परिस्थितियों में कुछ भी हो सकता है। भाजपा में शिवराज और ज्योतिरादित्य पर चुनाव की जवाबदारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थक कांग्रेस विधायकों को तोड़कर लाए हैं। इसके बाद सरकार बनी है। उन्हें यह साबित करना है कि ये विधायक उनके आभामंडल की बदौलत जीते थे, इसे बरकरार रखने के लिए फिर सभी का जीतना जरूरी है। इससे भाजपा में उनका राजनीतिक भविष्य निर्धारित होगा। विधानसभा चुनाव में पार्टी की पराजय के बावजूद शिवराज सिंह चौहान को फिर मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसलिए उनकी जवाबदारी है कि ज्यादा सीटों पर भाजपा जीते ताकि सत्ता बरकरार रहे। इसलिए शिवराज का भविष्य भी इन उपचुनावों के नतीजों पर टिका है।

उधर कांग्रेस में कमलनाथ और दिग्विजय के कौशल की परीक्षा है। कांग्रेस में कमलनाथ एवं दिग्विजय सिंह की पारी अभी और चलेगी या उनके राजनीतिक भविष्य पर विराम लग जाएगा, उपचुनाव के नतीजों से यह भी तय हो सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ चुके हैं। इसकी वजह नाथ-दिग्विजय की जोड़ी को माना जा रहा है। बाद में भी 3 विधायक कांग्रेस छोड़कर गए, इसका भी यही अर्थ निकला कि कमलनाथ सरकार के बाद संगठन को संभाल नहीं पा रहे हैं। ऐसे हालात में यदि उपचुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आते हैं तो एक बार फिर नाथ-दिग्विजय की जोड़ी के कौशल का लोहा माना जाएगा। ऐसा न हुआ तो कांग्रेस के नुकसान का खामियाजा इन दोनों नेताओं को उठाना पड़ सकता है।

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

Celebrating 25 YEARS EXPERIENCE

Science House Medicals Pvt.Ltd.

17/1, Sector-1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal (M.P.) INDIA-462023

GST. No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbpl@rediffmail.com

PH. : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

कांग्रेस को राजनीति के हाशिए पर धकेलने के बाद अब भाजपा की नजर क्षेत्रीय दलों पर है। इसके लिए पार्टी के रणनीतिकार तैयारी में जुटे हुए हैं। मोदी-शाह की नजरें ममता के बंगाल, पटनायक के ओडिशा, केसीआर के तेलंगाना और जगन के आंध्र पर टिकी हैं। जबकि कांग्रेस ने अपना सारा ध्यान प्रधानमंत्री पर ही केंद्रित कर रखा है।

अब निशाने पर क्षेत्रीय दल

सहयोगी दलों के लिए बदलाव की जरूरत

1990 के दशक के मध्य में भाजपा का विस्तार राजनीतिक मॉडरेशन पर आधारित था। 1996 में वाजपेयी के नेतृत्व वाली उसकी गठबंधन सरकार 13 दिनों में गिर गई क्योंकि शिवसेना, समता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल को छोड़कर कोई भी बड़ी पार्टी सांप्रदायिक छवि के कारण इसकी सहयोगी नहीं बनना चाहती थी। जैसा कि राजनीति विज्ञानी माइकल गिलन ने अपने अध्ययन असेसिंग द 'नेशनल' एक्सपेंशन ऑफ हिंदू नेशनलिज्मः द बीजेपी इन साउदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया 1996-2001, में जिक्र किया है कि भाजपा ने इस चरण में आक्रामक रूप से एक कांग्रेस-विरोधी समान मंच के आधार पर गठबंधन सहयोगियों को जोड़ा और हिंदुत्व को एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बनाने के बजाय क्षेत्रीय संदर्भों के अनुरूप हिंदुत्व का पुनर्निर्धारण किया। वास्तव में भाजपा के 1999 के घोषणापत्र में आश्चर्यजनक रूप से राम मंदिर का कोई उल्लेख नहीं था। भाजपा अब अपने प्रभुत्व के चरण में है और क्षेत्रीय सहयोगियों की बाध्यताओं से मुक्त हो चुकी है। भाजपा के वैचारिक एजेंडे के अनुरूप समझौता क्षेत्रीय दलों को करना पड़ रहा है जैसा हाल ही में आप और बसपा के साथ देखा गया, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है।

कांग्रेस मुक्त भारत अभियान के साथ ही भाजपा क्षेत्रीय दलों के सफाए पर भी काम कर रही है। भाजपा के निशाने पर कई क्षेत्रीय पार्टियां और उसके नेता हैं। लेकिन नीतीश कुमार के पास ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी उनका साथ छोड़ नहीं रही? कई राजनीतिक रणनीतिकार इसका जवाब ढूंढ़ने के लिए अपना सिर धुन रहे हैं। आखिरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी लोकप्रियता के चरम पर हैं। कुछ लोगों का कहना है कि झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को लगे झटकों ने अमित शाह का जोखिम न लेने की राह पर मोड़ दिया है। वह नहीं चाहेंगे कि कुमार 2015 की तरह फिर कोई महागठबंधन बनाए, जिसमें जनता दल-यूनाइटेड (जदयू), कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और अन्य दल शामिल हों। और इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2020 में भाजपा-जदयू गठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके सारी अटकलों पर विराम लगा दिया है।

भाजपा के अंदरूनी सूत्र इस पर कुछ अलग ही राय रखते हैं। उनका कहना है कि शाह की प्राथमिकता पहले राजद को खत्म करना है। उनका आंकलन कहता है कि इस चुनाव में मिली हार लालू यादव की पार्टी को हमेशा के लिए अप्रासंगिक बना देगी। राजद के वरिष्ठ नेताओं ने पहले ही पार्टी छोड़ना शुरू कर दिया है और एक अन्य चुनावी हार राजद के मुख्य आधार, यादवों को भाजपा के पाले में खड़ा कर देगी। 69 साल के नीतीश कुमार अपनी अंतिम राजनीतिक पारी खेल रहे हैं और एक बार उन्होंने राजनीति से किनारा किया तो जदयू के पास आगे लंबे समय तक टिके रहने के लिए नेतृत्व की दूसरी पंक्ति नहीं है। राजद और जदयू के राजनीतिक हाशिए पर जाने के साथ ही बिहार में भाजपा अपराजेय हो जाएगी। कहने का सीधा आशय यह है कि भाजपा पहले नीतीश कुमार को राजद के 'सफाए' के लिए इस्तेमाल करना चाहती है और फिर इस बात का इंतजार और इस दिशा में काम करना चाहती है कि नीतीश कुमार परिदृश्य से बाहर हो जाएं ताकि वह उनकी राजनीतिक विरासत पर दावा करे या फिर उसे हड़प सके।

भाजपा ओडिशा में भी इसी तरह इंतजार की रणनीति अपना रही है। वह 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को तीसरे स्थान पर धकेल कर प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभरी थी। ऐसे में किसी को भी यही उम्मीद होगी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह अब इसका फायदा उठाएंगे और नवीन पटनायक के साथ जोर-आजमाइश करेंगे। इसके बजाय, भाजपा ने संसद में अपनी सरकार का समर्थन सुनिश्चित करने के लिए बीजू जनता दल की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया। उनके साथ रिश्ते इतने सौहार्दपूर्ण हैं कि भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजद के पूर्व नेता बैजयंता पांडा को अपने खेमे में लाने के लिए राज्यसभा सीट देने जैसा कदम नहीं उठाया।

इसे लेकर भी भाजपा के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि मोदी और शाह अक्टूबर में 74 साल के होने जा रहे पटनायक की राजनीतिक पारी पूरी होने का इंतजार करेंगे। पटनायक, जिन्होंने पार्टी में दूसरी पंक्ति का नेतृत्व तैयार नहीं किया है, एक बार मैदान से बाहर हुए तो भाजपा के लिए बीजद का जनाधार खत्म करना और उस पर कब्जा करना आसान होगा। कांग्रेस आज ओडिशा में अप्रासंगिक हो चुकी है, ऐसे में भाजपा राज्य की राजनीति पर उसी तरह हावी होने को तत्पर है जैसे पिछले दो दशक से बीजद वहां पर काबिज है। बहरहाल, मोदी और शाह क्षेत्रीय दलों के वर्चस्व वाले अन्य राज्यों में अपनी बाजीगरी आजमा रहे हैं। मोदी सरकार को अपनी पहली पारी में इनकी आवश्यकता थी क्योंकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के पास विवादास्पद विधेयकों पर संसदीय अनुमोदन के लिए बहुमत कम था और अन्य दलों की मदद की जरूरत थी। मौजूदा स्थिति में एनडीए 245 सदस्यीय राज्यसभा में सहज स्थिति में है जिसके पास कांग्रेस की 40 सीटों के मुकाबले अकेले भाजपा की 85 सीटें हैं। यहां तक कि अगर कोई भाजपा विरोधी दलों (आज की तारीख में) के सांसदों की गिनती करे तो,

वामपंथी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी), झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और कुछ अन्य यानी कुल मिलाकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की संख्या अकेले भाजपा के बराबर नहीं हो सकती।

एनडीए सांसद और नामित सदस्यों को मिला दिया जाए तो आंकड़ा राज्यसभा में बहुमत के निशान से करीब एक दर्जन ही कम है, जबकि ऐसे पाला बदलने वाले सदस्यों की लंबी फेहरिस्त है जो सदन पटल पर मोदी सरकार का समर्थन करने को तैयार हैं। इसलिए, मोदी सरकार को अब क्षेत्रीय दलों को साधने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा, जब भाजपा अपने 'कांग्रेस-मुक्त भारत' अभियान को आगे बढ़ा रही थी और केंद्र और कांग्रेस के मुख्य प्रतिद्वंद्वी होने वाले राज्यों में सफलता हासिल कर रही थी, वो क्षेत्रीय दल ही थे जिन्होंने ग्रांड ओल्ड पार्टी के खिलाफ मोर्चेबंदी की थी। इन क्षेत्रीय दलों ने कई राज्यों में कांग्रेस का पूरी तरह सफाया कर दिया, जिससे भाजपा को उस राजनीतिक रिक्तता को भरने और विस्तार का मौका मिला। पश्चिम बंगाल में भाजपा इसलिए हावी हो रही है क्योंकि वहां पर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस एकमात्र चुनौती बनी हुई है, वामपंथी और कांग्रेस विपक्ष की जगह भगवा पार्टी के लिए खाली करते जा रहे हैं। 65 वर्षीय बनर्जी की राजनीतिक पारी पूरी होने में अभी काफी वक्त है और भाजपा ऐसे में अपना समय बेवजह बर्बाद नहीं कर सकती है।

नवीन पटनायक की तरह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और के. चंद्रशेखर राव भी तमाम व्यावहारिक उद्देश्यों को ध्यान में रख भाजपा के सहयोगी दलों की तरह काम कर रहे हैं। हाल तक संसद में इनके समर्थन की जरूरत रहने के बाद, भगवा पार्टी ने इन दो क्षेत्रीय क्षत्रपों को कांग्रेस और तेलुगुदेशम पार्टी के खिलाफ मोर्चा संभालने के लिए छोड़ दिया है। हालांकि, एक प्रमुख भाजपा रणनीतिकार ने मुझे बताया कि अपनी दक्षिण यात्रा में पार्टी के लिए ये दोनों राज्य 'स्वाभाविक तौर पर अगला पड़ाव' हैं। भाजपा को तेलंगाना में अपने लिए 'एक उर्वर जमीन' नजर आती है, जहां 13 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है और अखिल भारतीय मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के सहयोगी बने हुए हैं। 2019 में भगवा पार्टी ने राज्य की 17 लोकसभा सीटों में से चार पर जीत हासिल की थी जबकि टीआरएस को 9 और कांग्रेस की तीन सीटें मिली थीं। तेलंगाना में कांग्रेस राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक नहीं हो सकती है (जैसे बिहार, ओडिशा या पश्चिम बंगाल में हो गई है) लेकिन फिर भी भाजपा के पास आक्रामक होने के कारण हैं। आंध्र प्रदेश में भाजपा के साथ-साथ कांग्रेस को भी 2019 के लोकसभा चुनाव में खास सफलता नहीं मिली। अब जबकि 70 साल के चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी के फिर से खड़े होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे और मुख्यमंत्री रेड्डी पर 'अल्पसंख्यक तुष्टीकरण' का आरोप लगाया जा रहा है, यह भाजपा के मोर्चा संभालने के लिए एक आदर्श स्थिति है। पार्टी ने अपने दो युवा सांसदों- मैसूर के प्रताप सिम्हा और बेंगलुरु दक्षिण के तेजस्वी सूर्या को इस साल की शुरुआत में अभिनेता से नेता बने जनसेना पार्टी के पवन कल्याण से मिलने भेजा था। भाजपा चाहेगी कि कल्याण अपनी पार्टी का उसके साथ विलय कर दें और आंध्र की राजनीति में उसका चेहरा बन जाएं। हालांकि अभी शुरुआत है लेकिन भाजपा ने वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। सीबीआई पहले से आय से अधिक संपत्ति मामले में रेड्डी पर शिकंजा कसने को तैयार है।

तमिलनाडु में जयललिता के निधन ने सत्तारूढ़ अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके), एक भाजपा सहयोगी, को कमजोर कर दिया है। भाजपा के पास इस राज्य में पैर जमाने की उम्मीद करने के कारण हैं, जहां कांग्रेस ने 1960 के दशक के उत्तरार्ध में द्रविड़ दलों के आगे अपना आधार खो दिया था और तब से उनके साथ गठबंधन के जरिए अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए संघर्षरत है। एक तरफ जहां भाजपा अब क्षेत्रीय दलों के खिलाफ मोर्चा खोल रही है, कांग्रेस ने अपना ध्यान पूरी तरह भाजपा पर ही केंद्रित कर रखा है। ग्रांड ओल्ड पार्टी ने क्षेत्रीय दलों के बढ़ते दबदबे के कारण ही भारतीय राजनीति में अपना पुराना रुतबा गंवाया है लेकिन उसे सिर्फ भाजपा की धुन सवार है और अपनी सारी ऊर्जा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने में खर्च कर रही है। भाजपा के पास 2019 में जीती सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ सफलता का रिकॉर्ड 92 प्रतिशत है। और इनमें से अधिकांश सीटों पर जीत का अंतर लाखों में है। फिर भी क्षेत्रीय खिलाड़ियों के खिलाफ मोर्चा खोलकर अपनी स्थिति बेहतर करने की कोशिश, जिसमें बेहतर मौके मिल सकते हैं, के बजाय कांग्रेस भाजपा के ही पीछे पड़ी है।

● इंद्र कुमार

अर्थव्यवस्था अब राष्ट्रीय मुद्दा नहीं

अब जबकि भारत आजादी के बाद से सबसे खराब आर्थिक मंदी की स्थिति में है, तब भी मोदी की लोकप्रियता एक सर्वकालिक शीर्ष स्तर पर है। यह भाजपा के लिए मददगार है क्योंकि आर्थिक मंदी से इतना तो तय है कि मोदी सरकार 2024 में किसी भी बड़ी आर्थिक उपलब्धियों के साथ मैदान में नहीं उतरेगी। इतनी गहरी मंदी से उबरने में अर्थव्यवस्था को सालों लगते हैं। चूंकि राजकोषीय स्थिति का बड़ा हिस्सा सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक संकट के दुष्प्रभावों को दूर करने में लगेगा, इसलिए भाजपा के लिए सामाजिक क्षेत्र की कोई नई बड़ी योजना शुरू करने या कल्याणकारी कार्यों के लिए मौका नहीं होगा। यह तथ्य कि मोदी अब '2022 तक भारत' के बारे में लगभग न के बराबर बात करते हैं, (जिसके तहत आवास, बिजली, इंटरनेट और पेयजल जैसे क्षेत्रों में महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए गए थे) इस बात का संकेत है कि उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। न ही यह संभावना है कि मोदी बड़े आर्थिक सुधारों पर अधिक राजनीतिक पूंजी खर्च करेंगे, न ही आर्थिक मुद्दे राजनीतिक बहस के केंद्र में वापस आएंगे।

परिवार भरोसे

पिछले दिनों राजस्थान में अपनी सरकार जैसे-तैसे बचा पाने में सफल हुई कांग्रेस पार्टी उत्साहित जरूर है लेकिन अपनी 'लीडरशिप' को लेकर पार्टी में चिंता की लकीरें देखी जा सकती हैं। भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दहाड़ के आगे बौनी नजर आ रही राष्ट्रीय कांग्रेस पिछले 6 वर्षों से सिमटती जा रही है। वैसे तो कई महीनों से पार्टी के अंदर बागडोर संभालने को लेकर महामंथन चल रहा है। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कोई फैसला नहीं हो पाया। इस कारण सोनिया गांधी पुनः अंतरिम अध्यक्ष चुनी गईं।

कांग्रेस पार्टी को न जाने क्या रोग लग गया है कि उसके समाधान के लिए जितनी दवा की जा रही है उसका रोग उतना ही बढ़ता जा रहा है। पार्टी को सबसे बड़ा रोग यह लगा है कि वह नेहरू-गांधी परिवार के आगोश से निकल नहीं पा रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हवाले से खबर फैलाई गई कि अबकी बार किसी बाहरी को अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन मामला सोनिया बनाम राहुल बना दिया गया।

पिछले कुछ वर्षों से सबसे खराब दौर से गुजर और बिखर रही कांग्रेस को लेकर उम्मीद की जा रही थी कि वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी कुछ उभर पाएगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता इस बैठक में पिछले कई दिनों से निगाहें लगाए बैठे थे। कुछ दिनों पहले तक जो खबरें आ रही थीं, उसके अनुसार वर्किंग कमेटी में कांग्रेस के नए अध्यक्ष पद की ताजपोशी ही सबसे महत्वपूर्ण फैसला बना हुआ था। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पटकथा कई दिनों पहले लिखी गई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्किंग कमेटी की बैठक जैसे ही शुरू हुई कांग्रेस पूरी तरह दो फाड़ में नजर आई। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक ऐसे वक्त में हुई जब पार्टी के 23 वरिष्ठ नेताओं ने नेतृत्व पर सवाल खड़े किए। बैठक में सख्त तेवर और तिमिलाहट के साथ जुड़े पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल सहित उन तमाम 23 नेताओं पर भाजपा के साथ मिलीभगत के खुलेआम आरोप लगाए, जिन्होंने नेतृत्व परिवर्तन को लेकर सोनिया गांधी को पत्र लिखा। यही नहीं राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस की बैठक में भाजपा ने अपने 'वजीर' फिट कर रखे हैं।

राहुल के इस आक्रामक अंदाज को कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद सहन नहीं कर सके, इन दोनों ने भी अपनी-अपनी आस्तीन चढ़ा लीं। फिर क्या था दोनों ओर से जबरदस्त 'तू-तू, मैं-मैं' होती रही। सबसे महत्वपूर्ण यह था कि कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक का भाजपा लाइव प्रसारण भी देख रही थी (आज भाजपा अपने मिशन कांग्रेस के सफाए को लेकर एक कदम और आगे बढ़ गई)। अभी तक कहा जाता है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अधिकांश बातें सूत्रों के हवाले से ही बाहर आती हैं लेकिन आज पार्टी का महाभारत अपने आप ही बाहर निकलने को बेताब दिखाई दिया। राहुल के आरोपों के बाद गुस्साए गुलाम नबी आजाद बोले कि, भारतीय जनता पार्टी से मिलीभगत साबित हुई तो इस्तीफा दे दूंगा। बैठक की शुरुआत में वरिष्ठ कांग्रेसियों की चिट्ठी सार्वजनिक होने का मामला गरमाया रहा। सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की, साथ में उस चिट्ठी का जवाब भी दिया, जिसमें नेतृत्व पर सवाल उठाए गए थे। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी ने इस चिट्ठी की जबरदस्त आलोचना की।

कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता ऐसे हैं जो सीधे गोपनीय बातें लीक कर रहे हैं और भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। राहुल के बयान के बाद कांग्रेसी नेताओं की ट्विटर पर जंग दिखाई दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने ट्विटर का सहारा लिया और राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया। सिब्बल ने लिखा कि, राहुल गांधी कह रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, मैंने राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस पार्टी का सही पक्ष रखा, मणिपुर में पार्टी को बचाया, पिछले 30 साल में ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो किसी भी मसले पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाए, फिर भी कहा जा रहा है कि हम भाजपा के साथ हैं।

कपिल सिब्बल के ट्वीट पर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पलटवार किया। सुरजेवाला ने

राहुल-प्रियंका चाहते हैं बाहरी हो अध्यक्ष

2019 के आम चुनाव में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस कार्यकारिणी के सामने शर्त रखी कि वो गांधी परिवार से अलग किसी नेता को अध्यक्ष के तौर पर चुनने की तैयारी करे। तैयारियां भी देखने को मिलीं और तब भी राहुल गांधी ने कहा कि नए कांग्रेस अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया से गांधी परिवार दूरी बनाए रखेगा। राहुल गांधी ने ही बताया कि नया अध्यक्ष चुने जाने की प्रक्रिया से सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी दूर रहेंगी। अचानक एक दिन बताया गया कि सोनिया गांधी को कांग्रेस कार्यकारिणी ने अंतरिम अध्यक्ष चुन लिया है। 10 अगस्त को हुई बैठक से पहले भी बाहरी को अध्यक्ष बनाने की हवा चली, लेकिन फिर से सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बना दिया गया।

सिब्बल के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा कि, 'राहुल गांधी ने इस तरह की कोई भी बात नहीं कही और ना ही इस संबंध में कोई जिक्र किया है, कृपया कोई भी गलत सूचना ना फैलाएं, लेकिन हां हम सब क्रूर मोदी राज से लड़ने के लिए एकजुट हैं ना कि आपस में या कांग्रेस से लड़ने के लिए।'

दरअसल राहुल गांधी ने जब चिट्ठी लिखने वाले नेताओं को भाजपा का मददगार बताया, तो गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो इस्तीफा दे देंगे, चिट्ठी लिखने का फैसला सिर्फ कार्यसमिति का रहा है। करीब 15 दिन पहले पार्टी के 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि भाजपा लगातार आगे बढ़ रही है। पिछले चुनावों में युवाओं ने डटकर नरेंद्र मोदी को वोट दिए। कांग्रेस में लीडरशिप फुल टाइम होनी चाहिए और उसका असर भी दिखना चाहिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में वरिष्ठ नेताओं के बीच हुई आर-पार की लड़ाई में फिलहाल अभी तक भाजपा केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। लेकिन मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए ट्वीट किया कि कांग्रेस नेताओं ने पत्र लिखा कि पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए, तो राहुल गांधी कहने लगे कि ये गद्दारी है, सत्य कहने वालों को कांग्रेस में गद्दार कहा जाता है, ऐसी पथभ्रष्ट कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता है। वहीं मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जरूर कांग्रेस की इस महाभारत पर तंज कसा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि, कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए कई योग्य उम्मीदवार हैं। इनमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रेहान वाड्रा, मिराया वाड्रा शामिल हैं। कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए कि कांग्रेस उस स्कूल की तरह है, जहां सिर्फ हेडमास्टर के बच्चे ही क्लास में टॉप आते हैं। दूसरी ओर राहुल के समर्थन में पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि आंतरिक चुनावों की बजाय सबकी सहमति देखी जानी चाहिए। खुर्शीद ने कहा कि राहुल को कार्यकर्ताओं का पूरा समर्थन है ऐसे ही पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा कि फिलहाल गांधी परिवार को ही पार्टी की बागडोर संभालनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी राहुल गांधी पर भरोसा जताया है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी राहुल गांधी के नाम की ही वकालत करते हुए कहा कि राहुल गांधी को आगे आना चाहिए और पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए।

बता दें, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू होने से पहले दिल्ली स्थित पार्टी के मुख्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया, कहा कि गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष बना तो पार्टी टूट जाएगी। इस तरह आज हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में तड़क-भड़क इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस नए अध्यक्ष पद के मुख्य मुद्दे से ही भटक गई। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर बड़ा बयान दिया है। प्रियंका ने राहुल गांधी की उस मांग से सहमति जताई है कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष गांधी परिवार के बाहर के किसी शख्स को बनाने की मांग की गई थी। प्रियंका गांधी ने ये बातें एक इंटरव्यू में कही हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने नेहरू-गांधी परिवार के बाहर के व्यक्ति को अगला कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग की थी। राहुल की इसी मांग को अब प्रियंका का भी समर्थन मिला है। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी को एक बार फिर से अंतरिम अध्यक्ष बना दिया गया।

● **दिल्ली से रेणु आगाल**

88 अध्यक्षों में से सिर्फ 6 ही नेहरू-गांधी परिवार से रहे

काबिले-गौर है कि मोतीलाल नेहरू से राहुल गांधी तक नेहरू परिवार के सिर्फ 6 लोग ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। गौरतलब है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। 1885 में बोमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद 1886 में दादाभाई नौरोजी, 1887 में बदरूद्दीन तैय्यबजी, 1888 में जार्ज यूल, 1889 में सर विलियम वेडरबर्न, 1890 में सर फिरोजशाह मेहता, 1891 में पी. आनंद चार्लू, 1892 में बोमेश चन्द्र बनर्जी, 1893 में दादाभाई नौरोजी, 1894 में अलफरेड वेब, 1895 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, 1896 में रहीमतुल्ला सयानी, 1897 में सी. शंकरन नायर, 1898 में आनंद मोहन बोस, 1899 में रमेश चंद्र दत्त, 1900 में एनजी चंद्रावरकर, 1901 में दिनशा इदुलजी वाचा, 1902 में एसएन बनर्जी, 1903 में लाल मोहन घोष, 1904 में सर हैनरी कटन, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, 1906 में दादाभाई नौरोजी, 1907 में डॉ. रास बिहारी घोष, 1909 में मदन मोहन मालवीय, 1910 में सर विलियम वेडर्बन, 1911 में पंडित बिशन नारायण धर, 1912 में आरएन माधोलकर, 1913 में सैयद मोहम्मद बहादुर, 1914 में भूपेंद्रनाथ बसु, 1915 में सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, 1916 में अम्बिका चरण मजूमदार, 1917 में एनी बेसेंट, 1918 में हसन इमाम और मदनमोहन मालवीय, 1919 में मोतीलाल नेहरू, 1920 में सी. विजया राघवाचारियर, 1921 में सीआर दास, 1923 में लाला लाजपत राय और मुहम्मद अली, 1924 में मोहनदास गांधी, 1925 में सरोजिनी नायडू, 1926 में एस. श्रीनिवास आयंगार, 1927 में डॉ. एमए अंसारी, 1928 में मोतीलाल नेहरू, 1929 में जवाहरलाल नेहरू, 1931 में सरदार वल्लभभाई पटेल, 1932 में आर अमृतलाल, 1933 में नेल्ली सेन गुप्ता, 1934 में बाबू राजेंद्र प्रसाद, 1936 में जवाहरलाल नेहरू, 1938 में सुभाष चंद्र बोस, 1940 में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, 1946 में जवाहरलाल नेहरू और सितंबर 1946 में आचार्य जेबी कृपलानी पार्टी अध्यक्ष बने। आजादी के बाद 1948 में बी. पट्टाभि सीतारमय्या कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन, 1951 में जवाहरलाल नेहरू, 1955 में यूएन ढेबर, 1960 में इंदिरा गांधी, 1961 में एन संजीव रेड्डी, 1962 में डी. संजिवैया, 1964 में के कामराज, 1968 में एस. निजिलिंगप्पा, 1969 में सी सुब्रमण्यम, 1970 में जगजीवन राम, 1971 में डी संजिवैया, 1972 में डॉ. शंकर दयाल शर्मा, 1975 में देवकांत बरूआ, 1976 में ब्रह्मनंदा रेड्डी और 1978 में इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनीं। इंदिरा गांधी की मौत के बाद पंडित कमलापति त्रिपाठी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। फिर 1984 में राजीव गांधी को पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। उनके बाद 1991 में पीवी नरसिम्हा राव, 1996 में सीताराम केसरी और 1998 में सोनिया गांधी को सर्वसम्मति से कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 2017 में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया गया।

दंडकारण्य में बदलाव की करवट

अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से 2018 में जारी एक रिपोर्ट में यह बात कही गई कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बने नक्सली दुनिया के चौथे सबसे खतरनाक आतंकी संगठन हैं। देश में जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य में होने वाले आतंकी हमलों की तुलना में नक्सली हिंसा ने अधिक सुरक्षाकर्मियों की जानें ली है। सीपीआई माओवादी को विश्व का चौथा सबसे खतरनाक संगठन करार देते हुए 2018 की अमेरिकी स्टडी में कहा गया कि भारत में हुए 53 प्रतिशत हमलों में इसका हाथ रहा है। हालांकि, इस अध्ययन के मुताबिक, भारत में 2016 और 2017 के बीच नक्सली हमलों में कमी आई है। नक्सलवाद सिर्फ देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं है बल्कि राजनीतिक और आर्थिक समस्या के साथ-साथ एक विकट सामाजिक समस्या भी है। नक्सलवाद ने अब तक हजारों लोगों की जानें ली हैं। जब भी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरों की बात आती है, तो नक्सलवाद सबसे पहले आता है। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। इतिहास गवाह है कि वैचारिक भटकाव, स्वार्थलिप्सा और छलावा जैसी प्रवृत्तियां किसी भी आंदोलन या क्रांति की कब्रगाह साबित होती हैं। ऐसा ही कुछ नक्सल आंदोलन के साथ हो रहा है। माओवादी विचारधारा या कथित क्रांति से मोहभंग की लगातार आ रही खबरें इन दिनों दंडकारण्य के जंगलों में जबरदस्त हलचल पैदा कर रही हैं। प्राय: रोजाना ही नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने और हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास की मुख्यधारा के सहयात्री बनने की खबरें बता रही हैं कि गलियारे का लाल रंग तेजी से फीका पड़ता जा रहा है। जिन्होंने कभी विचारधारा के नाम पर बंदूकें उठाई थीं, आज वे व्यवस्था के मददगार बन रहे हैं। सवाल है कि नक्सलवाद की जमीन कैसे हिल रही है?

अभी हाल ही में दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा ब्लॉक स्थित नहाड़ी गांव से खबर आई कि ग्रामीणों ने वहां ढहाए गए एक स्कूल की इमारत दोबारा खड़ी कर दी है। 13 साल पहले इस स्कूल को नक्सलियों ने बम से उड़ा दिया था। तब से गांव के बच्चों को घने जंगलों के बीच 7 किमी का सफर तय करके एक अन्य स्कूल जाना पड़ रहा था। इधर हाल ही में जब सुरक्षाबलों ने वहां शिविर लगाया तो नहाड़ी के ग्रामीणों ने नक्सली डर और धमकियों को दरकिनार करते हुए एक बड़ी झोपड़ी तैयार की और उस पर एस्बेस्टस की छत डालकर स्कूल खड़ा कर दिया। हाल के दिनों में दंतेवाड़ा के अलावा सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जैसे धुर नक्सल प्रभावित जिलों से दर्जनों नक्सली बंदूक से बदलाव लाने के भ्रम से बाहर आकर हथियार डाल चुके हैं। रक्षाबंधन के मौके पर एक नक्सली अपनी बहन की पुकार पर हमेशा के लिए घर लौट आया। प्रभावित इलाके के कई अन्य गांवों ने भी नक्सलवाद को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। अभी पिछले दिनों नक्सलियों के शहीदी सप्ताह जैसे अहम मौके पर कुछ गांवों में तो अलग ही साहसिक पहल देखने को मिली। सुरक्षाबलों के अभियान के दौरान मारे गए नक्सलियों की याद में निर्मित कई पक्के स्मारकों को ग्रामीणों ने हथौड़े और फावड़े से ढहा दिया। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि नक्सली संगठन इसे किस तरह से लेंगे। एक तरह से यह व्यवस्था के प्रति जंगल की नाराजगी या फिर विभ्रम दूर होने के संकेत हैं। क्षेत्रवासियों को शायद अब ऐसा लगने लगा है कि पुलिस और प्रशासन उनके दुश्मन नहीं, बल्कि मददगार हैं। लोगों को अहसास हो गया है कि विकास और हक दिलाने के नाम पर लंबे समय से चल रहे इस कथित क्रांति के बावजूद आदिम समाज आज भी जस का तस वहीं खड़ा है। दूसरी ओर, नक्सल नेता और कमांडर ऐशोआराम की जिंदगी जी रहे हैं। इनके पास अथाह पैसा है और इनके बच्चे जंगलों से बहुत दूर महानगरों में सुविधा संपन्न जीवन जी रहे हैं। ये सारी बातें छन-छनकर जंगलों में भी पहुंच रही हैं और नक्सलवाद तेजी से अपनी सहानुभूति खो रहा है। उससे तो यही लगता है कि करीब चार दशक से रक्त-पथ पर लहूलुहान दंडकारण्य बदलाव की करवट लेने जा रहा है।

दरअसल, पिछले एक साल के दौरान दंडकारण्य में नक्सली आंदोलन के 9 बड़े माओवादी नेताओं की मौत हो गई है। इससे आंदोलन कमजोर पड़ता जा रहा है। ऐसे में नक्सली नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है। इसका प्रभाव यह पड़ा है कि बड़ी संख्या में नक्सलियों का आंदोलन से मोहभंग हो गया है। वे अब मुख्यधारा में लौटने के लिए पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

तेजी से सिकुड़ रहा नक्सली आंदोलन

दंडकारण्य समेत देशभर में तेजी से सिकुड़ रहा नक्सली आंदोलन 9 बड़े नक्सली नेताओं की मौत से और भी कमजोर हो गया है। दंडकारण्य में साढ़े तीन दशक तक नक्सलवाद की कमान संभालने वाले रावुलू श्रीनिवास उर्फ रमन्ना की मौत के 8 महीने बाद भी नक्सली उसकी जगह नया नेता नहीं तलाश पाए हैं। ऐसे में आधा दर्जन से अधिक बड़े नेताओं की मौत से नक्सल संगठन में बिखराव की आंशका जताई जा रही है। रमन्ना दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सचिव तथा सेंट्रल कमेटी का सदस्य था। उसकी मौत से नक्सली आंदोलन को बड़ा झटका लगा है। इसका खुलासा नक्सली संगठनों ने शहीदी सप्ताह के दौरान पर्चा जारी कर किया था। उसमें रमन्ना के अलावा 8 और बड़े नेताओं की मौत का ब्यौरा दिया गया है। नक्सलियों ने माना है कि बीते एक साल में बीमारी, मुठभेड़ और कथित मुठभेड़ों में उनके 105 साथी मारे गए हैं। यह आंकड़ा देशभर में मारे गए नक्सलियों से संबंधित है। बिहार-झारखंड के चार, दंडकारण्य के 67, आंध्र-ओडिशा बॉर्डर इलाके के 14, सेंट्रल रिजर्व कमेटी नंबर दो का एक सदस्य, महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ (एमएमसी) जोन के 9 तथा पश्चिमी घाट इलाके के 4 नक्सली बीते एक साल में मारे गए हैं। नक्सलियों ने मौत से हुए नुकसान के क्रम में रमन्ना की मौत को सबसे ऊपर रखा है।

बंगला नंबर-2

पिछले हफ्ते शरद पवार के पोते पार्थ पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख द्वारा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग के लिए सार्वजनिक रूप से फटकार खाने के बाद, उनके मुंबई आवास पर उनसे मिलने गए। टेलीविजन कैमरों और पत्रकारों का एक दल पहले से ही गेट पर उनका इंतजार कर रहा था। 30 वर्षीय पार्थ, जब अपनी चाची और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से मिलकर दो घंटे बाद निकले तो पत्रकारों ने उनसे कई सवाल पूछे।

दक्षिण मुंबई स्थित भुलाभाई देसाई रोड वाले सिल्वर ओक बंगले के लिए ये एक और बड़ा दिन था जो पवार के उदय के बाद से महाराष्ट्र की राजधानी में सबसे महत्वपूर्ण और नए राजनीतिक ठिकानों में से एक बन गया है। पवार शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के तीन दलों वाले महागठबंधन सरकार के सूत्रधार हैं। नाम न बताने की शर्त पर एक एनसीपी नेता ने कहा, 'एमवीए सरकार के सत्ता में आने के बाद से सिल्वर ओक सुर्खियों में रहा है। यहां कई और गतिविधियां हुई हैं, जिनमें विभिन्न दलों के राजनीतिक नेताओं द्वारा की गई यात्राएं शामिल हैं। यह मीडिया के लिए एक नियमित स्थान बन गया है।'

22,000 वर्ग फीट में फैला सिल्वर ओक एस्टेट, विशेष रूप से 1990 के दशक तक पारसी समुदाय के लिए था, जब यह 'धर्मनिरपेक्ष' था। पवार 2013 में पेडर रोड पर रामालय बिल्डिंग के अपने पिछले निवास से बंगला नंबर 2 में चले गए, जहां दिवंगत कांग्रेस नेता मुरली देवड़ा भी रहते थे। इसलिए, सिल्वर ओक का राजनीतिक पता मुंबई में ज्यादा पुराना नहीं है, जैसे मातोश्री (शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे, और अब उद्धव ठाकरे का घर), वर्षा (मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास), और सह्याद्री (राज्य सरकार का आधिकारिक गेस्ट हाउस) है।

मातोश्री, वर्षा या सह्याद्री के विपरीत, दो मंजिला बंगला भी काफी अलौकिक है। तीनों अन्य जगहों पर कड़ी सुरक्षा का इंतजाम है जहां किसी भी बाहरी लोगों के लिए प्रवेश वर्जित है लेकिन 2 सिल्वर ओक इससे बिल्कुल अलग है। राजनीतिक टिप्पणीकार प्रताप अस्बे कहते हैं, 'सिल्वर ओक में कोई भी सीधे जा सकता है। यहां मातोश्री जैसे सुरक्षा के कई स्तर नहीं हैं। सुरक्षा गार्ड आपको बताते हैं कि शरद पवार अंदर हैं या नहीं। आप वहां इंतजार कर सकते हैं और बिना किसी परेशानी के अंदर जा सकते हैं। यह लगभग एक राजनीतिक पार्टी के कार्यालय की तरह है।'

एनसीपी के एक विधायक ने कहा कि पवार के घर के ग्राउंड फ्लोर पर एक छोटा कार्यालय है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के निजी सहायक और कुछ अन्य लोग बैठते हैं। विधायक ने कहा, 'सुरक्षा गार्ड सिर्फ इतना कहते हुए एक नोट में भेजते हैं कि कौन आया है और कहां से हैं। पवार उनके घर आए हर व्यक्ति से मिलते हैं, चाहे मिलने का समय पहले लिया हो या नहीं।' विधायक ने पूछा, 'मैंने सुरक्षा गार्डों को थोड़ा और सतर्क रहने के लिए कहा है, वो भी आज के राजनीतिक रूप से प्रेरित घृणा के युग में। हमारे बहुत सारे कर्यकर्ता बिना ज्यादा छानबीन के जाते हैं। हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि वे वास्तव में हमारे कार्यकर्ता हैं?'

महाराष्ट्र चुनाव के बाद ये बंगला विशेष रूप से पिछले साल नवंबर में सुर्खियों में रहा था। पत्रकारों को सिल्वर ओक के सूत्रों से कई जानकारियां मिली, जब राजनीतिक ड्रामा चल रहा था- शिवसेना ने भाजपा के साथ संबंध तोड़ दिया, एनसीपी और कांग्रेस ने शिवसेना के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश की, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी नेता अजित पवार को अपने साथ लेकर शपथ ली। फिर, गठबंधन को अंतिम रूप दिया गया, फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया, अजित पवार एनसीपी में लौट आए और आखिरकार 28 नवंबर को एमवीए सरकार बनी। इस दौरान, ठाकरे ने भी सिल्वर ओक में शरद पवार के साथ बैठक की। यह दुर्लभ था क्योंकि उद्धव अपने पिता बाल ठाकरे की तरह लगभग सभी बैठकें और प्रेस कॉन्फ्रेंस मातोश्री में करने के लिए जाने जाते हैं, जबकि पवार हमेशा उन्हें अपने घर के बाहर रखना पसंद करते हैं- या तो एनसीपी कार्यालय में या नरीमन प्वाइंट स्थित वाईबी चव्हाण सेंटर में।

शरद पवार के मीडिया को संभालने वाले दल के एक अधिकारी ने कहा, 'अब भी, सिल्वर ओक में कुछ खास मौकों पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, केवल जरूरी मुद्दों पर।' एक पत्रकार जो कई वर्षों से एनसीपी को कवर कर रहे हैं, ने कहा कि सिल्वर ओक में बैठकें तभी होती हैं जब पार्टी के नेता पवार से मिलने आते हैं। नाम न बताने की शर्त पर उन्होंने कहा, 'एनसीपी के सत्ता में आने के बाद से इसमें तेजी आई है।' उदाहरण के लिए, पिछले हफ्ते ही उप मुख्यमंत्री अजित पवार, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले और पार्टी के राज्य प्रमुख जयंत पाटिल ने पार्थ को फटकार लगाने के बाद सिल्वर ओक में शरद पवार के साथ बैठक की। चूंकि पवार इस गठबंधन को एकसाथ जोड़े हुए हैं इसलिए यह भी कहा जाता है कि एमवीए सरकार का रिमोट कंट्रोल सिल्वर ओक में है। ठीक उसी तरह जैसे 1995-99 तक शिवसेना की अगुवाई वाली सरकार में कहा जाता था कि इसका रिमोट कंट्रोल मातोश्री में है।

● **बिन्दु माथुर**

दूसरा महत्वपूर्ण पता

मातोश्री, वर्षा और सह्याद्री भी मुंबई के राजनीति के प्रमुख स्थान हैं, हालांकि मातोश्री ने बाकी दोनों के महत्व को कम जरूर किया है। मुंबई के मालाबार हिल स्थित वर्षा में राजनीतिक गतिविधि तब कम होनी शुरू हो गईं जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आधिकारिक घर में रहने से मना कर दिया और मातोश्री से ही काम जारी रखा। उन्होंने वहीं से महत्वपूर्ण बैठकें कीं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य पर नजर बनाए रखी खासकर महाराष्ट्र में कोरोना फैलने के बाद। हालांकि पिछले कुछ महीनों में एक बंगला राजनीति का केंद्र बनकर उभरा है- पूर्ववर्ती मेयर का बंगला, जो कि शिवाजी पार्क के पास स्थित है। जो अब प्रस्तावित बाल ठाकरे स्मारक स्थल है। उद्धव ठाकरे ने शरद और अजित पवार के साथ यहां बैठकें कीं।

नाम पर राजनीति

अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर का भूमिपूजन 5 अगस्त को किया जा चुका है। मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने के साथ ही अब मस्जिद को लेकर भी तैयारियां तेज हो गई हैं। यही नहीं, 5 एकड़ जमीन पर बनने वाली मस्जिद का नाम भी लगभग तय कर लिया गया है। अयोध्या शहर के बाहर 5 एकड़ जमीन पर बनने वाली मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर नहीं होगा, बल्कि मस्जिद को उसी नाम से जाना जाएगा, जिस जगह पर यह बनने जा रही है। मस्जिद निर्माण के लिए बनाए गए ट्रस्ट की ओर से कहा गया है कि वह इस बार किसी भी विवाद में नहीं फंसना चाहते हैं। इसके चलते अब किसी भी शासक के नाम पर मस्जिद का नाम नहीं होगा। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से गठित इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सचिव अतहर हुसैन का कहना है, मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन अयोध्या के रौनाही कस्बे के धन्नीपुर में दी गई है। ऐसे में अब धन्नीपुर में ही मस्जिद का निर्माण होगा तो मस्जिद का नाम भी धन्नीपुर गांव के नाम पर ही होगा। उन्होंने बताया है कि पहले मस्जिद के नामों में अमन मस्जिद और सूफी मस्जिद पर भी विचार किया गया था लेकिन अब इस मस्जिद का नाम धन्नीपुर ही होगा।

गौरतलब है कि नई मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद होना चाहिए तो कोई कह रहा है कि नई मस्जिद वैसे ही बननी चाहिए जैसा ढांचा बाबरी मस्जिद का था। अत: तीन गुम्बद वाली मस्जिद बनानी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी कुछ मुस्लिम धर्मगुरु और नेता यही राग अलाप रहे हैं कि भले ही बाबरी मस्जिद नेस्तनाबूत कर दी गई हो, लेकिन वह जगह कयामत तक मस्जिद ही रहेगी। इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी सोशल मीडिया पर भी हो रही है। यहां तक कि सोशल मीडिया पर रामलला के मंदिर निर्माण को कुछ 'दहशतगर्द' मोदी सरकार का हिंदुत्व एजेंडा बताते हुए इसे उनका (मोदी सरकार) भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का पहला कदम बता रहे हैं।

वाकयुद्ध में ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड (आईएमपीएलबी) भी कूदने से पीछे नहीं रहा। बाद में फजीहत होने पर जरूर वह अपने बयान से पीछे हट गया। दरअसल मामला राम मंदिर के भूमिपूजन से ठीक पहले का है, जब आईएमपीएलबी ने ट्वीट कर कहा था कि बाबरी मस्जिद थी और हमेशा के लिए एक मस्जिद रहेगी। बोर्ड ने अपने ट्वीट में लिखा था, 'बाबरी मस्जिद थी और हमेशा एक मस्जिद रहेगी। हागिया सोफिया हमारे लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। अन्यायपूर्ण, दमनकारी, शर्मनाक और बहुसंख्यक तुष्टिकरण के आधार पर भूमि का पुनर्निर्धारण निर्णय इसे बदल नहीं सकता है। दिल टूटने की जरूरत नहीं है, स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती है।' हालांकि विवाद होने के बाद बोर्ड द्वारा ट्वीट को डिलीट कर दिया गया था। विवादित ट्वीट पर बोर्ड के सचिव व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जफरयाब जिलानी ने सफाई भी दी थी। उन्होंने कहा था कि ये ट्वीट महासचिव की मंजूरी के बिना किया गया था, इसीलिए इसे डिलीट कर दिया गया है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं।

इस सब से इतर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा ने सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड को सुझाव दिया है- अयोध्या में बन रही मस्जिद का नाम अगर रखना है तो मोहम्मद साहब के नाम पर नाम रखा जाए और इसे 'मस्जिद-ए-मोहम्मदी' का नाम दिया जाए। मोहसिन रजा ने कहा कि इस देश में बाबर के नाम पर कोई भी चीज स्वीकार नहीं होगी। वह मस्जिद हो या कोई और क्योंकि बाबर ने कोई अच्छा काम नहीं किया। बाबर के नाम पर मुसलमानों के सभी फिरके भी एकमत नहीं होंगे और हम भी तो स्वीकार नहीं करेंगे।

मोहसिन रजा ने कहा, 'जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम पुरुषों में उत्तम हैं, उसी तरीके से पैगंबर मोहम्मद साहब मुसलमानों में महापुरुष हैं और उन्हें हिंदुओं में भी उतना ही सम्मान प्राप्त है इसलिए अगर इस मस्जिद का नाम ही रखना है तो इसका नाम 'मस्जिद-ए-मोहम्मदी' रखा जाए, यह मेरा सुझाव सुन्नी बोर्ड को है।' मोहसिन रजा ने कहा, रही बात योगीजी के वहां के कार्यक्रम में शामिल होने की तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उन्हें मस्जिद बनाने की अनुमति मिली है तो वहां मस्जिद बनेगी और जब भी किसी अच्छे काम के लिए किसी को भी बुलाया जाएगा, चाहे मुझे बुलाया जाए या फिर भाजपा में किसी भी बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को, तो सभी लोग जाएंगे, अच्छे काम के लिए हम लोग सभी जगह जाते हैं। बहरहाल, इस सबके बीच सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने साफ किया है कि अयोध्या में दी गई जमीन पर बनने वाली मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद के नाम पर नहीं होगा। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के प्रवक्ता के अनुसार, मस्जिद निर्माण में शिलान्यास के कार्यक्रम की इस्लाम में इजाजत नहीं है। सिर्फ नींव खोद कर मस्जिद की शुरुआत होती है, लेकिन इस जमीन पर जब अस्पताल या फिर ट्रस्ट के भवन की नींव रखी जाएगी तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया जाएगा।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

3 महीने में शुरू होगा निर्माण

मस्जिद के निर्माण को लेकर यह जानकारी भी सामने आई है कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करने के लिए 2 बैंक खाते भी खोले जाएंगे। इसके जरिए मस्जिद निर्माण के लिए चंदे की राशि जुटाई जाएगी। इनमें से एक खाता मस्जिद निर्माण के लिए होगा जबकि दूसरे खाते में आए पैसे से मस्जिद के आसपास बनने वाले अस्पताल, सामुदायिक रसोईघर और शैक्षणिक केंद्र बनाया जाएगा। बोर्ड का कहना है कि मेड़बंदी का काम शुरू कर दिया गया है और आने वाले 3 महीनों में मस्जिद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में यह चर्चा लगातार चल रही थी कि अयोध्या के पास रौनाही के धन्नीपुर गांव में बनने वाली मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर होगा, जिसे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने खारिज कर दिया और इसे अफवाह बताया। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने हाल ही में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट का निर्माण किया है जो अयोध्या में मस्जिद और उसके साथ-साथ अस्पताल, कम्युनिटी सेंटर और कम्युनिटी किचन बनाएगा। साथ ही वहां इस्लामिक मामलों पर एक रिसर्च सेंटर भी होगा।

राजनीति के महा जादूगर

मप्र की तरह राजस्थान में भी कांग्रेस में असंतोष के बाद सत्ता पर संकट मंडराया था, लेकिन राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत ने जिस सूझबूझ के साथ इस संकट का सामना और खात्मा किया इससे उन्होंने अपने जादूगरी का एक बार फिर से लोहा मनवा दिया है। मप्र में कमलनाथ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, लेकिन गहलोत जयपुर से लेकर दिल्ली तक संकट को खत्म करने के लिए मोर्चा संभाले रहे। मुख्यमंत्री गहलोत के अनुभव और जादुई नेतृत्व ने सचिन पायलट और भाजपा की उस योजना को ऐसी पटखनी दी है कि आने वाले कई समय तक राजनीतिक गलियारों में इसका जिक्र होगा। होना भी चाहिए, एक के बाद एक राज्यों में **खरीद फरोख्त, दल-बदल कानून** की धज्जियां उड़ाकर संविधान की भावना के साथ खिलवाड़ करते हुए जनता की चुनी हुई सरकारें गिर रही हैं। खास बात यह है कि सभी जगह कांग्रेस की ही सरकारें गिर रही हैं, उससे बड़ी बात यह है कि सभी जगह भाजपा की सरकार बन रही है। पूरे देश में कांग्रेस के अब तक 110 विधायक बागी होकर भाजपा से मिलकर नई सरकारें बना चुके हैं। भाजपा लाख सच छुपाए, सच छुप नहीं सकता। राजस्थान के सियासी खेल में भी पायलट और भाजपा का गठजोड़ था, लेकिन यहां कामयाबी नहीं मिल सकी। क्योंकि यहां कांग्रेस के पास अशोक गहलोत जैसा मजबूत अनुभवी नेता बैठा है।

गहलोत ने अपने राजनीतिक चातुर्य से भाजपा और पायलट की रणनीति को ऐसी पटखनी दी कि भाजपा खुद अपने विधायकों को बचाने के काम में लग गई, वहीं पायलट खेमा चुपचाप गहलोत शरणम् गच्छामी हो गया। यह मुख्यमंत्री गहलोत की केवल जादूगरी नहीं है बल्कि महाजादूगरी कही जानी चाहिए। मुख्यमंत्री गहलोत ने इतनी तगड़ी किलेबंदी की, कि कांग्रेस खेमे में बैठा एक भी विधायक इधर से उधर नहीं हो सका। सचिन पायलट ने जिस अंदाज के साथ 18 विधायकों को लेकर गहलोत के खिलाफ महासंग्राम शुरू किया था, उन्हें अपनी सारे राजनीतिक हथियार डालकर गहलोत के पास आगे होकर आना पड़ गया। घटनाक्रम कैसे भी चला हो, कुछ भी हुआ हो, गहलोत सरकार गिराने के लिए जिस तरह पायलट अहसाय हो गए, ठीक वैसा ही हाल भाजपा का भी था। गहलोत के द्वारा एक के बाद एक ऐसे निर्णय किए गए कि विपक्षी खेमे के होश उड़ गए। कई राज्यों में कांग्रेस विधायकों का सहारा लेकर कांग्रेस की सरकारों को गिरा चुकी भाजपा की स्थिति तो ऐसी हो गई कि उसके नेताओं ने यह कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कि यह कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा है, उसे इससे कोई लेना-देना नहीं है। यहां तक कि भाजपा ने एक बार भी नहीं कहा कि गहलोत सरकार अल्पमत में है, उसे बहुमत साबित करना चाहिए। बल्कि नहले पे देहला यह रहा कि गहलोत खुद ही बहुमत लेकर राजभवन पहुंच गए, बोले-बुलाईए विधानसभा का सत्र।

इतनी हिम्मत कौन मुख्यमंत्री कर सकता है, वो भी तब जब उसकी पार्टी के 19 विधायक बागी हो चुके हों। यह काम देश में पहली बार गहलोत सरकार ने करके दिखाया है। गहलोत की रणनीति इतनी मजबूत रही कि भाजपा और पायलट का प्लान हर दिन बदलता चला गया। आखिर में दोनों के पास एक-दूसरे से दूर होने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। इस पूरे सियासी संग्राम में जहां एक ओर मुख्यमंत्री गहलोत ने लोकतंत्र और अपनी सरकार को बचाया, बल्कि विधायकों की खरीद-फरोख्त संबंधी ऑडियोटेप जारी कर लोकतंत्र विरोधी मुहिम में शामिल किए जाने वाले हथकंडों को एक्सपोज भी किया। मुख्यमंत्री गहलोत बहुत पहले से यह बात बोलते आ रहे हैं कि देश में चुनी हुई सरकारों को गिराने का षड्यंत्र किया जा रहा है। गहलोत ने बाकायदा अमित शाह का नाम लेकर बोला कि वो हमेशा सरकारें गिराने का ही सपना देखते रहते हैं, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं होगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने पायलट से ज्यादा बड़े हमले भाजपा पर किए, कहा कि भाजपा कि खट्टर सरकार न सिर्फ कांग्रेस विधायकों की मेहमान नवाजी में लगी है बल्कि उनको हरियाणा पुलिस बल के बीच बैठा रखा है।

मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को गिराने की बात अच्छी नहीं है। यह नैतिक नहीं है। खुद अपना उदाहरण देते हुए बताया कि भाजपा के भैरोंसिंह शेखावत की बीमारी के मौके पर वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष थे। कुछ लोगों ने उनकी सरकार को ऐसे मौके पर गिराने का षड्यंत्र रचा। लेकिन खुद गहलोत ने पहल करते हुए उस षड्यंत्र को नाकाम कर दिया। गहलोत बार-बार कहते रहे कि चुनी हुई सरकारों को गिराने की परंपरा अच्छी नहीं है। कम से कम राजस्थान में तो ऐसा किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। चाहे सरकार किसी की भी हो।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

पायलट और समर्थकों के सामने विकल्प नहीं

मुख्यमंत्री गहलोत ने सचिन पायलट खेमे के लिए ऐसी स्थिति खड़ी कर दी कि उनके पास दो ही विकल्प बचे, या तो अपने इस्तीफे दे दें या फिर खामोशी के साथ, बिना शर्त लौटकर आ जाएं वापस। हुआ भी वही, मुख्यमंत्री गहलोत से नाराज होकर गए सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद से अशोक गहलोत को हटाने के लिए अपनी सबसे बड़ी और पहली मांग ही छोड़नी पड़ गई। इसी बात को लेकर ही तो पायलट ने बागी बनकर संग्राम शुरू किया था। लेकिन गहलोत ने उन्हें हाशिए पर ला दिया। पायलट दो दिन की और देरी कर देते दो काम होने निश्चित थे, **पहला**- पायलट के 18 विधायकों का खेमा आधा रह जाता, **दूसरा**- बाकी बचे विधायकों की विधायकी भी जाती और 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य भी साबित हो जाते। यानी कि पूरे राजनीतिक कैरियर पर काफी समय के लिए प्रश्न चिन्ह लग जाता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस राजनीतिक महासंग्राम को जीतकर साबित कर दिया कि वो अब राजनीति के केवल जादूगर नहीं बल्कि महाजादूगर हो गए हैं।

नीतीश की सेंधमारी

सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच का रास्ता खोलकर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से मुद्दा झटक लिया है, फिर एक के बाद एक लगातार झटके देते जा रहे हैं। चंद्रिका राय को जेडीयू में लाकर नीतीश कुमार ने लालू यादव को जो झटका दिया है उससे उबर पाना तेजस्वी यादव के लिए अकेले काफी मुश्किल होने वाला है। तेजस्वी यादव के लिए जीतनराम मांझी का महागठबंधन छोड़कर जाना कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन चंद्रिका राय का जेडीयू ज्वाइन कर लेना बहुत बड़ा नुकसान है, और वो इसलिए भी क्योंकि वो तेजस्वी यादव की चुनावी घेरेबंदी में मुख्य भूमिका निभाने की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं।

लालू प्रसाद की गैरहाजिरी में नीतीश कुमार न सिर्फ आरजेडी को खोखला करते जा रहे हैं, बल्कि तेजस्वी यादव को चारों तरफ से घेरते जा रहे हैं और तेजस्वी को लेकर कहते हैं जिसके पास कोई काम नहीं होता वो ट्वीट करता है। लालू परिवार के लिए धीरे-धीरे नीतीश कुमार हद से ज्यादा **खतरनाक होते जा रहे हैं** और ऐसा भी नहीं है कि तेजस्वी यादव ऐसी बातों से बेखबर हैं, लेकिन नीतीश कुमार के सामने उनका वैसा ही हाल हो रहा है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का। वैसे भी दोनों एक ही तरीके की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जूझ रहे हैं।

जंग कोई भी हो, किसी करीबी के विरोधी के पाले में चले जाने से ज्यादा खतरनाक कुछ और नहीं होता। बिहार चुनाव के ऐन पहले लालू प्रसाद के समधी चंद्रिका राय का नीतीश कुमार को नेता मान लेना बिलकुल वैसा ही है। साथ ही, चंद्रिका राय का बेटी ऐश्वर्या के चुनावी इरादे की तरफ इशारा करना इसे और भी खतरनाक बना रहा है। अव्वल तो चंद्रिका राय ने सीधे-सीधे ऐसी कोई बात नहीं कही है कि उनकी बेटी ऐश्वर्या चुनाव लड़ने ही जा रही हैं, लेकिन सवालों के जवाब में जो संकेत दिया है उससे तो ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल नहीं हो रहा है कि उनकी विधानसभा सीट कौन सी होगी?

लालू यादव और चंद्रिका राय के बीच बदले की लड़ाई तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन ऐश्वर्या ससुराल छोड़कर मायके शिफ्ट हो गईं। ऐश्वर्या का लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव के साथ तलाक का मुकदमा चल रहा है। चंद्रिका राय ने लालू परिवार के राजनीतिक विरोधी नीतीश कुमार से हाथ मिलाकर एक तरीके से बदले का राजनीतिक ऐलान कर दिया है। चंद्रिका राय से पहले तेजस्वी यादव ने ही दबाव की राजनीति शुरू की थी और ये उसी का प्रतिक्रियात्मक जवाब है। तेजस्वी यादव ने चंद्रिका राय को चुनौती देने के लिए उनके ही परिवार की डॉक्टर करिश्मा राय को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का संकेत दिया था। चंद्रिका राय के बड़े भाई विधानचंद राय की बेटी करिश्मा राय पहले ही आरजेडी ज्वाइन कर चुकी हैं और माना जाता है कि वो आने वाले चुनाव में चंद्रिका राय को चैलेंज कर सकती हैं। करिश्मा का अपने इलाके के लोगों से लगातार मिलना-जुलना चुनाव की तैयारियों से जोड़कर ही देखा जा रहा है। चंद्रिका राय की नई राजनीतिक राह को तेजस्वी के इस कदम का काउंटर भी माना जा सकता है।

चार कदम आगे की सोचते हैं सुशासन बाबू

नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति का चाणक्य यूं ही तो नहीं कहा जाता है। अगर तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार की संभावित राजनीतिक चालों का अंदाजा लगाते हुए रणनीति तैयार कर सकते हैं तो जेडीयू नेता तो चार कदम आगे ही सोचेंगे। यही वजह है कि ऐश्वर्या के लिए विधानसभा चुनाव जीतने से बड़े रोल वाली स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। दरअसल, नीतीश कुमार की कोशिश इस बार चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनना भर नहीं है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करना है। अगर नीतीश कुमार ऐसा कर पाते हैं तो भाजपा पर दबदबा कायम रखने में सफल रहेंगे। भाजपा भी नीतीश कुमार को एनडीए का नेता घोषित करने के साथ-साथ उनकी जीत पक्की करना इसलिए भी चाहती है ताकि बिहार के राजनीतिक पटल पर आरजेडी का हाल भी वैसा ही हो जाए जैसा राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का है।

करिश्मा राय की ही तरह तेजस्वी यादव श्याम रजक की आरजेडी में वापसी कराकर भी इतरा रहे होंगे, लेकिन मालूम होना चाहिए कि नीतीश कुमार ने हाल फिलहाल आरजेडी के जिन छह विधायकों को हथिया लिया है उनमें दो यादव हैं और एक मुस्लिम, यानी नीतीश कुमार अब लालू प्रसाद के सबसे कारगर और कामयाब चुनावी नुस्खे माय फैक्टर पर भी हाथ डाल दिया है। मालूम नहीं तेजस्वी यादव अपने खिलाफ ऐसी राजनीतिक चालों से वाकिफ हैं भी या नहीं?

चंद्रिका राय ने पूछे गए सवाल का सीधा जवाब तो नहीं दिया लेकिन नया सवाल पूछकर तस्वीर जरूर साफ कर दी। चंद्रिका राय ने पूछा कि दोनों भाई कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये जानकारी हो तो बता दीजिए। फिर बोले, सुना है दोनों भाई सुरक्षित सीट तलाश रहे हैं। तेजस्वी यादव फिलहाल बिहार की राघोपुर विधानसभा से और तेजप्रताप यादव महुआ सीट से विधायक हैं। चंद्रिका राय के इस सवालिया जवाब के बाद कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि ऐश्वर्या राय चुनाव में महुआ विधानसभा सीट पर तेजप्रताप यादव को चैलेंज कर सकती हैं। बताते हैं कि तेजस्वी यादव को भी अब तक ऐसा ही लग रहा है और वो चाहते भी यही हैं। आरजेडी सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक तेजप्रताप अगले विधानसभा का चुनाव लड़ने से कहीं ज्यादा एमएलसी बनने या राज्यसभा जाने में दिलचस्पी दिखा रहे थे, लेकिन तेजस्वी ने उनको मना लिया और रणनीति यही है कि अगर जेडीयू की तरफ से ऐश्वर्या को चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो तेजप्रताप बाकायदा मुकाबला भी करें।

● **विनोद बक्सरी**

त्रिकोणीय मुकाबला

पिछले दिनों अमेरिकी मध्यस्थता में एक समझौते के तहत जब संयुक्त अरब अमीरात और इजरायल ने घोषणा की कि वे एक-दूसरे के संग सामान्य संबंध स्थापित करेंगे तो उन्होंने दरअसल उस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकारा जो कई सालों से जाहिर थी- अमीरात के अलावा सऊदी अरब और कई अन्य अरब देशों के राष्ट्रीय हित इजरायली हितों के साथ मिलने में निहित थे।

मध्य पूर्व में त्रिकोणीय मुकाबला- ईरान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच क्षेत्रीय प्रभुत्व की होड़- फारसियों, ओटोमन्स और अरबों के बीच पुरानी प्रतिद्वंदिता की आधुनिक पुनरावृत्ति है। इजरायल जब एक तरफ ईरान के कारण अस्तित्व पर खतरा महसूस कर रहा है और वहीं कभी मैत्रीपूर्ण संबंधों वाले तुर्की के खतरा बनने को लेकर सतर्क है तो सही मायने में तार्किक अपेक्षा तो तेल अवीव के अरब देशों की ओर बढ़ने की ही होगी। फिलिस्तीन को लेकर यक्ष प्रश्न ने लंबे समय से इजरायल और अरब ताकतों के बीच गठबंधन को रोक रखा था। इजरायल और अरब देशों ने इसे परे रख दिया है और मध्य पूर्व पर ईरानी-तुर्की आधिपत्य को रोकने की राह पर सह-यात्री बनकर चल पड़े।

समझौते के तहत संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) इस शर्त पर राजनयिक संबंध स्थापित करेगा कि इजरायल कुछ फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर कब्जे और उनकी स्थिति बदलने की अपनी योजनाओं को स्थगित करेगा। जैसा कि पत्रकार अंशेल फेफर ने हारेत्ज को बताया है, यह इजरायली प्रधानमंत्री के लिए राजनयिक स्तर पर तख्तापलट जैसा है क्योंकि 'बेंजामिन नेतन्याहू के पास कभी भी वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर कब्जे की कोई योजना नहीं थी। न कोई समयसीमा थी, न कोई नक्शा, सरकार या कनेसेट में कोई मसौदा लाने का प्रस्ताव भी नहीं था।' नेतन्याहू के लिए यह एक उपलब्धि है क्योंकि उनके पूर्ववर्तियों, जो फिलिस्तीनियों को बड़ी रियायतें देने को तैयार थे, ने केवल सपना देखा था और उन्होंने इसकी कोई कीमत भी नहीं चुकाई, सिर्फ कब्जे की उस योजना के 'अस्थायी निलंबन' की बात कही जो वह कभी करने भी नहीं जा रहे थे।'

निश्चित रूप से, इसका नतीजा यह होगा कि भविष्य में एकतरफा कार्रवाइयों की इजरायल की क्षमता अरब देशों के साथ उसके राजनयिक संबंधों पर निर्भर करेगी, क्योंकि इसके पास खोने के लिए कुछ होगा। वास्तव में, यह तर्क दिया जा सकता है कि फिलीस्तीनी हितों को ज्यादा बेहतर ढंग से पेश किया जा सकेगा जब इजरायल की राजधानी में और ज्यादा अरब देशों के दूतावास होंगे। यद्यपि यूएई का निर्णय अपने आप में बेहद अहम है लेकिन यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या सऊदी अरब भी ऐसा ही करेगा। इस बात के पुख्ता संकेत हैं कि रियाद आज इजरायल के साथ रिश्ते सामान्य बनाने के लिए इतना ज्यादा इच्छुक है जितना वह पहले कभी नहीं रहा। निश्चित तौर पर सऊदी अरब की मौन स्वीकृति के बिना यूएई-इजरायल समझौता संभव नहीं था। फिर भी सऊदी अरब के शाही परिवार में एक पीढ़ीगत मतभिन्नता है खासकर किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच, फिलिस्तीन मसले पर पुरानी पीढ़ी का दृष्टिकोण इजरायल को मान्यता देने के प्रति अधिक रूढ़िवादी रहा है।

सऊदी नेतृत्व को इस तथ्य से भी जूझना पड़ता है कि यदि वह यहूदी राष्ट्र को मान्यता देता है तो सुन्नी इस्लामी देशों के नेता के तौर पर उसे तुर्की-मलेशिया कॉकस से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। बदले में यह राजनीतिक चुनौतियां पेश करने वालों को सामने लाकर आंतरिक स्तर पर सऊदी राजवंश की वैधता को कमजोर कर सकता है। इसलिए, रियाद बेहद सावधानी के साथ लेकिन स्पष्ट तौर पर इजरायल की ओर उन्मुख हो रहा है।

यूएई का कदम मध्य पूर्व में एक पुनर्संगठन का संकेत है जिसका व्यापक असर होगा। एक तो इसने क्षेत्र में इस तरह त्रिकोणीय ध्रुवीकरण बढ़ा दिया है कि देश या तो अरब अथवा ईरान या तुर्की के साथ हैं और उनके दखल से प्रभावित हो रहे हैं। ठीक 1914 से पहले के यूरोप की तरह एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का खतरा बढ़ गया है। लेकिन उस समय के विपरीत, यहां ऐसी बाहरी ताकतें परिदृश्य में हैं जो अपने हितों के कारण मध्य पूर्व में युद्ध नहीं देख सकतीं। इसलिए, क्षेत्र की सुरक्षा अब भी अमेरिका, रूस और चीन के साथ इसके रिश्तों पर निर्भर करती है।

अरब (और इजरायल) के तीनों बाहरी शक्तियों के साथ अच्छे संबंध हैं और चीन एकमात्र बाहरी ताकत है जिसके सभी क्षेत्रीय शक्तियों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अपने हथियार निर्यात, निवेश और क्रय शक्ति के जरिए बीजिंग ने यह सुनिश्चित किया है कि उसे तीनों पक्षों और चारों यदि आप इजरायल को शामिल करें तो, द्वारा एक अहम साझीदार के तौर पर देखा जाए। चीन इस प्रकार मध्य पूर्व समीकरणों के सभी पक्षों का साथ निभा सकता है, जैसे सऊदी वैश्विक शक्ति समीकरण के सभी पक्षों को साध सकता है।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

भारत के लिए अवसर

दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान अपने नए आका चीन के साथ संबंधों के दम पर सऊदी खेमे से दूर जा रहा है। यह सऊदी अरब से हटकर तथाकथित इस्लामिक देशों का नेतृत्व कब्जाने की कवायद में तुर्की और मलेशिया के साथ खड़े होने पर भी विचार कर रहा है। जैसा कि सी. राजामोहन लिखते हैं, 'इस्लामाबाद शायद यह सोचकर दांव लगा रहा है कि अमेरिका मध्य पूर्व से बाहर निकल रहा है और चीन के साथ बढ़ती उसकी सदाबहार रणनीतिक साझेदारी पाकिस्तान को बदलते मध्य पूर्व में नए अवसर देगी। अंतरिम स्तर पर तुर्की और ईरान के साथ गठबंधन की धमकी सऊदी और अमीरात पर दबाव बनाने के साधन के रूप में काम करती है।' भारत के लिए इजरायल और खाड़ी के अरबों के बीच रिश्ते सामान्य होना एक अच्छी बात है क्योंकि इससे क्षेत्र में हमारे जुड़ाव के और अधिक अवसर खुलते हैं। हालांकि, यह बेहद अहम है कि नई दिल्ली मध्य पूर्वी त्रिभुज के किसी एक पक्ष की तरफ न झुके। ईरान भारत के लिए महत्वपूर्ण है और अमेरिका द्वारा इसे अलग-थलग करने की परवाह किए बिना इससे जुड़े रहना चाहिए। पुनर्संगठन के बावजूद अरब देशों, इजरायल और ईरान के साथ संबंध के मामले में भारत बेहतर स्थिति में है।

भोपाल विकास प्राधिकरण

बुकिंग दिनांक 21.08.2020 से 05.09.2020 तक

संपत्ति क्रय करने का सुनहरा अवसर
ऑफर के माध्यम से विक्रय की जाने वाली सम्पत्तियां
नोटः अधिकतम ऑफर मूल्य ही स्वीकार होंगे

रेरा पंजीकृत
रेरा पंजीयन क्र. P-BPL-17-1018

सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना
मिसरोद फेस-2
सार्वजनिक / अर्द्ध सार्वजनिक प्रयोजन के भूखण्ड उपलब्ध

अनु. क्र.	भूखण्ड/इकाई का विवरण	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	प्रयोजन जिस हेतु भूखण्ड/इकाई को आरक्षित रखा गया है	रियायती दरों पर आरक्षित मूल्य	निक्षेप रकम (धरोहर राशि)
1	2	3	4	5	6
1	नर्सरी स्कूल सेक्टर- ए	830 वर्गमीटर	नर्सरी स्कूल	87,64,800/-	8,76,480/-
2	नर्सरी स्कूल सेक्टर- बी	750 वर्गमीटर	नर्सरी स्कूल	79,20,000/-	7,92,000/-
3	धार्मिक स्थान सेक्टर-ई	680 वर्गमीटर	धार्मिक स्थान	71,80,800/-	7,18,080/-
4	प्राईमरी स्कूल सेक्टर-ए	4200 वर्गमीटर	प्राईमरी स्कूल	4,88,98,080/-	48,89,808/-
5	प्राईमरी स्कूल सेक्टर-बी	3440 वर्गमीटर	प्राईमरी स्कूल	4,00,49,856/-	40,04,985/-
6	नर्सरी स्कूल सेक्टर- ए	510 वर्गमीटर	नर्सरी स्कूल	59,37,624/-	5,93,762/-
7	नर्सरी स्कूल सेक्टर- ए	1070 वर्गमीटर	नर्सरी स्कूल	1,24,57,368/-	12,45,736/-
8	धार्मिक स्थान सेक्टर-ए	700 वर्गमीटर	धार्मिक स्थान	81,49,680/-	8,14,968/-
9	धार्मिक स्थान सेक्टर-डी	730 वर्गमीटर	धार्मिक स्थान	84,98,952/-	8,49,895/-
10	नर्सरी स्कूल सेक्टर- डी	810 वर्गमीटर	नर्सरी स्कूल	99,01,861/-	9,90,186/-
11	डिस्पेन्सरी सेक्टर-डी	1040 वर्गमीटर	डिस्पेन्सरी	1,33,49,176/-	13,34,917/-
12	प्राईमरी स्कूल सेक्टर-ई	1000 वर्गमीटर	प्राईमरी स्कूल	1,28,35,746	12,83,574

आवासीय सह व्यवसायिक

अनु. क्र.	भूखण्ड/इकाई का विवरण	भूखण्डों /इकाईयों का उपयोग	क्षेत्रफल वर्ग मीटर प्रत्येक भूखण्ड	आरक्षण की श्रेणी यदि आरक्षित हो	भूखण्ड/इकाई की आरक्षित कीमत प्रति भूखण्ड	निक्षेप रकम (धरोहर राशि)
1	2	3	4	5	6	7
1	एस.आर 70 एवं एस. आर-71 सेक्टर-ए	आवासीय सह व्यवसायिक	189 वर्गमीटर	अनु.जनजाति	69,88,842/-	6,98,884/-
2	एस.आर-66, सेक्टर-ए	आवासीय सह व्यवसायिक	169 वर्गमीटर	अनु. जाति	68,74,244/-	6,87,424/-
3	एस.आर-9, सेक्टर-डी	आवासीय सह व्यवसायिक	135वर्गमीटर	सामान्य	66,44,295/-	6,64,429/-
4	एस.आर-15 सेक्टर-डी	आवासीय सह व्यवसायिक	135 वर्गमीटर	अन्य पि. वर्ग	60,40,305/-	6,04,030/-
5	एस.आर- 51, 52, 53, 53 ए, 8, 24 एवं 30 सेक्टर-डी	आवासीय सह व्यवसायिक	135 वर्गमीटर	सामान्य	60,40,305/-	6,04,030/-
6	एस.आर-6, सेक्टर-ई	आवासीय सह व्यवसायिक	228 वर्गमीटर	सामान्य	1,35,78,084/-	13,57,808/-

भुगतान हेतु नियम एवं शर्तें निम्नानुसार होगी :-

1. भूखण्ड पर भारित सम्पत्ति कर एवं पुनर्निर्धारण शुल्क (भू-राजस्व प्रीमियम राशि) रजिस्ट्री पृथक से देय होगा।
2. भूखण्ड पर भारित रहवासी समिति शुल्क तय अनुसार रजिस्ट्री पूर्व अंतिम किश्त में पृथक से देय होगा।
3. जल प्रदाय स्ट्रीट लाईट एवं साफ-सफाई संचालन मद में 24 माह की राशि अग्रिम रूप रजिस्ट्री से पूर्व पृथक से देय होगी।
4. सम्पत्ति फ्री होल्ड पर विक्रय हेतु है।
5. जी.एस.टी. एवं अन्य लागू टैक्स शासन नियमानुसार देय होगें।
6. किश्तों का निर्धारण निम्नानुसार देय होगा-

1. आवंटन मूल्य का 50 प्रतिशत पंजीयन राशि के समायोजन सहित आवंटन आदेश जारी होने के 45 दिवस की समयावधि में जमा करना अनिवार्य होगा। 2. आवंटन मूल्य का 10 प्रतिशत सड़क कार्य पूर्ण होने पर। 3. आवंटन मूल्य का 10 प्रतिशत जल प्रदाय कार्य पूर्ण होने पर। 4. आवंटन मूल्य का 10 प्रतिशत सीवर नेटवर्क शुरू होने पर। 5. आवंटन मूल्य का 10 प्रतिशत विद्युत लाईन एवं सबस्टेशन चार्ज होने पर। 6. आवंटन मूल्य का 10 प्रतिशत विद्युत लाईन एवं सबस्टेशन चार्ज होने पर + सम्पतिकर + ब्याज राशि (अगर कोई देय है) + समिति शुल्क + पुनर्निर्धारण शुल्क (भू राजस्व प्रिमियम राशि) + अन्य कोई देय योग्य राशि अंतिम किस्त के रूप में (कार्य पूर्ण होने पर) देय होगी। 7. शेष नियम एवं शर्तें आवेदन पत्र के साथ संलग्न रहेंगे।

संपदा अधिकारी
भोपाल विकास प्राधिकरण
भोपाल

नोट :-
1. समस्त भूखण्ड फ्री होल्ड हैं
2. समस्त भूखण्ड भू-स्वामी अधिकार के अंतर्गत

सम्पत्तियों के ऑफर दिनांक 07.09.2020 को समय दोपहर 12.00 बजे खोले जावेंगे।
आवेदन पत्र मुख्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण से कार्यालयीन समय में प्राप्त किए जा सकते है।

ऑफर फार्म का मूल्य 500/-

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें-

प्रगति भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन- I, एम.पी. नगर, भोपाल 462011 (म.प्र.)
दूरभाष : 0755-2701836/37/38, 2557273 / 2557276
Email : info@bda.org.in www.bda.org.in

श्री राजेश पुष्प, सहायक यंत्री मो. 9425300295, 9399067403
श्री डी.सी. श्रीवास्तव मो. 7987337045, 8827539901, श्री अनिल उज्जैनकर मो. 9826315933

एक तीर से कई निशाने

डेमोक्रेटिक पार्टी से अमेरिकी राष्ट्रपति के उम्मीदवार जो बिडेन ने अपनी पार्टी से भारत-अमेरिका मूल की कमला हैरिस का नाम उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आगे कर एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। पहला यह कि अश्वेतों का वोट उन्हें मिलेगा, दूसरा महिला होने का लाभ भी उनके हिस्से में ही जाएगा। साथ ही उन्होंने भारत के रुख को भी अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया है। माना जा रहा है कि सब कुछ अनुकूल रहा तो अमेरिका के लोकतांत्रिक इतिहास में कमला हैरिस पहली महिला उपराष्ट्रपति बन सकती हैं।

अमेरिका में अभी तक कोई महिला न तो राष्ट्रपति बनी है और न ही उपराष्ट्रपति। ऐसा पहली बार हुआ है जब उपराष्ट्रपति के लिए किसी भारतीय-अमेरिकी महिला को टिकट मिला है। अमेरिका में इसके पहले उपराष्ट्रपति के लिए दो महिलाएं गेराल्डाइन फरेरो (1984) और सारा पालेन (2008) में इस पद के लिए चुनाव हार चुकी हैं। साल 2016 में हिलेरी क्लिंटन अमेरिका में पहली ऐसी महिला थीं जिन्हें व्हाइट हाउस जाने का अवसर मिला था, मगर वह डोनाल्ड ट्रंप से चुनाव हार गई थीं। यहां एक खास बात यह है कि अमेरिका में अभी तक कोई महिला न तो राष्ट्रपति बनी है और न ही उपराष्ट्रपति। कमला हैरिस यदि चुनाव जीतती हैं तो कुछ हद तक इस मिथक को टूटते हुए देखा जा सकेगा।

माना तो यह भी जा रहा है कि कमला हैरिस और बिडेन की जोड़ी बराक ओबामा वाला जादू वापस ला सकती है। गौरतलब है कि बराक ओबामा 2008 से 2016 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि कमला हैरिस किस हद तक अश्वेत वोटों से बिडेन को फायदा पहुंचा पाएंगी मगर नस्लभेद के पुराने जिन्न से जूझते अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में इसके प्रभाव को कमतर आंकना सही नहीं होगा। कमला हैरिस की उम्मीदवारी ट्रंप को अखर रही है, क्योंकि अश्वेत वोटों का ध्रुवीकरण अब डेमोक्रेटिक की ओर जा सकता है। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हैरानी जताते हुए कहा कि बिडेन ने भारतीय मूल की सीनेटर हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना, जबकि वह लगातार उनका अनादर करती रहीं। यहां ट्रंप ने हैरिस को अश्वेत के बजाय भारतीय मूल का कहकर अप्रत्यक्ष तौर पर एक संकुचित दृष्टिकोण देने का प्रयास किया है।

हैरिस खुद को भारतीय मूल के रूप में देखती हैं या फिर अश्वेत इस पर भी अमेरिका का मतदाता विचार मंथन करेगा। वैसे अश्वेत के रूप में भी इन्हें बाकायदा मान्यता दी जा रही है। अमेरिका के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हैरिस को अश्वेत उम्मीदवार के रूप में पेश किया जा रहा है ताकि अश्वेत आंदोलन के मौजूदा माहौल में बिडेन को जीत की ओर ले जाया जा सके। गौरतलब है कि अमेरिका में सैकड़ों वर्षों से नस्लभेद की जड़ें फैली हुई हैं।

हैरिस का उप राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के प्रति उनकी नीतियां अधिक लचीली न हों ऐसी कोई खास वजह नहीं दिखाई देती, किंतु जम्मू-कश्मीर के अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद वहां के हालात को काबू में करने के लिए पाबंदी लगाए जाने का हैरिस ने विरोध किया था। उन्होंने पाबंदियों को हटाने की मांग की थी। इसके अलावा लोकतांत्रिक मूल्यों और धार्मिक एकता को लेकर वे काफी मुखर रही हैं। ऐसे में यह कह पाना कठिन है कि उनके उपराष्ट्रपति बनने से भारत को हर्ष एवं गर्व कितना होगा। अगर कमला हैरिस और बिडेन की जोड़ी 2020 चुनाव में जीत दर्ज करती है तो कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि साल 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में हैरिस की दावेदारी मजबूत हो जाएगी। फिलहाल हैरिस ने चुनाव प्रचार में बिडेन की तुलना में अधिक उदारवादी कदम उठाए हैं चाहे वह हेल्थ केयर हो या इमीग्रेशन।

वैसे भारतीय मूल के अमेरिकी रिपब्लिकन के बजाय डेमोक्रेट की ओर झुकाव रखते हैं। बिडेन ने स्पष्ट किया है कि यदि वे चुनाव जीतते हैं तो भारतीय आईटी पेशेवर में सबसे अधिक मांग वाले एच-1 बी वीजा पर लगाई गई स्थायी रोक हटा देंगे। गौरतलब है कि ट्रंप ने इस वीजा को निलंबित कर रखा है। भारत में अमेरिकी राजदूत रह चुके रिचर्ड वर्मा के द्वारा यह पता चला है कि यदि बिडेन राष्ट्रपति बनते हैं तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट दिलाने का प्रयास करेंगे। बहरहाल कमला हैरिस में वे सारी खूबियां हैं जो चुनाव में पार्टी को फायदा पहुंचा सकती हैं। प्रगतिशील मतदाताओं पर इन तमाम योग्यताओं का असर पड़ेगा जरूर।

● **अक्स ब्यूरो**

बिडेन-हैरिस की जोड़ी कमाल

जो बिडेन ने कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाकर नीरस अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। कैलीफोर्निया की सीनेटर हैरिस एक वक्त खुद राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी में बिडेन की प्रतिद्वंद्वी रह चुकी हैं। यह निश्चित ही ऐतिहासिक पड़ाव है जहां किसी बड़ी पार्टी द्वारा उपराष्ट्रपति पद की प्रत्याशी बनाई जाने वाली कमला हैरिस पहली अश्वेत और एशियाई अमेरिकी महिला हैं। पुलिस द्वारा जॉर्ज फ्लायड की हत्या के बाद हुए राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन जब चुनावी बयार को प्रभावित करते दिख रहे थे तब डेमोक्रेट्स के लिए महत्वपूर्ण था कि वे अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय में अपनी पैठ बढ़ाएं। हैरिस के नामांकन के साथ उम्मीद है कि यह तबका बिडेन के पीछे एकजुट होगा। अश्वेत मतदाताओं की अहमियत न केवल मिशिगन, पेंसिलवेनिया और विस्कॉन्सिन जैसे कांटे की टक्कर वाले राज्यों में बढ़ेगी, बल्कि जार्जिया और फ्लोरिडा जैसे रिपब्लिकन झुकाव वाले राज्यों में भी ऐसा होने के आसार हैं। हैरिस युवा मतदाताओं से जुड़ाव में भी मददगार होंगी जिनकी आकांक्षाएं शायद 77 वर्षीय बिडेन उतने बेहतर तरीके से न व्यक्त कर पाएं।

सशक्त सहकारिता; समृद्ध मध्यप्रदेश

अपेक्स बैंक

अपेक्स बैंक

म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या.

समृद्धि आपकी, योजनाएं हमारी

- वाहन ऋण
- त्यौहार ऋण
- आवास ऋण
- चिकित्सा ऋण
- व्यक्तिगत ऋण
- परियोजना ऋण
- भ्रमण ऋण
- उपभोक्ता ऋण
- उच्च शिक्षा ऋण
- आभूषणों के तारण पर ऋण
- व्यापारियों को साख-सीमा
- अचल सम्पत्ति के बंधक पर ऋण

क्यों देखें महज सपने, आइये करें उन्हें साकार

केन्द्र/राज्य शासन/शासकीय निगम, मण्डल, बोर्ड, समस्त सहकारी बैंकों/संस्थाओं एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के नियमित कर्मचारियों हेतु उपरोक्त समस्त ऋण (आवास ऋण छोड़कर) रियायती ब्याज दर

मात्र 9.5% पर ऋण सुविधा उपलब्ध

हमारी अन्य बैंकिंग सेवायें

एनईएफटी | आईएमपीएस | मोबाईल बैंकिंग

आरटीजीएस | एटीएम | लॉकर्स सुविधा

वरिष्ठ नागरिकों को सावधि जमा पर 1% अधिक ब्याज

अपेक्स बैंक की समस्त शाखाओं में आपका हार्दिक स्वागत है।

जीवन ही अब भार मुझे

मेरा अपना इस जग में,
आज अगर प्रिय होता कोई।
मैंने प्यार किया जीवन में,
जीवन ही अब भार मुझे।
रख दूं पैर कहां अब संगिनी,
मिल जाए आधार मुझे।
दुनिया की इस दुनियादारी,
करती है लाचार मुझे।
भाव भरे उर से चल पड़ता,
मिलता क्या उपहार मुझे।
स्वप्न किसी के आज उजाड़ूं,
इसका क्या अधिकार मुझे।
मरना-जीना जीवन है,
फिर छलता क्यों संसार मुझे।
विरह विकल जब होता मन,
सेज सजाकर होता कोई।
विकल, बेबसी, लाचारी है,
बांध रहा दुख भार मुझे।
किस ओर चलूं ले नैया,
अब सारा जग मंजधार मुझे।
अपना कोई आज हितैषी,
देता अब पुचकार मुझे।
सहला देता मस्तक फिर यह,
सजा चिता अंगार मुझे।
सारा जीवन बीत रहा यों,
करते ही मनुहार मुझे।
पागल नहीं अबोध अरे,
फिर सहना क्या दुत्कार मुझे।
व्यथा विकल भर जाता मन,
पास खड़ा तब रोता कोई।
फूलों से नफरत सी लगती,
कांटों से है प्यार मुझे।
देख चुका हूं शीतलता को,
प्रिय लगता है अंगार मुझे।
दुख के शैल उमड़ते आएं,
सुख की क्या परवाह मुझे।
भीषण हाहाकार मचे जो,
आ न सकेगी आह मुझे।
नहीं हितैषी कोई जग में,
यही मिली है हार मुझे।
ढूंढ चुका हूं जी का कोना,
किंतु मिला क्या प्यार मुझे।
पग के छाले दर्द उभरते,
आंसू से भर धोता कोई।

- कालिका प्रसाद सेमवाल

घर का स्तंभ

दहलीज पर पैर रखते ही चाचाजी ऊंची आवाज में मां पर बरस पड़े।

भाभी... 'आप नहीं जानतीं, मोहल्ले वाले रजनी को लेकर क्या-क्या बातें बना रहे हैं? सीढ़ियों से नीचे उतरकर रजनी को मास्क पहनकर जाते हुए देखकर उबल पड़े।

रजनी ठहरो! कहां जा रही हो?... सुना है...चार घंटे बाद लौटकर आती हो आज इस बात का जवाब देना ही होगा।

तुम्हारे पिता मरे अभी कुछ ही महीने हुए हैं। और तुम हो कि ये सब।

चाचाजी मुझे कमाने के लिए घर से निकलना ही होगा वर्ना घर कैसे चलेगा।

आप तो जानते ही हैं 'पिता जी के मरते ही भाई की नीयत भी बदल गई मां के भोलेपन का फायदा उठाकर सारा पैसा निकाल लिया और अपने बच्चों को लेकर चला गया पलटकर हम मां-बेटी की तरफ देखा भी नहीं।

चाचाजी मैं रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्टरी में कपड़े सिलने जाती हूं।

देवर जी, मुझे बेटी पर गर्व है। इसने ने मेरे घर के स्तंभ को ढहने से बचाया है... मैं तो पुत्र मोह में सब गवां बैठी थी।

- अर्विना

बाबागिरी

नवनीत बचपन से ही बड़ा होनहार था। पहली कक्षा से ग्रेजुएशन तक की सभी कक्षाओं में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने के तुरंत बाद अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा पास कर एक आईपीएस अधिकारी बन गया।

निर्धारित प्रशिक्षण और परीवीक्षा अवधि पूरा करने के बाद पुलिस अधीक्षक के रूप में उसकी पोस्टिंग रामपुर जिले में होने के पहले ही हफ्ते गृहमंत्री जी का दौरा हुआ। मंत्री जी को उस क्षेत्र के प्रख्यात बाबा श्री संतराम जी के आश्रम उनके दर्शन के लिए जाना था।

निर्धारित तिथि को वह मंत्री जी के स्वागत के लिए पहुंच गया। जैसे ही मंत्री जी हैलीकॉप्टर से बाहर निकले, नवनीत के आश्चर्य का ठिकाना न था। उसके सैल्यूट के लिए उठे हाथ उठे ही और आंखें फटी की फटी रह गईं। मंत्री जी के रूप में उसकी यूनिवर्सिटी का वही लड़का था, जिसे यूनिवर्सिटी कैंपस में नशीले पदार्थों की बिक्री करने से कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था।

खैर, ड्यूटी तो करनी ही थी। वह मंत्री जी को ससम्मान बाबा जी आश्रम लेकर गया। मंत्री जी को जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि उनके साथ में चल रहा डीएसपी कभी उसका जूनियर छात्र रह चुका है।

आश्रम में बाबा जी के दर्शन कर वह पुनः आश्चर्यचकित रह गया। बाबा जी कोई और नहीं उसी की यूनिवर्सिटी का वह पूर्व छात्र था, जिसे एक जूनियर लड़की से छेड़खानी करने पर बाकी लड़कियों ने मिलकर लात-घूंसों से खूब खातिरदारी करने के बाद पुलिस के हवाले कर दी थी।

आश्रम में मंत्री जी और बाबा जी के बीच मौसेरे भाईयों जैसी चल रही बातचीत से ऐसा बिलकुल भी नहीं लग रहा था कि उनके संबंध बाबा जी और भक्तों जैसे हैं।

उधर आश्रम के बाहर मंत्री जी की पार्टी के कार्यकर्ता और बाबा जी के भक्तों की भीड़ उनकी जय-जयकार कर रही थी। इधर नवनीत अपनी यूनिवर्सिटी के इन दोनों होनहारों की प्रगति देख किंकर्तव्यविमूढ़ हो गया था।

- डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा

एमएस धोनी उर्फ 'माही' ने आखिरकार इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अलविदा कह दिया, मतलब ऐसे खिलाड़ी को अब हम वन-डे या टी 20 में खेलते हुए नहीं देख पाएंगे। हां क्रिकेट के अन्य फॉर्मेट जैसे आईपीएल इत्यादि में हम अभी भी कप्तान कूल को खेलते हुए देख सकते हैं।

'माही' तुम बहुत याद आओगे!

क्रिकेट हिन्दुस्तान में क्या अहमियत रखता है इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि जब क्रिकेट चलता है तो बस क्रिकेट ही चलता है, बाकी सब बंद रहता है। किसी भी खिलाड़ी के लिए लगातार क्रिकेट खेलना, वह भी हिन्दुस्तान के लिए जहां जरूरत से बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली जाती है, बहुत मुश्किल होता है। लगातार खेलते हुए फॉर्म बरकरार रखना, फिटनेस बरकरार रखना और उससे भी ज्यादा मैदान पर या उसके बाहर भी अपना टेम्परामेंट बरकरार रखना, यह बेहद कठिन होता है। और इस मामले में माही ने अपने समकालीन खिलाड़ियों से कहीं बेहतर किया, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है।

महेंद्र सिंह धोनी ने एक तरह से छोटे शहरों के टैलेंट का प्रतिनिधित्व किया और बाकी लोगों को अपने सपने के पीछे भागने का हौसला दिया। साल 2006-07 के दौर में जब इंटरनेट का आगमन हो चुका था और दुनिया तेजी से बदल रही थी। उस समय हर फील्ड में छोटे शहरों के लोगों की भूमिका बढ़ रही थी। फिल्मों में इरफान, अनुराग कश्यप, नवाजुद्दीन सिद्दीकी समेत ढेरों नए चेहरे स्थापित हो रहे थे, वहीं टाटा, बिरला जैसी स्थापित कंपनियों की भीड़ में कई नए स्टार्टअप्स अपनी जगह बनाने की जी-तोड़ कोशिश कर रहे थे। उस दौर में हर किसी की जुबान पर था कि देखो, धोनी जब मेहनत से इतना ऊंचा मुकाम हासिल कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। जिस तरह 80 के दशक में पैदा हुए हर खिलाड़ी के आदर्श सचिन थे, उसी तरह 90 के दशक में पैदा हर खिलाड़ी और जीवन में कुछ बड़ा करने की ख्वाहिशों के गुलाम हर शख्स की जुबां पर धोनी एक उदाहरण और सच के तौर पर थे।

7 जुलाई 1981 को तत्कालीन बिहार के रांची जिले में एक पंप ऑपरेटर के घर पैदा हुए महेंद्र सिंह धोनी को फुटबॉल खेलना और खासकर गोलकीपिंग बेहद पसंद था, लेकिन उनकी किस्मत में क्रिकेट खेलना था। एक दिन अचानक उन्हें स्कूल क्रिकेट टीम में विकेटकीपिंग का मौका मिला और फिर धोनी ने उसमें इतना अच्छा कर दिया कि क्रिकेट उनके जीवन का हिस्सा बन गया। सचिन तेंदुलकर को खेलते देख धोनी भी क्रिकेटर बनने का सपना देखने लगे और अपनी अथक मेहनत के साथ ही ढेरों चुनौतियों को पार करते वह आगे बढ़ते गए। धोनी के क्रिकेट जीवन का शुरुआती सफर कितना मुश्किल भरा था, ये आप उनकी बायोपिक में देख चुके हैं, लेकिन जो आपने नहीं देखा, वो है धोनी का जुनून और जज्बा। ऐसा जज्बा, जो उन्हें किसी भी परिस्थिति में हारने नहीं देता। 1999-2000 के दौरान बिहार रणजी क्रिकेट टीम और फिर 2002-03 में झारखंड क्रिकेट टीम के अभिन्न अंग के रूप में अपनी प्रतिभा साबित करने के बाद धोनी का चयन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम में होता है। साल 2004 का 23 दिसंबर, चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे मैच में डेब्यू करने वाले धोनी कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन उनकी प्रतिभा से चयनकर्ता और दर्शक दोनों वाकिफ थे, ऐसे में उन्हें मौका मिलता रहा और फिर धोनी ने ऐसा जादू चलाया कि पूरी दुनिया उनकी विकेटकीपिंग और बैटिंग की कायल हो गई। ठीक एक साल बाद यानी दिसंबर 2005 में धोनी ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में पर्दापण किया और फिर क्रिकेट के दोनों शीर्ष फॉर्मेट यानी टेस्ट और वनडे में धोनी ने अपने शानदार परफॉर्मेंस से जगह पक्की कर ली।

धोनी ने साल 2004 में डेब्यू करने के बाद लगभग हर वनडे और टेस्ट सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन किया और इसका उन्हें रिवॉर्ड भी मिला। जून 2007 में उन्हें क्रिकेट के नए और उभरते फॉर्मेट टी20 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया गया। वहीं सितंबर 2007 में धोनी को एक दिवसीय मैचों के लिए भी भारतीय टीम को लीड करने का जिम्मा दे दिया गया। धोनी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पर्दापण के महज 3 साल के अंदर वनडे और टी20 फॉर्मेट में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बन गए। अब दौर था धोनी का, जो भारतीय टीम की बेहतरी के लिए बड़े से बड़ा फैसला लेने से चूकता नहीं था। कप्तान बनने के बाद धोनी ने इंडियन टीम को यंग बनाने का फैसला किया और चयनकर्ताओं को साफ-साफ कह दिया कि वह अपनी टीम में कुछ नए चेहरे को शामिल करना चाहते हैं, जिसके लिए पुराने चेहरे को टीम से बाहर निकालना होगा। ऐसे समय में टी20 फॉर्मेट में सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले और सौरभ गांगुली जैसे खिलाड़ियों को विश्राम दिया गया। धोनी के इस फैसले की काफी आलोचना भी हुई, लेकिन जब धोनी ने रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, जोगिंदर शर्मा, दिनेश कार्तिक, इरफान पठान, आरपी सिंह, एस श्रीसंत, रॉबिन उथप्पा और युवराज सिंह जैसे यंग खिलाड़ियों के साथ टी-20 वर्ल्ड कप का मुकाबला जीत लिया तो दुनिया ने धोनी के कड़े फैसले की हकीकत जानी और लोग लोहा मान बैठे कि धोनी जो फैसला करता है, वह टीम के साथ ही देश हित में होता है।

● **आशीष नेमा**

धोनी के साहसिक फैसले के बदली फिजा

धोनी ने भारतीय टीम की पहले से स्थापित व्यवस्था को कड़ी चुनौती देते हुए महानगरों के मठाधीशों को चैलेंज किया और फिर अपनी यंग टीम के बुते ऐसा कर दिखाया कि बड़े-बड़े खिलाड़ियों को उनकी हकीकत और भविष्य में क्रिकेट के स्वरूप का अंदाजा हो गया। ऐसी स्थिति में वह खुद ही या तो संन्यास लेने लगे या चयनकर्ताओं के साथ ही धोनी के फैसले का सम्मान करने लगे। सितंबर 2007 विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के खराब प्रदर्शन के बाद जब टीम की कप्तानी राहुल द्रविड़ से महेंद्र सिंह धोनी को सौंपी गई, तभी धोनी ने फैसला कर लिया कि साल 2011 के आईसीसी वनडे विश्व कप के लिए वह ऐसी टीम बनाएंगे, जो हर मुश्किल में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है और भारतीय क्रिकेट को बुलंदियों पर ले जाने से साथ ही भारत को दोबारा विश्व कर दिला सकती है। धोनी ने इसी रणनीति के तरह एक ऐसी टीम बनाई, जिसमें छोटे शहर के स्टार्स प्लेयर थे।

पोस्ट शेयर कर कंगना ने रिया पर साधा निशाना

बोलीं- इस लंगड़ी स्क्रिप्ट का राइटर कौन है?

रिया चक्रवर्ती ने हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत मामले में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कई बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने अपने बयान में सुशांत के परिवार द्वारा लगाए गए सभी आरोपों पर चर्चा की। साथ ही 8 से 14 के बीच घर में क्या हुआ इसको लेकर भी सवाल खड़े किए।

कंगना रनौत ने सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे पर निशाना साधा, जिसका जवाब अंकिता ने तुरंत दिया। सुशांत केस में लगातार सुर्खियों में छाई हुईं एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अंकिता के जवाब को रीट्वीट किया और रिया चक्रवर्ती का बिना नाम लिए फिर बॉलीवुड पर निशाना साधा।

रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू के बाद कंगना रनौत ने कई ट्वीट किए। इस दौरान उन्होंने रिया द्वारा सुशांत की मानसिक स्थिति पर अंकिता लोखंडे के बयान पर एक्ट्रेस (रिया) को घेरने की कोशिश की। उन्होंने ट्वीट कर कहा- तथ्य #Sushant का रिया के साथ डेटिंग से पहले मानसिक बीमारी का कोई इतिहास नहीं था, यह मानसिक बीमारी की साजिश यूरोप ट्रिप पर एक गॉथ होटल से शुरू हुई, जिसे एयर सिकनेस के साथ ट्विस्ट किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इस लंगड़ी स्क्रिप्ट का राइटर कौन है?

कंगना रनौत ने और भी ट्वीट किए। उन्होंने लिखा- रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू से सिर्फ दो बातें निकलीं, पहली उसने कहा कि मूवी माफिया ने सुशांत को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए उन्हें परेशान किया और सुनियोजित ढंग से उनके खिलाफ कैंपेन चलाए। दूसरी, उसने ये नहीं कहा कि उसके और महेश भट्ट जैसे गिद्धों ने सुशांत को दोबारा मारा।

कमाल खान ने रिया पर कसा तंज... कहा-अल्लाह आपकी जैसी गर्लफ्रेंड किसी को न दे

सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कई एजेंसियों की जांच का सामना कर रही मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती ने हाल ही में मीडिया के सामने आकर अपनी चुप्पी तोड़ी। मुंबई पुलिस, ईडी और अब सीबीआई जांच टीम सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। सुशांत के परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों पर रिया ने हाल ही में अपना पक्ष रखा। रिया ने इस दौरान कहा कि वह सुशांत से बेहद प्यार करती थीं और यही शायद उनसे गलती हुई है। रिया के इस बयान पर एक्टर कमाल राशिद खान ने ट्वीट कर रिया पर तंज कसा है। एक्टर कमाल राशिद खान ने ट्वीट कर कहा- रिया चक्रवर्ती ने कहा- मेरा क्राइम बस इतना है कि मैंने सुशांत से बहुत प्यार किया। मैडम, अल्लाह आपकी जैसी प्यार करने वाली गर्लफ्रेंड किसी को न दे।

मौनी रॉय ने खुले आसमान के नीचे कराया फोटोशूट, व्हाइट आउटफिट में दिखा बोल्ड अंदाज

अपने स्टाइल को लेकर काफी चर्चा में रहने वाली एक्ट्रेस मौनी रॉय ने कुछ तस्वीरों अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। इस तस्वीरों में वह खुले आसमान के नीचे बोल्ड अंदाज में दिखाई दे रही हैं। बॉलीवुड और टीवी एक्ट्रेस मौनी रॉय सोशल मीडिया पर वह काफी एक्टिव हैं। सोशल मीडिया के जरिए मौनी अपने फैंस से लगातार जुड़ी हुई हैं और उन्हें अपनी डेली लाइफ को लेकर अपडेट भी देती रहती हैं।

हाल ही में उन्होंने एक फोटोशूट कराया है, जिसकी वजह से मौनी सुर्खियों में बनी हुई हैं। अपने स्टाइल को लेकर काफी चर्चा में रहने वाली एक्ट्रेस मौनी रॉय ने कुछ तस्वीरों अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। इस तस्वीरों में वह खुले आसमान के नीचे बोल्ड अंदाज में दिखाई दे रही हैं, जिसको लोग काफी पसंद कर रहे हैं। तस्वीरों में मौनी एक गार्डन में नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों में वह व्हाइट आउटफिट में नजर आ रही हैं। तस्वीरों में उनके स्टाइल और बोल्डनेस की लोग तारीफ कर रहे हैं।

मुहल्ले का कोई नीच, दुराचारी, शराबी, वैश्यागामी और कुत्ते के समान कुतृत्व का धनी व्यक्ति यदि मर जाए और लोग उसके यहां सांत्वना देने जाएं तो उसकी प्रशंसा में कसीदे पढ़ते हैं कि भला आदमी था! इनके जाने का दुख है! जबकि मन में यही चल रहा होता है कि उक्त व्यक्ति और पहले क्यों नहीं मर गया!

मक्खनबाजी और बेईमानी कम्पल्सरी है भाई...!

जी हां! बिलकुल सही पढ़ा है आपने! खुद के द्वारा किए गए एक शोध से यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं कि यह दुनिया सिर्फ और सिर्फ मक्खनबाजी और बेईमानी की बुनियाद पर टिकी हुई है! दुनिया में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति में मक्खनबाजी और बेईमानी का गुण विद्यमान है चाहे वह नर हो या नारी!

मैं तो यह बात भी दावे के साथ कह रहा हूं कि यदि मक्खनबाजी और बेईमानी का रास्ता छोड़ दिया जाए तो दुनिया जैसी चल रही है वैसे चल ही नहीं पाएगी! मक्खनबाजी और बेईमानी की राह छोड़ देने से सब तहस-नहस हो जाएगा! रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे! मक्खनबाजी और बेईमानी छोड़ देने से आपसी प्रेम और भाईचारा खत्म हो जाएगा! आपने कभी सोचा है कि एक औरत अपने पति के बारे में जो सोचती है वह कह ही नहीं सकती या एक पति अपने पत्नी के बारे में जो सोचता है वह कहता ही नहीं जीवन पर्यन्त क्यों? क्योंकि यदि दोनों एक-दूसरे को वह कह देंगे जो सच्चाई है तो यकीन मानिए दोनों के मध्य लाठीचार्ज की नौबत आ सकती है इसलिए दोनों मक्खनबाजी और बेईमानी का सहारा लेकर रिश्ते को लोकलाज के डर से ढो रहे होते हैं!

नौकर अपने मालिक से और मालिक अपने नौकर से एक-दूसरे से वह कह ही नहीं सकते जो एक-दूसरे के बारे में सोचते हैं! मेरे जीवन में आपके जीवन में हजारों ऐसे लोग या दोस्त होंगे जिनको देखते ही लगता है जूता लेकर तब तक पीटो जब तक थक ना जाओ! लेकिन हम ऐसा चाहकर भी नहीं करते बेईमानी का सहारा लेते हैं मक्खनबाजी का सहारा लेते हैं और जूता मारने के बजाय हम उनको मालाएं पहनाते हैं उस व्यक्ति से या दोस्त से अपने दिखावे के रिश्ते को जिंदा रखने के लिए!

ठीक यही स्थित दो युगल प्रेमी जोड़ों के मध्य होती है। कुछ समयोपरांत दोनों का मन एक-दूसरे से प्रेम करके ऊब चुका होता है लेकिन दोनों ढो रहे होते हैं एक-दूसरे को, गाली देने का मन होता है लेकिन मक्खनबाजी और बेईमानी का सहारा लेते हैं और ताली देते हैं! मुहल्ले का कोई नीच, दुराचारी, शराबी, वैश्यागामी और कुत्ते के समान कुतृत्व का धनी व्यक्ति यदि मर जाए और लोग उसके यहां सांत्वना देने जाएं तो उसकी प्रशंसा में कसीदे पढ़ते हैं कि भला आदमी था! इनके जाने का दुख है! जबकि मन में यही चल रहा होता है कि उक्त व्यक्ति और पहले क्यों नहीं मर गया! जीवन में ज्यादा समय के लिए तो नहीं महज चौबीस घंटे के लिए ही आप या मैं मक्खनबाजी और बेईमानी का रास्ता छोड़कर देंखे उस चौबीस घंटे में ही हम ना जाने जीवन भर के लिए कितने झमेले खड़े कर लेंगे! कुल मिलाकर मानव जीवन में व्यवहार, शिष्टाचार, सदाचार में मक्खनबाजी और बेईमानी का पूर्णत: समावेश हो चुका है! अब तो यह लगता है कि कोई व्यक्ति किसी के बहकावे में आकर ईमानदारी और सच्चाई की राह पर ना चलने लगे वरना पग-पग पर अनिष्ट होने की आशंका बनी रहेगी! मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि मक्खनबाजी और बेईमानी कम्पल्सरी है भाई!

मेरे एक मित्र हैं वे हमेशा सब की तारीफ करते हैं। एक बार मैंने उनसे कहा- कुछ सामान लेना है, तो वे बोले- चलो और एक ऐसे दुकानदार के पास ले गए जो घटिया माल देता था और पैसे भी ज्यादा लेता था लेकिन उन्होंने उसकी ऐसी तारीफ की देखो ये आदमीं इनसे मिलो ये बहुत ही सज्जन और ईमानदार हैं इनकी दुकान पर हर माल बढ़िया और बाजार से सस्ता और उचित दाम पर मिलेगा मैं तो हर माल इन्हीं भाई साहब से लेता हूं।

इतनी प्रशंसा सुनने के बाद मजाल है जो वह गलत सामान देता और कीमत भी वाजिब ऊपर से उसने गन्ने का रस भी पिलाया।

आगे से आप किसी की निंदा या बुराई ना करें बल्कि ये कहें कि वह आपकी बहुत प्रशंसा कर रहा था इससे समाज में आपकी और आपके शहर की भी इज्जत बढ़ेगी।

आज़मा कर देखें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।

तो फिर मक्खनबाजी और बेईमानी से डर कैसा? मैं तो कहता हूं कि शिक्षा नीति और पाठ्यक्रमों में मक्खनबाजी और बेईमानी को शामिल कर दिया जाए! जिससे आगामी पीढ़ी मक्खनबाजी और बेईमानी में पूर्णत: सिद्धहस्त और आत्मनिर्भर हो! समूचे विश्व के लोगों की एक ही धारणा होनी चाहिए कि-

जमकर खाए और जिए चलो
मक्खनबाजी, बेईमानी किए चलो!

● **आशीष तिवारी निर्मल**

मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश सरकार की पहल
नये हितग्राहियों को मिलेगी
खाद्यान्न सुरक्षा

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

25 श्रेणियों के सभी पात्र परिवारों को जारी होगी राशन की पात्रता पर्ची
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जोड़े जायेंगे

37 लाख नये हितग्राही

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

- 15 अगस्त तक 21 लाख तथा 31 अगस्त तक शेष 16 लाख हितग्राहियों को जारी की जायेंगी पात्रता पर्ची।
- सितम्बर माह से हितग्राही परिवारों को आरंभ हो जायेगा खाद्यान्न वितरण।
- उक्त हितग्राहियों को भी 5 किलो प्रति सदस्य 1 रुपये प्रति किलो की दर से नियमित राशन एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति सदस्य निर्धारित मात्रा में नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा।

M राशन मित्र

- राशन की दुकान पर जाकर अथवा "एम-राशन मित्र" एप पर हितग्राही को स्वयं आधार नम्बर दर्ज करने की सुविधा।
- परिवार के सभी सदस्यों के आधार नम्बर दर्ज होने पर पूरे देश में कहीं भी राशन प्राप्त करने की पात्रता एवं सुविधा।

सबके लिए खाद्यान्न सुरक्षा
मध्यप्रदेश सरकार की प्राथमिकता

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश

D-16049/20

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

बेहतर क्वालिटी अधिक पैदावार का आधार

श्रीराम

सिंगल सुपरफॉस्फेट

16% P_2O_3 (W.S.)

मध्यभारत फास्फेट प्रायवेट लिमिटेड

ऑफिस : ई-7/80, अरेरा कॉलोनी, 12 नं. बस स्टॉप के पास, भोपाल (म.प्र.)
फोन : 0755-2420563ए 4240551, फैक्स : 0755-2676361
यूनिट- 1, दिवानगंज जिला रायसेन (म.प्र.)
यूनिट- 2, 176, ए.के.व्ही.एन. एण्डस्ट्रीज, मेघ नगर, जिला-झाबुआ (म.प्र.)